(*St.*) (*M*)

occurring in the two statements made by the hon. Minister for Food and Agriculture in Lok Sabha on 14th November, 1967.

In answer to Unstarred Question No. 180 on 14th November, 1967, the hon. Minister has stated that a quantity of about 37,500 tonnes of rice has been arranged from imports to be supplied to Kerala State in the month of November.

On the same day, the same hon. Minister has answered a Calling-attention notice on the supply of rice to Kerala and some other States. I quote the following sentence from that statement :

> "In November, about 25,000 tonnes of rice will be provided from imports".

The difference between the two statements is obvious. The difference in quantity is 12,500 tonnes.

I request that the hon Minister is asked to explain how he will square up the two statements. Let him make a firm statement as to the quantity of rice that will be supplied to Kerala in November. We are already in December, this is about November.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE) : The information given in the Parliament about quantity of foodgrains likely to arrive in a particular State from abroad during a particular month is always based on the latest information available about the loading, sailing and movement of the ships and the quantity that is expected to be discharged out of each ship at that particular port. When the reply to the Unstarred Question No. 180 had been framed, the latest information indicated that there was every likelihood of 37,500 tonnes of rice reaching Kerala port from abroad during the month of November. By the time the statement was made on the Calling Attention Notice, it became clear that a ship carrying 10,000 tonnes of rice that was expected to reach Cochin by the end of November may get a little delayed and may actually arrive in India at the beginning of December. According to the information available then, it also became clear that another ship which was to arrive in Madras before the middle of November and from which a large quantity of rice was to go to Kerala might get delayed by 3-4 days. For this reason the quantity of rice taken to be moved to Kerala ex. this ship had to be reduced by 2,500 tonnes. Even the figure of 25,000 tonnes mentioned in the Calling Attention Notice statement cannot be considered as final. The actual quantity that reached Kerala during November will be known only when the accounts of the quantities unloaded and moved against the ships are finalized. According to the latest information, the quantity of rice delivered to Kerala during November both from imports and internal sources was 30,600 tonnes. Attempts are always made to give the latest information available at the moment in the Parliament.

12·05 hrs.

MOTION *Re* : FOOD SITUATION IN THE COUNTRY

MR. SPEAKER : The House will now take up further consideration of the Motion regarding Food Situation in the country.

Mr. Ram Charan, to continue his speech.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : How much of time is still left ?

MR. SPEAKER : 3 hours and 45 minutes more.

श्री राम चरण (खुर्जा) : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने आज़ादी मिलने के बाद तीन पंचवर्षीय योजनायें गुज़ार दीं। यह सभी जानते हैं कि हमारे देश की 80 फीसदी आबादी देहात में रहती है और इनका जीवन किसान से सम्बन्धित है, लेकिन आज तक इस सरकार ने तीन पंचवर्षीय योजनाओं के अन्दर इस काश्तकारी के काम के डवेलपमेन्ट के लिये कितना पैसा खर्च किया ? इन तीन पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार ने 1270 करोड़ रुपया खर्च किया, इस रकम में से यदि औसतन लगाया जाय—एक-तिहाई हिस्सा यानी 400 करोड़ रुपया सरकार ने 40 करोड़ आदमियों के लिये खर्च किया— इस से साफ़ जाहिर है कि तीन पंच वर्षीय योजनाओं के अन्दर एक आदमी पर 10 रु० खर्च किये

[श्री राम चरण]

गये। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि देहात की समस्या कैसे हल हो सकती है।

इन तीन पंचवर्षीय योजनाओं में इस सरकार ने 2,821 करोड़ रु० का खाद्य बाहर से मंगाया —इससे अन्दाजा होता है कि इस सरकार ने हमारी जितनी आमदनी थी, उस से न जाने कितने गुना खाद्य खरीदने के लिये, फूड परचेज पर खर्च किया। जितना पैसा सरकार ने इन खाद्यान्नों के इम्पोर्ट पर खर्च किया, यदि इस पैसे से किसानों को सुविधायें दी जातीं, तो मुमकिन है कि खाद्य समस्या हमारे देश में ही किसी हद तक हल हो जाती।

इस के अलावा इन तीन पंचवर्षीय योजनाओं के अन्दर 9.3 मिलियन एकड़ जमीन को रिक्लेम किया गया है, लेकिन 10 मिलियन जरखेज जमीन के ऊपर कालोनीज सैट हो गई हैं, प्रोजेक्ट बन गये हैं—इस तरह से यह रिक्लेम करना और न करना बराबर हो गया। यही कारण है कि हमारे देश की फूड प्राबलम दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है और सरकार इस की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। इसकी वजह क्या है? आज तक इस समस्या को सरकार ने नैशनल प्राबलम के रूप में नहीं माना। आपको इस खाद्य समस्या को वार फुटिंग पर हल करना चाहिये था लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इंडस्ट्रियल डिवेलेपमेंट पर आपने बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है और किसान की बहबूदी के लिए आपने कुछ नहीं किया है। मैं बता ही चुका हूं कि पिछले तीन प्लांज में आपने एक किसान पर सिर्फ दस रुपये खर्च किये हैं। किसान ही हैं जो कि फूड प्राबलैम को हल कर सकते हैं। लेकिन उनके साथ इस सरकार का व्यवहार गद्दारी का रहा है। पूंजीपति तबके को ही इसने सब से ज्यादा लिफ्ट दी है। जिसके पास पहले एक साइकिल हुआ करती थी उस पूंजीपति के पास आज तीन तीन कारें हो गई हैं। पूंजीपति तबके से आपको रिश्वत मिलती है। लेकिन किसान आपको कोई रिश्वत नहीं देता है और न ही आपको उससे रिश्वत मिलने की कोई उम्मीद है। आपको यह पता था कि अगर किसान की प्रगति होती, उसको आगे बढ़ाया जाता, उसकी खेती का डिवेलेपमेंट होता तो वह आपकी ही जड़ को खोदता। इंडस्ट्रियल डिवेलेपमेंट अगर होती है, इंडस्ट्रियलिस्ट्स को अगर आगे बढ़ाया जाता है तो सरकार को उनसे रिश्वत मिलती और इलैक्शन के लिए उसको पैसा मिलता जो कि मिलता रहा है इस वास्ते कांग्रेस सरकार ने किसान की कोई परवाह नहीं की। इसी का यह नतीजा है कि आप विदेशों से खाद्यान्नों की भीख मांगने पर मजबूर होते रहे हैं। वास्तव में अगर आप चाहते हैं कि खाद्य की समस्या हल हो तो सब से पहले आपको लैंड रिफार्म्स पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिये था। लैंड पर स्वामित्व की जो पहले से प्रथा चली आ रही है वही भी चालू है और लैंड रिफार्म्स को लागू नहीं किया गया है। खेती उसकी होनी चाहिये जोकि खेती स्वयं करता है। जो जोतने वाला होता है, जो मजदूर होता है, जो हलवाहा होता है उसको सिर्फ एक या डेढ़ रुपया मजदूरी का इस महंगाई के जमाने में मिलता है। लेकिन जो जमींदार होता है, जो जमीन का मालिक होता है वह पूरी मेहनत नहीं करता है। वह उत्पादन ज्यादा करने में कोई रुचि नहीं रखता है। इस वास्ते जमीन उसकी होनी चाहिये जो जमीन जोतता है। लैंड शुड बिलांग टू दी टिल्लर। अगर इस पालिसी को आपने कार्यान्वित कर दिया होता तो जो फूड प्राबलैम है यह हल हो गया होता।

जहां तक लैंड पर सीलिंग लगाने का सम्बन्ध है, बहुत सी स्टेट्स में आज तक भी इसको नहीं किया गया है। एक आदमी के पास चार सौ एकड़ जमीन होती है तो दूसरे के पास पांच एकड़ ही होती है। जिसके पास पांच एकड़ जमीन है वह बेचारा मेहनत करके

उत्पादन को दुगुना या तिगुना करता है। लेकिन चार सौ एकड़ वाला उत्पादन भी पूरा नहीं कर पाता है। इसका कारण यह है कि वह खुद काम नहीं करता है, दूसरों से काम करवाता है। इस वास्ते मैं कहूंगा कि लैंड सीलिंग लगाने के बाद जो लैंड बचे वह भूमिहीन जो किसान हैं उनको दी जानी चाहिये ताकि फूड प्राबलैम हल हों।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिनके पास थोड़ी-थोड़ी जमीनें हैं उनकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये, उनको आपको फाइनेंशल हैल्प देनी चाहिये, इरिगेशन फैसिलिटीज उनको देनी चाहिये और लोंज वगैरह का आपको उनके लिए प्रबन्ध करना चाहिये, उनको लोंज देने चाहियें।

लैंड रिफार्म्स के बाद दूसरा नम्बर पानी का आता है। पानी सब से जरूरी चीज है। अगर किसान को पानी मिल जाए तो वह पैदावार बढ़ा कर आपको दे सकता है। हमारे देश में साल में तीन महीने ही बारिश होती है और कई बार तो वह भी नहीं होती है। नौ महीने कुदरत पर किसान को आश्रित रहना पड़ता है। अगर पानी ठीक मात्रा में और समय पर बरस गया तब तो उसकी खेती अच्छी हो गई और अगर नहीं बरसा तो वह सूख जाती है और अगर ज्यादा बरस जाता है तो भी उसकी खेती बरबाद हो जाती है। जितना पैसा खाद्यान्नों का इम्पोर्ट करने में खर्च करते हैं और आपने आज तक किया है अगर वही पैसा आपने किसानों पर खर्च किया होता, किसान के लिए पानी का प्रबन्ध करने में खर्च किया होता तो यह जो आपको अनाज बाहर से मंगाना पड़ता है, यह न मंगाना पड़ता अगर इस पैसे के आपने पम्पिंग सैट लगा दिये होते, या ट्यूबवैल लगा दिये होते तो आपकी खाद्य समस्या हल हो गई होती और हमेशा के लिए हल हो गई होती। जो आपने प्लानिंग कमीशन बिठा रखा है और जो इस कमीशन में आफसर्स बिठा रखे हैं, उनको जो आप तन्ख्वाहें देते हैं, एयर कंडिशंड कमरों का प्रबन्ध करते हैं, उन पर पैसा खर्च करते हैं, अगर यही पैसा आपने किसानों के ऊपर खर्च किया होता, उनके लिए ट्यूबवल और पम्पिंग सैट लगाने पर खर्च किया होता तो यह फूड प्राब्लैम आपकी साल्व हो गई होती। अब भी मैं कहता हूं कि अगर आप किसान की वहबूदी चाहते हैं, फूड प्राब्लैम को हल करना चाहते हैं तो आपको चाहिये कि किसान के खेत पर आप ट्यूबवैल लगा दें। अगर बिजली मुहैया नहीं की जाती है तो पम्पिंग सैट आप फ्री लगा दीजिये या फिर सस्ते लगा कर उनको आप दे दें। जो-जो कारखाने इनको बनाते हैं उनसे आप कहें कि वे सस्ते पम्पिंग सैट मैनुफैक्चर करें और सरकार उनको उनसे खरीद कर किसानों को सप्लाई करे। किसान इस—काबिल नहीं हैं कि वे ट्यूबवैल खुद लगा सकें या पम्पिंग सैट खुद लगा सकें। गवर्नमेंट स्वयं अपने पैसे से उनके खेतों में ट्यूबवैल लगा कर दें, पम्पिंग सैट लगा कर दे और जो पैसा खर्च होता है उसको आसान किश्तों में उनसे वह रिकवर करे। इस तरह से यह जो खाद्य समस्या है उसको हल करने में सहायता मिल सकती है।

पानी के बाद दूसरे नम्बर का स्थान खाद का होता है। पानी अगर मिलता है तो खाद काम करेगी, अगर पानी नहीं मिलता है तो खाद भी बेकार हो जाएगी। चाहे जितना आप फर्टिलाइजर दे दें, जब तक पानी नहीं देते हैं, तब तक खाद से काम नहीं चल सकता है। पानी के बाद ही खाद का नम्बर आता है। मैं चाहता हूं कि किसान की जरूरत का खाद उसको मिल जाना चाहिये और आसानी से मिल जाना चाहिये।

तीसरी किसान की जरूरत उन्नत बीज की है। हमारी सरकार पिछली तीन योजनाओं में इतना भी नहीं कर सकी है कि वह किसान को एक-एक या दो-दो किलो अच्छी किस्म का

[श्री राम चरण]

बीज ही दे सके ताकि वह अच्छा गेहूं पैदा करके आपको दे सके।

अगर आप खाद्य समस्या को हल करना चाहते हैं तो जितने भी अनप्रोडक्टिव खर्चे हैं इस सब को खत्म करके एग्रिकल्चर की तरफ आपको इन फंड्स को डाइवर्ट करना होगा। अगर आपने इन कामों को नहीं किया तो आप तो कहते हैं कि 1971 तक आप खाद्यान्नों के मामले में आत्म-निर्भर हो जायेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि 1981 भी गुजर जाएगा लेकिन आप आत्म-निर्भर नहीं हो सकेंगे। यह कांग्रेस सरकार फूड प्राबलैम को हल नहीं कर सकेगी। आप याद रखिये कि किसान पूंजीपति तबके से नहीं है, वह मजदूर तबके से है। वह आपको रिश्वत नहीं दे सकता है, इलैक्शन के लिये आपको फंड्स नहीं दे सकता है जिस तरह से पूंजीपति वर्ग देता है। किसान होशियार हो गया है। वह आपको वोट नहीं देगा जिस तरह से अब उसने वोट नहीं दिया है। इस वास्ते अगर आप देश का हित चाहते हैं तो यही रास्ता आपके सामने है कि किसान को पानी सस्ता और मुफ्त दें, किसान की आर्थिक स्थिति को अच्छा करें, उसको फर्टिलाइजर दें, अच्छी किस्म का बीज दें।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जमीन रिक्लेम करके आप भूमिहीन हरिजन को उस जमीन को दें। हरिजनों के अन्दर भी दो तीन तबके हैं। एक तबका वह है जो जमीन का काम नहीं करता है। दूसरा तबका हरिजनों का वह है जो किसानी का काम करता है और गांवों में रहता है। ये वे लोग हैं जो कि मजदूरी करते हैं और उनको आठ आने या बारह आने मिलते हैं। मैं कहूंगा कि जहां कहीं भी जमीन रिक्लेम हो वह इन हरिजनों को मिलनी चाहिये जो कि गांवों में काम करते हैं और जिनको आठ आने या बारह आने मजदूरी के मिलते हैं, जो कि किसानी का काम करते हैं। उन हरिजनों को नहीं मिलनी चाहिये जो कि किसान के काम से सम्बन्धित नहीं है।

आप बड़ी-बड़ी प्राजैक्ट्स बना रहे हैं। मुझे पता चला है कि बहुत ज्यादा भूमि जो कि बंजर पड़ी हुई है उसको आप रिक्लेम करने जा रहे हैं। मेरा सुझाव है कि इस भूमि को कोओप्रेटिव बेसिस पर भूमिहीन हरिजनों को या और जो लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं हैं, उनको दे देनी चाहिये। आप किसी भी हालत में उस भूमि को-बड़े बड़े पूंजीपतियों को न दें, उनको न दें जिनका इंडस्ट्री में भी हाथ है, बिजिनेस में भी हाथ है, या इस तरह के जो दूसरे काम करते हैं उनमें हाथ है। अगर वे किसानों की तरह काम करना शुरू कर दें तो भी उनको नहीं मिलनी चाहिये। उनको आपको जमीन देनी होगी जो कि जमीन में हल चलाते हैं। उसकी जमीन नहीं होनी चाहिये जो नौकरी करते हैं या बिजिनेस चलाते हैं। इस तरह के जो लोग हैं उनके हाथ से जमीन को छीन लिया जाना चाहिये। यह बहुत जरूरी है अगर आप फूड प्राबलैम को हल करना चाहते हैं।

मैं आपको वार्न करना चाहता हूं कि अगर आपने लैंड रिफार्म नहीं किया तो मुमकिन है कि देश में सिविल वार हो जाए। खेती में काम करने वाले किसान और मजदूर लोग हैं। उनके साथ आज तक जुल्म होता आया है। इस चीज को हमने पिछली तीन योजनाओं में देख लिया है।

चीनी को आप लें। मेरे जिले के अन्दर किसान गन्ना पैदा करता है लेकिन अगर उसको एक छटांक चीनी की दवाई के लिए जरूरत पड़ती है तो उसको एक छटांक चीनी भी नहीं मिलती है। वह परेशान फिरता रहता है लेकिन उसके चीनी के दर्शन नहीं होते हैं। गन्ने की कीमत भी उसको ठीक नहीं मिलती है। इस सरकार ने उसको आज तक लूटा है। यही कारण है कि मिलें बन्द हो रही हैं। किसान को होश आ गया

है। जब उसको पता चल गया कि इतनी कम कीमत पर गन्ना देने के बाद भी, ढाई रुपये के भाव पर गन्ना देने के बाद भी उसको एक छटांक चीनी दवा तक के लिए नहीं मिलती है तो उसने कहा कि वह पंद्रह सोलह रुपये से कम में गन्ना नहीं देगा, गुड़ बना कर वह बाजार में बेचेगा। इस वास्ते ये सब जो चीजें हैं इनकी ओर आपका ध्यान जाना चाहिये। किसान का मसला अगर आपको हल करना है तो इसको वार फुटिंग पर आपको हल करना होगा, इसको नैशनल प्राबलेम मान कर आपको चलना होगा, टैक्कल करना होगा। मिनिस्टर साहब भाषण दे कर चले जायें, इससे काम नहीं चलेगा। इस तरह से फूड प्राबलैम साल्व नहीं हो सकेगा। प्लानिंग कमिशन में बैठे हुए अफसर इस समस्या को हल नहीं कर सकेंगे, जो कर्मचारी वहां बैठे हुए हैं वे हल नहीं करेंगे, अधिकारी हल नहीं करेंगे। हल करेंगे तो किसान ही हल करेंगे। एग्रिक्लचर डिपार्टमेंट में कई स्कीमें हैं जिन पर व्यर्थ में पैसा खर्च किया जा रहा है, जो कि बोगस स्कीमें हैं। जैसे सैंट्रल काउंसिल फार गोसंवर्द्धन है, हाइड फ्लैइंग स्कीम है, इस तरह की दसियों स्कीमें हैं जिन में मुफ्त में पैसा बहाया जा रहा है। इन स्कीमों को आप बन्द कर दें। दूसरी बात यह है कि एग्रिकलचर को अगर आपको डिवलेप करना है तो जो एग्रिकलचर अफसर बने वह किसान का बेटा हो, एग्रिकलचर डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वे किसानों के बेटे हों, ऐसे लोग हों जिनको पता हो कि गेहूं कैसे उगता है, जिन को पता हो कि गेहूं का पेड़ कितना लम्बा होता है, धान कैसे पैदा होता है। आज ऐसे-ऐसे लोग एग्रिकलचर डिपार्टमेंट के अधिकारी बने बैठे हैं जिन को इन सब के बारे में कुछ पता नहीं होता है, एग्रिकलचर डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट बने बैठे हैं जिन को एग्रिकलचर के बारे में कुछ पता नहीं होता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि एग्रिकलचर डिपार्टमेंट में जितने भी अधिकारी भरती किये जायें वे किसानों के बेटे हों, ऐसे लोग हों जिन को पता हो कि जमीन कैसी है और उस में क्या पैदा हो सकता है।

12.18 hrs.

MR. SPEAKER : We shall continue this discussion on the food situation till 5 P.M. to day; that means, we shall have this debate for another 4 hours or 4½ hours. The hon. Minister may reply tomorrow so that a few more Members will be able to take part in the debate. We shall conclude the discussion by 5 P.M. today; and only the reply of the hon. Minister will be given tomorrow.

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : मैं जगजीवन राम जी से कहना चाहता हूं कि खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत जो कुछ भी होता है वह कृषक खुद करता है। यह जरूर है कि सरकार की तरफ से जो कुछ इमदाद मिलती है या मिलने को होती है उसको लेने के लिए कृषक दौड़ते-दौड़ते मर जाता है।

दूसरी बात यह है कि अभी हाल में नैशनल डिवेलेपमेंट काउंसिल की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में श्री गाडगिल ने कहा कि हमारे यहां पांच से दस एकड़ तक की सिंचाई की जमीन में इतनी पैदावार होती है कि किसान के पास सरप्लस हो जाता है और इस लिए उस पर टैक्स लगाना चाहिए। मेरे मित्र, श्री कमलनाथ तिवारी, इस समय सदन में नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि वह प्रधान मंत्री, कैबिनेट के मिनिस्टरों और श्री गाडगिल को दस-दस एकड़ सिंचाई की जमीन देंगे। ये सब लोग उस जमीन पर खेती करें, उसकी पैदावार से अपने बाल-बच्चों की परिवरिश करें और प्लानिंग कमीशन जो टैक्स लेना चाहता है, वह भी दें। मेरा परामर्श है कि मिनिस्टर की हैसियत से इन लोगों को जो सहूलियतें मिली हुई ह, उनको वे छोड़ दें, उस जमीन की पैदावार से अपने बाल-बच्चों को खिलायें, उन को सेंट जेवियर और दूसरे पब्लिक स्कूलों में पढ़ायें और सरकार को टैक्स भी दें।

[श्री विभूति मिश्र]

श्री गाडगिल के प्रति मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है। मैं उन को बड़ा योग्य व्यक्ति समझता हूं। लेकिन जब से मैं ने उन का यह बयान पढ़ा है, मुझे आश्चर्य होता है कि इतने बड़े इकानोमिस्ट इतने अव्यावहारिक कैसे हो गये ह । वह कहते हैं कि पांच से दस एक तक की सिंचाई की ज़मीन में इतनी पैदावार होती है कि उस के मालिक से इनकम टैक्स लेने की ज़रूरत है।

12.21 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं खेतिहर हूं। मैं जानता हूं कि सूखे और दाही के मारे किसान परेशान है। डा० वी० के० आर० वी० राव ने बंगलौर में ठीक ही कहा है कि यदि बारिश ठीक होती है, तो नदियों में भी पानी होता है और किसान को सिंचाई का पानी मिलता है, लेकिन अगर बारिश ठीक नहीं होती है, तो नदियों में भी पानी नहीं होता है और किसानों को भी सिंचाई के लिए पानी ठीक से नहीं मिलता है। हमारे देश में खेती का सारा कारोबार भगवान की मर्जी पर निर्भर है, आस्मान की मर्जी पर या बारिश पर निर्भर है। अगर बारिश न भी हो, तो सिंचाई वाली ज़मीन पर पचास फ़ीसदी पैदावार हो जाती है।

लेकिन सवाल यह है कि हमारी सरकार क्या करती है। मैं देखता हूं कि इस हाउस में हमेशा फूड पर डीबेट होती है, लेकिन एग्रीकल्चर पर कभी डीबेट नहीं होता है, जिससे फूड की पैदावार होती है। इन दोनों विषयों पर अलग-अलग डीबेट होनी चाहिये। जिस प्रकार श्री मोरारजी देसाई फ़िनांस मिनिस्टर हैं और नोटों के मालिक हैं, उसी तरह फूड फ़िनांस के लिए एक अलग मिनिस्टर होना चाहिए, जो फूड के बंटवारे की व्यवस्था करे। एग्रीकलचर के लिए एक अलग मिनिस्टर होना चाहिए।

जब तक एग्रीकल्चर के ज़रिये पैदावार नहीं होगी, तब तक फूड और गल्ला कहां से आयेगा? इस लिये आज आवश्यकता इस बात की है कि एग्रीकल्चर की पैदावार को बढ़ाने के लिए किसानों को मदद दी जाये। उस को सस्ते दर पर कर्जा दिया जाना चाहिए। आज कहा जाता है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिए। मैं ने माना कि नहीं होना चाहिए, लेकिन किसानों को को-आपरेटिव सोसायटीज से कितना पैसा दिया जाता है? सारे हिन्दुस्तान में सिर्फ़ दो या तीन अरब रुपया किसानों को दिया जाता है। को-आपरेटिव सोसायटीज से रुपया लेने में किसानों की जो ज़िल्लत होती है, उसको वही जानते हैं। जहां तक बिहार का सम्बन्ध है, वहां पर किसान को सोसायटी में दस रुपया दे कर एक शेयर लेना पड़ता है। एक शेयर पर उस को सौ रुपया कर्जा मिलेगा। जब किसान कर्ज के लिए सोसाइटी के सेक्रेटरी के पास जाता है, तो वह कहता है कि बैंक से रुपया नहीं आया है और बैंक कहता है कि एपेक्स बैंक से रुपया नहीं आया है। इस प्रकार किसान को खेती के लिए उचित समय पर कर्जा नहीं मिलता है।

बिहार में आश्विन के महीने में मेले लगते हैं, जहां किसान बैल खरीदते और बेचते हैं। लेकिन किसान को इस काम के लिए उस वक्त को-आपरेटिव सोसायटी से रुपया नहीं मिलता है। ऐसा मालूम होता है कि सरकार को को-आपरेटिव्ज को ढाल बना कर अपने आप को बचाना चाहती है और कहती है कि हम को-आपरेटिव्ज की मार्फ़त किसानों की मदद करते हैं, लेकिन यह ग़लत है। बैंकों का कुल जमा 35 अरब रुपया है। यह सब रुपया सेठों को मिलता है। इस के अलावा एल० आई० सी० का 9 अरब रुपया भी सेठों को मिलता है। इस का अर्थ यह है कि इन 44 अरब रुपयों में से किसानों को एक पैसा भी नहीं मिलता है। अब बैंकों के राष्ट्रीयकरण का जो हल्ला हुआ है, उस से बैंक वाले

सोचनें लगे ह कि किसानों की भी कुछ मदद की जाये।

आप जानते हैं कि आषाढ़ से ले कर आश्विन तक का चार मास का समय खेती का है। इसी समय में काम कर के किसान को अपना और अपने परिवार का पेट पालना पड़ता है, अपने मजदूरों को खिलाना पड़ता है। उसी वक्त उस को पैसे की जरूरत पड़ती है, लेकिन उस को न तो को-आपरेटिव्ज से पैसा मिलता है और न किसी और जरिये से। इस स्थिति में खेती से पैदावार कैसे मिले। जब तक सरकार किसानों को पानी और बीज नहीं देगी, सस्ते दाम पर खाद नहीं देगी, अनाज रखने का ठीक इन्तजाम नहीं करेगी, कीड़े मारने की दवा नहीं देगी, तब तक किसान कैसे पैदावार करेगा ?

श्री जगजीवन राम की रिपोर्ट में कहा गया है कि 95 मिलियन टन तक पैदावार होगी। मुझे नहीं पता कि किस हिसाबी ने यह आंकड़े तैयार किये हैं, जिस जिले में मैं रहता हूं, उसके मोतिहारी, हरसिद्धी, गोविन्दगंज, जोगापटी, लौरिया, चनपटिया, बेतिया, मझौलिया और नौतन थानों में सूखा पड़ा है, क्योंकि हथिया का पानी नहीं हुआ है। ढाका और पताही का हिस्सा भी थोड़ा एफ़ेक्टिड है। मैं नहीं जानता कि किस आधार पर 95 मिलियन टन पैदावार का अनुमान लगाया गया है। पता नहीं कि रबी की फ़सल भी अच्छी होगी या नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को इस हिसाब के अनुसार काम नहीं करना चाहिए। जब किदवई साहब फूड मिनिस्टर थे, तो उन्होंने यह बयान दिया था कि हमारा हिसाब गलत है।

सरकार प्रोक्युरमैंट कर के सेठों के कारखानों से कपड़ा नहीं लेता है, लेकिन किसान जो गल्ला पैदा करता है, सरकार उस के घर से, उस का ताला तोड़ कर, सस्ते दाम पर उस को ले लेती है, जब कि बाजार में गल्ले का भाव उस से दुगुना रहता है। सरकार किसानों से तो गल्ला ले लेती है, लेकिन सेठों की तिजोरियों को वह नहीं छूती हैं। आज उन लोगों पर पांच अरब रुपया इनकम टैक्स का बकाया है, लेकिन सरकार ने किसी सेठ के घर पर छापा मार कर नहीं लिया। इस की तुलना में किसान भादों से आषाढ़ तक, जाड़े गर्मी में, मेहनत कर के जो गल्ला पैदा करता है, सरकार उस को छीनने के लिए तुरन्त पहुंच जाती है और प्रोक्युरमैंट और लेवी से उसको छीन लेती है। उस के लिए वह उन को जेल भी भेज देती है। लेकिन वह सेठों की तिजोरी पर कभी छापा नहीं मारती है। वह कभी नहीं कहती है कि उन के पास जो इतना कपड़ा पड़ा है, वह किसानों को सस्ता दे दिया जाये। हमारी सरकार समाजवाद लाना चाहती है, लेकिन इस तरह से वह समाजवाद कैसे लायेगी ?

सब जगह सीलिंग हो गया, लेकिन सीलिंग की सरप्लस जमीन नहीं निकाली गई। सरप्लस जमीन बेच दी गई या बेनामी कर दी गई। सरप्लस जमीन को बेच कर किसान ने पैसा रख लिया, लेकिन आज तक सेठों की इनकम पर कोई सीमा नहीं लगाई गई है। मैं ने 1952 में यह प्रस्ताव रखा था कि इंडिविजुअल इनकम पर सीलिंग होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने उस को नहीं माना था। डा० वी० के० आर० वी० राव ने भी कहा है कि इंडिविजुअल इनकम पर सीलिंग होनी चाहिए। श्री चन्द्रशेखर ने बैंकों के नैशनलाइजेशन के सम्बन्ध में हमारे पास जो काग़ज भेजा है, उस में कहा गया है कि बिहार की पर-कैपिटा इनकम 200 रुपये है। लेकिन हमारे मिनिस्टरों को क्या मिलता है ? उन पर सालाना क्या खर्च होता है ? मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में इन्ट्रस्ट का पोलराइजेशन शुरु हो गया है। एक तरफ़ तो सोशलिष्ट विचार वाले सब दल और तत्व इकट्ठे हो जायेंगे, जिन में राइट और लेफ्ट दोनों कम्युनिस्ट होंगे, और दूसरी तरफ़ धनी वर्ग के लोग होंगे। दस बरस में इस दक्ष में

[श्री विभूती मिश्र]

एक क्रान्ति होगी। जो ज्यादा खायेगा, ग़रीब जनता उस का पेट फाड़ कर निकाल लेगी। यह स्ट्रक्चर ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। इस का कारण यह है कि एक तरफ़ ग़रीबी बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ धन का केन्द्रीकरण बढ़ता जा रहा है।

जहां तक प्राइस कमीशन का सम्बन्ध है, श्री जगजीवन राम ने कहा है कि इस में कसान रखा जायेगा। और प्राइस कमीशन में, प्लानिंग कमीशन में बैठने वाले आदमी बड़े-बड़े अफसर हैं जिन को 2 हजार, 3 हजार, 4 हजार रुपये तनख्वाह मिलती है। वह एकोनामिकल टर्म्स पर सोचते हैं। कभी गांव में जाते नहीं हैं। कभी उन की मेहनत को देखते नहीं है। केवल अपने खाने के लिए, शहर को खिलाने के लिए, धनी आदमियों को खिलाने के लिए कीमत कम करते हैं।

उसमें किसान का एक भी रेप्रेजेन्टेटिव नहीं है जबकि गांधी जी ने कहा कि हिन्दुस्तान का मालिक किसान होगा लेकिन कहां किसान मालिक दिखाई देता है? एक बात और मैं बताना चाहता हूं क्योंकि टैक्सों की बात आई तो यह वही हाल है जो पुराने जमीदारों के समय था। पुराने जमीदार देखते थे कि गांव में फलां आदमी सफेदपोश हो गया तो सोचते थे कि कौन सा उपाय लगावें कि इस का हाल थोड़ा खराब कर दें ताकि यह तगड़ा न होने पाये। इसी तरह से सरकार सोचती है। गांव में किसी किसान को देख लिया कि उस ने पक्का घर बना लिया या थोड़ा सफेदपोश हो गया, कभी गए तो जरा चाय पानी और मिठाई खिला दिया तो वह क्या सोचते हैं कि यह बड़ा धनी आदमी है, इस पर टैक्स लगावें। लेकिन शहर में कितने ही आदमियों ने बताया कि फलां जमीन हम ने 500 रुपये में ली थी, वह 50 हजार रुपये में बिकी लेकिन शहर में कोई अर्बन टैक्स नहीं लगाया। गाडगिल साहब को और कुछ नहीं सूझा उन्होंने कहा कि पांच और दस एकड़ जो सिंचाई की जमीन है उसी पर टैक्स लगाओ। लेकिन टैक्स तो लगना चाहिए शहर वालों पर। शहर में देखिए कि कितने पक्के मकान बने और कितने बन रहे हैं? इन के पास कहां से पैसा आता है? लेकिन इन के पास कोई नहीं जाता है। न इधर वाले जाते हैं न उधर वाले जाते हैं। कोई नहीं जाते हैं····· (व्यवधान)····· तुम भी नहीं जाते। तुम्हारा काम तो सेठों से चलता है। जनसंघ का पूरा काम सेठों से चलता है, मैं जानता हूं। उपाध्यक्ष जी, हम लोगों को चुनाव में एक मोटर मिलना मुश्किल है और इनके उम्मीदवार को चार-चार मोटरें, यह कहां से आती हैं? इन का भी काम सेठों से चलता है। और यह जो हमारे कम्यूनिस्ट भाई हैं इन के यहां तो पैसा आसमान से झड़ता है। हम लोगों को तो बहुत मेहनत करने पर कोई नेता मदद कर देता है लेकिन इनके ऊपर तो आसमान से पैसा झड़ता है। चले जाइए बीरांज में थैलियां भर-भर कर ले आइए।

सवाल यह है कि इस देश के लोग जो गरीब आदमी हैं उन के लिए आप क्या सोचते हैं? गरीब जो खेती करता है, जो काम करता है, जो मेहनत करता है उस गरीब के लिए आप उचित कीमत उसकी पैदावार का दीजिए। प्राइस कमीशन का तुरत से तुरत सुधार कीजिए नहीं तो प्राइस कमीशन के जो सदस्य हैं, इसी बुनियाद पर प्राइस कमीशन कायम हुआ कि किसान की चीजों का इन्टीग्रेटेड दाम दिया जाय। हम ने ए० आई० सी० सी० में यह कबूल किया कि किसान को इन्टीग्रेटेड प्राइस देनी चाहिए। लेकिन नहीं दिया। कपड़े का दाम बढ़ गया, स्कूलों की फीस बढ़ गई, जूते का दाम बढ़ गया, छाते का दाम बढ़ गया, नमक का दाम बढ़ गया, सब उपयोगी चीजों के दाम बढ़ गए लेकिन किसान की चीजों के दाम नहीं बढ़े। हां ओपेन मार्केट में बढ़े हैं। लेकिन सरकार कहती है कि हम तुम्हारे ऊपर लेवी लगाते हैं और प्राक्योरमेंट करते हैं।

मैं लेवी प्राक्योरमेंट के खिलाफ नहीं हूं लेकिन सब चीजों के ऊपर लेवी प्राक्योरमेंट हो। जितने इंडस्ट्रियल गुड्स हैं उन के ऊपर भी लेवी प्राक्योरमेंट हो और किसान की पैदा की हुई चीजों पर भी हो। सब के ऊपर लेवी प्राक्योरमेंट हो तो हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन एक किसान वर्ग को अलग छांट कर के उसके ऊपर आप करते हैं।

आप देखिए उपाध्यक्ष जी, इस देश की राष्ट्रीय आय का 45 प्रतिशत हिस्सा किसान पैदा करता है जिस की आबादी 85 प्रतिशत है और 55 प्रतिशत जो आमदनी है उस का उपभोग हिन्दुस्तान के 15 प्रतिशत आदमी करते हैं। यह स्थिति कब तक रहेगी ? · ·

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : क्रान्ति आ जायेगी : इन्क्लाब आ जायेगा ।

श्री विभूति मिश्र : इन्क्लाब तुम से नहीं आयेगा। · · · (**व्यवधान**) · · · इन्क्लाब लाने के लिए जब तक पार्लियामेंट का मोह ममता हम को रहेगी तब तक इन्क्लाब नहीं आयेगा। इन्कलाब तो डाइरेक्ट ऐक्शन से आयेगा। इन्कलाब के लिए दूसरी सूरत, जो गांधी जी का रास्ता था वह अपनाना पड़ेगा। उसी रास्ते से इन्क्लाब आयेगा और इन्कलाब आने वाला है।

मैं एक बात कहता हूं कि किसान को आप सारी सहूलियत दीजिए। एक गंडक नहर है हिन्दुस्तान भर में सब से बढ़िया लेकिन आज तक केन्द्र सरकार उस को पैसा ही नहीं देती है। आज किसी स्टेट की आमदनी ज्यादा है, किसी की कम है। बिहार को आमदनी कम है। उसको आप बराबर नहीं कर रहे हैं । किसी स्टेट की पर-कैपिटा आमदनी कम है और किसी की ज्यादा है। यह प्लानिंग कमीशन का काम था कि जिसकी पर-कैपिटा आमदनी कम है उसको ज्यादा, इमदाद दी जाती है। लेकिन यह नहीं हुआ। इस का कारण यह है कि यह सरकार उन लोगों के हाथ में है जो अंग्रेजीशुदा आदमी हैं जो हिन्दुस्तान की प्राबलम को नहीं समझते। मैं चीन के खिलाफ हूं, माओ-त्से-तुंग के खिलाफ हूं। लेकिन माओ-त्से-तुंग अंग्रेजी भाषा नहीं जानता, चीन की भाषा को जानता है, चीन की परिस्थिति को जानता है। उस ने चीन को आगे बढ़ा दिया। हमारे नेताओं ने अंग्रेजी भाषा जान कर के इस देश का बटवारा किया। इस देश की तरक्की को आगे रोक दिया। अगर आज भी किसानों के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो इस देश में बगैर क्रान्ति हुए नहीं रहेगी।

SHRI MUTHU GOUNDER (Tiruppattur) : Sir, the food situation has eased considerably now and we are going to have a bumper harvest this year to the tune of 95 million tonnes. On previous occasions, when we discussed the food situation in this House, the situation was tense and gloomy, with famine and drought conditions prevailing all over the country. I think now the Government has selected the most opportune time to have this discussion. The monsoon has been favourable to some extent and it has contributed to increased production. Apart from that, it is quite evident that in rural areas a pucca revolution has come about in farming methods. That is the major factor contributing to increased production. In rural areas, wherever progressive farming is there, you can find ryots standing in queues to get fertilisers and new strains. Thanks to Mr. C. Subramaniam who started the new strategy in those days, it has caught on and has gained momentum. We, the farmers, have taken up the challenge to provide this country with enough food. We are already at it and if the Government is now sincere in its efforts to implement all the schemes it has got, we can solve the problem. No one can suggest any new or novel idea ; they have exhausted almost all ideas. We have already started work and we have only to keep up the momentum.

I can tell the House that the Indian farmers are not inferior to the farmers in any country. American farmers are considered to be the most efficient because an American family consisting of 4 or 5 mem-

[Shri Muthu Gounder

bers is able to manage big farms of a thousand acres and get the maximum yield also. In Japan also the farmers are getting the maximum yield, but they are managing only farms of 5 to 7 acres. Indian farmers have settled in America, purchased farms there and are running them in competition with the American farmers. There are I hope about a thousand farmers in USA, most of them in California and adjoining areas. Most of them are our Punjabi and Sardar friends. With a little capital, which they might have earned by hard work about 20 years back, they have purchased some bits of land. Now year after year they are acquiring new lands from their neighbour American farmers. Some of these farms are better managed than the American farms. Some orchards managed by Indian farmers in America are much better than American farms. So, if they are given the tools, equipment and facilities which are needed, the Indian farmers are in no way inferior to any farmers of any country. In the Philippines where the Ford and Rockfeller Foundations are working, in the International Rice Research Institute our Indian agronomists and scientists are doing magnificent work and they have been responsible for bringing out the IR.8 and other varieties. Therefore, if we are given the necessary tools we are prepared to solve the problem. Is the Government sincere in its efforts is the question ?

I am sorry to say tha eril isers are the costliest in India whereas they are the cheapest in Japan and America. Government has stopped the subsidy which they were giving hitherto. Because of this the price of fertilisers has risen. The Government of Madras, which is also doing its best to increase agricultural production, has been trying to get some subsidy. Other States have also been trying for it. But the Government of India, because of its financial commitments and financial troubles, has not been in a position to give any subsidy for fertilisers.

The other day, Sir, I heard one hon. Member, Shri Yajnik, speaking at great length against introduction of fertilisers. Many in our country are compost manure minded. If you want to increase production, with the limited land at our disposal, we have to resort to intensive cultivation. Intensive cultivation of paddy means introduction of high-yielding varieties. High-yielding varieties can go along with irrigation facilities and fertilisers. Without fertilisers, high-yielding varieties, especially in the case of paddy, will not be of any use. We cannot think of it without fertilisers because high-yielding varieties have short durations. In these days you are introducing Japanica varieties. Indica varieties having long duration do not give high yields. They cannot withstand the long dosage of nitro genous fertilisers. In the case of high yielding varieties, because they are of short duration, there is no way but to use fertilisers. If you are to use only compost manure you have to fill the field to a height of six inches or so if you are to give the needed nitrogenous fertiliser. So there is no other way, no escape, but to use fertilisers.

Therefore, the Government has to find out ways and means to start fertiliser factories. International policies and politics should not stand in the way. They should get money from America, Russia or any other country—it does not matter. They should find money and start such industries to produce fertilisers immediately because that is the biggest need of the country.

The hon. Member over there spoke about seeds. There is a good demand for seeds. It seems, nearby, in a place near Delhi, one or two farmers who were having sonar, a Mexico variety of wheat, earned undue profit by selling that variety of seeds. I am not very conversant with wheat, but in the case of paddy there is now demand for high-yielding varieties. But on account of the introduction of these new varieties blight diseases have set in. This year in the Vishakhapatnam area, I understand, the blight disease is too much that it has affected already two lakh acres and the entire crop worth Rs. 3 crores to Rs. 4 crores is withering now. New variety means more fertiliser and more nitrogenous fertiliser means more diseases to crops. Therefore, we have to find out blast and blight resistance varieties immediately. Otherwise, instead of having more yield we will be inviting more diseases with the result that the production will go down. Therefore, in consultation with foreign organisations like the Food and Rockfeller Foundations we have to

find out new strains, new blast and blight resistance varieties.

My. hon. friend, Shri Bibhuti Mishra was saying that price factors have not very much affected our ryots. I should say that the prices fixed by government are reasonable to some extent. We have also to take into account the consumers. The poor consumers cannot afford to pay high prices because of their poor economic position.

Now there is disparity in prices between commercial crops and food crops. Though we have been pleading for the last so many years that there should be no such disparity, we have not succeeded and that disparity is continuing. Most of my hon. friends were a little while earlier referring to the price of sugarcane. Any farmer in our area is able to make, at the prices at present offered by the factory owners for sugarcane, a profit of Rs. 2,000 per acre from sugarcane whereas farmers who are growing paddy, like me, are not able to get more than Rs. 500 per acre per year. Because of this disparity in prices, a farmer who is cultivating sugarcane is in a position to offer Rs. 4 as daily wage to the labourers, whereas a paddy cultivator like me cannot pay that much wage. Similarly, he is able to purchase groundnut cakes and other things in the market at a price of Rs. 40 or even 50 whereas a cultivator of paddy cannot pay that much.

The price that is paid in India to the cultivator of paddy is the lowest. I made enquiries and I understand that a farmer in the United States is getting Rs. 50 for 75 kilos of paddy in terms of the dollar equivalent. They are getting it for the Indica variety. Perhaps, with the exception of Thailand, not Philippines, we are paying the minimum price for cultivation of paddy, whereas the prices we offer for groundnut, sugarcane, chillies and other things are comparatively higher that those of the international price. That is why I say that a farmer in India who is producing paddy is in a disadvantageous position.

Government should seriously consider this aspect of the problem. The price which you offer to a farmer for his paddy should not only be sufficient but it should be such that there will be no disparity between the prices offered for food crops and commercial crops. Then alone will we be satisfied. Now, on account of the better prices offered for commercial crops, many people are switching over to commercial crops. I think the government will not be worried about it because we need commercial crops as much as we need food crops. We know that the country needs more of commercial crops. With the land at present available for foodgrains we can produce more by introducing new methods of cultivation.

If the hon. Minister is kind enough to come to Madras, we can show how AD727 is doing a miracle there. In the first year of its introduction we were getting 35 bags. Last year we got 30 bags and now it has come down to 23 bags. This is my explanation though I am not a scientist. The yield of any strain will be going down as time passes. It is not like hybrid varieties of jowar, sorgam or maize in which we collect quality seeds from seed planters. Here, in the case of paddy, we use the same seed which we get from our field in the next year. So, it loses some of its virulity. So, we cannot depend upon the same high-yielding varieties, so far as paddy is concerned. We have to go in for newer and newer varieties.

Madras and Andhra require very urgently frost-resistant and blight-resistant varieties, which should be of a short duration.

Coming to irrigation, unless we find a solution to fight against the vagaries of monsoon we will not be finding any solution at all for our short production. We can find it and we have found it ; I should not boast that I have found it. If the monsoon failed this year or the next year, it will not affect my farm or many farms of the many thousand farmers who are intelligent enough. Every farmer in my area is now having a pond for 40 acres of land. If he has a farm of 100 acres, it means that he will be having two ponds. If we get too much of rain, the ponds will be filled up and the wells in the entire region will be getting sufficient water for lift irrigation.

I think, many of our friends have gone to America. Not only here, there also lift irrigation is very popular. If you go from

[Shri Muthu Gounder]

New York to Washington in a bus, you can see miles and miles of lift irrigation and sprinkling irrigation works at the same time. By introducing lift irrigation, we can save water and next time we can use it for cultivation. We want to introduce this system in the Madras State because we have already exhausted all our water sources. We have got only one source, that is, the Cauveri, and we have exhausted to it the full. Every bit of water has already been exhausted. Now we want to desilt the irrigation tanks for which we have prepared a scheme called the Rayappa Scheme. We want you to give us a grant of Rs. 17 crores, or Rs. 20 crores. We know your financial position, and everything, but since we know that you have got a kind heart towards Madras because we are very much interested and are keen in producing more, I requested you that you should be kind enough to find a way to give more funds to us and other States which are really interested in it and are really doing good work towards more food production.

We can introduce lift irrigation everywhere in India. If you go from Wardha up to Amla, in vast areas if you dig a well within 30 feet you can get water and you can find one pumping set in a mile, whereas in our area within a square mile you can find 50 pumping sets. By the introduction of pumping sets and electrification we are solving the food problem in Madras State. The Government should give high priority to digging one million wells a year. It is not a very difficult thing. Only by that we can win over the drought conditions and the vagaries of monsoon. The Government, I think, will be serious about it.

Then, without mechanisation of our agriculture we cannot dream of producing more. How to mechanise ? Mechanisation starts by the introduction of tractors. Now, tractors are costly. The Russian tractors are very popular. They cost only Rs. 3,500 or just Rs. 500 more at Bombay Port, but the price we have to pay is Rs. 8,000 for a 14 horsepower Russian tractor. When Russia wants to provide us with cheap tractors, why should Government stand in the way and levy so much duty ? No doubt, we have to allow indigenous production of tractors, but those tractors cost too much of money. They will give you some tractor at Rs. 15,000 or Rs. 20,000. Each agent dealing in Fergusson tractors gets Rs. 2,000 to Rs. 3,000. We have no escape except to accept that. So, we should not feel shy to get tractors from the USSR. With the tractors Communism will not come. If Communism is to come, it will come ; if it is not to come, it will not come with the tractors.

SHRI NAMBIAR (Tiruchirappalli) : Tractors is all Communism.

SHRI MUTHU GOUNDER : We are taking a lot of technical assistance and know-how from the Americans. Without American help, the Ford Foundation or the Rockfeller Foundation, we would not have progressed with our hybrid varieties of jowar, sorghum, maize and other things. We are able to have a miraculous production of maize. It will solve the problem within five years ; 1970 will be too early, but by 1972, we can solve the problem. If we politicians pay less attention to politics, if, instead of aspiring for ministership, we devote our time to farming, then we can do wonders. Even though I am on the Opposition, I am of the opinion that this time we have got competent Ministers in the Ministry of Food & Agriculture. I am more a farmer than a politician. If, as I said, instead of aspiring for ministership, we devote our time to increasing our production, then within five years we can do wonders.

SHRI MANOHARAN (Madras North) : Our Food Minister was criticised by the leader of the Congress Party in Madras State.

SHRI MUTHU GOUNDER : If the Central Government give the Madras Government enough grants, then we will do wonders. We have already got schemes to give rice at rupee one a measure, and for that, we requested the Central Government to give subsidy ; perhaps if they had given at least some token grant, we would have been encouraged, but they have not done that. Still, we will be carrying on and we are going to introduce this in all the areas.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He will conclude now.

SHRI MUTHU GOUNDER : Unfortunately in Madras State, like Andhra Pra-

desh, we are having less water in reservoirs ; even then, we want to produce more.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The hon. Member will conclude.

SHRI MUTHU GOUNDER : With more fertilisers and with due irrigation facilities, we can solve the problem. Have one million wells with pumping sets every year ; then, we can fight against the vagaries of monsoon and by that, we can solve the food problem.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा प्यारा देश किसानों का देश है । मुझे बड़ी शर्म आती है जब मैं देखता हूं कि कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी हमें अपने देश के पचास करोड़ भाइयों के लिए बाहर से अन्न मंगाना पड़ता है । इसकी वजह यह है कि किसान को जो दर्जा मिलना चाहिये इस राज में, इस समाज में वह उसको नहीं मिला है । किसान सहमा हुआ बैठा है । उसका दिल बैठा हुआ है । आजादी से पहले जो उसका ख्याल था कि पता नहीं उसका क्या दर्जा होगा, उसको क्या मिलेगा अपने राज में उसको आज वह

MR. DEPUTY-SPEAKER : The hon. Member may continue after Lunch.

13.00 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at four minutes past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

MOTION RE : FOOD SITUATION IN THE COUNTRY—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER : The House will now resume further consideration of the motion regarding the food situation in the country.

Shri Randhir Singh may now resume his speech.

श्री रणधीर सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अर्ज कर रहा था कि तमाम देश का किसान परेशान है, उस के दिमाग में आराम नहीं है, दिल में सुकून नहीं है । यह बात मैं नहीं कहता; यह बात देश के हालात बताते हैं । किसान चाहे बंगाल का हो, आसाम और बिहार का हो, चाहे वह यू० पी०, पंजाब का और चाहे हरियाणा का हो, वह हर जगह परेशान है । जगह जगह ये जो वजारतें उलट रही हैं, ये बाद में आने वाले बड़े तूफ़ान से पहले के बगूले हैं । उस में सब से आगे किसान है । मैं बड़े जोर से कहना चाहता हूं कि यह मौका है, जब कि हालत को सम्भाला जाना चाहिए । मैं डंके की चोट से कहना चाहता हूं कि जिस तरह चीन का किसान इनक्लाब का सरबराह बना था, उसी तरह अब हिन्दुस्तान का किसान ज्यादा अरसा आराम से नहीं बैठ सकता है । वह यह महसूस करता है कि हालांकि मुल्क में अस्सी फ़ीसदी उस की आबादी है, मुल्क के पांच लाख गांवों में उस की अक्सरियत है, लेकिन फिर भी उस के साथ सौतेली मां का सा सलूक होता है । किसी भी हुकूमत में, चाहे वह मरकज की हो और चाहे स्टेट की, किसान को इन्सान नहीं समझा जाता है, उसको कीड़ा-मकोड़ों, ढोर-डंगर या भेड़-बकरी समझा जाता है । उस को लद्दू जानवर समझ कर सब से पहले उस पर टैक्स लगा दिया जाता है । आजादी मिलने के बाद किसान पर सैकड़ों किस्म के टैक्स दुगने और तिगुने कर दिये गए है । उस की मालगुजारी, नहरी दाम, लोकल रेट और चाही लगान वगैरह को बढ़ा दिया गया है । इस के अलावा आमदनी टैक्स और चौकीदार टैक्स में भी इजाफ़ा कर दिया गया है । एक मामुली कमजोर इन्सान और सौ किस्म के उस पर टैक्स है ।

किसान खून पसीना एक कर के काम करता है । उसका पूरा कुनबा, उस के बच्चे, उसकी औरत और माता और उस के दोस्त दिन-रात खाक के साथ खाक बने रहते हैं, लेकिन जब उस की कुछ पैदावार होता है, तो उसकी जिन्स कोड़ियों के दामों मंडियों में उठ जाती है । इस के बाद उस पर इतने टैक्स लगते हैं कि उस का जीना दूभर हो गया है ।

[श्री रणधीर सिंह]

जैसा कि मैं ने शुरू में कहा है, किसान का दिल बैठा हुआ है। वह यह महसूस करता है कि राज करने वाले दूसरे हैं और मरने के लिए मैं हूं, टैक्स मुझ पर लगाते हैं। अब किसान ज्यादा देर तक इस हालत को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। इस लिए मैं कहना चाहता हूं कि इनक्लाब के सर-बराह की तसल्ली की जाए, वर्ना इस देश में हालात नार्मल नहीं होंगे। मैं कांग्रेस बैंचिज से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि इस देश के हालात खराब हैं।

किसान को उस की जरूरत की चीजें ठीक कीमत पर दी जायें और उस को अपनी पैदावार का मुनासिब रिटर्न मिलना चाहिए। उसका गन्ना कौड़ियों के दाम लिया जाता है। अगर वह मिल में गन्ना नहीं देता है, तो उसको गिरफ्तार किया जाता है, उस के गन्ने को एटैच किया जाता है और एक मुजरिम की तरह उसको जेल भेज दिया जाता है। आज "जय जवान, जय किसान" का नारा तो बहुत लगाया जाता है, लेकिन किसान के साथ जो सलूक होता है, उस को वही जानता है। जैसा कि आज क्वैस्चन-आवर में मैं ने कहा था, जहां जलाने की सूखी लकड़ी का भाव तो सात आठ रुपये मन है, वहां गन्ने का भाव तीन रुपये मन है। जो जमीन सोना उगलती है, अपनी उस बेहतरीन जमीन में किसान नेशकर पैदा करता है। एक साल में उसकी एक फ़सल पैदा होती है। नेशकर बेहतरीन बीज, बेहतरीन खाद और ज्यादा से ज्यादा पानी मांगता है। किसान के पानी के दाम दुगुने हो गए हैं और बीज के दाम भी बढ़ गए हैं। खाद तो वह खरीद ही नहीं सकता है। सरकार की तरफ़ से कहा जाता है कि हम ने खाद के इतने कारखाने खोल दिये हैं। जब कोई खाद को खरीद ही नहीं सकता है, तो इन कारखानों का क्या करेंगे? अगर सरकार देश में चीनी की मिकदार बढ़ाना चाहती है, अगर वह फ़ारेन एक्सचेंज हासिल करना चाहती है, अगर वह फ़ारेन एक्सचेंज के जरिये बाहर से डिफेंस मैटीरियल खरीदना चाहती है, तो उसको किसान को उसके गन्ने की मुनासिब कीमत देनी पड़ेगी। किसान अपना जमीन से भाग रहा है। वह उस पर गन्ना नहीं बोना चाहता है। वह क्यों न उस पर दूसरा अनाज पैदा करे?

वह कामर्शियल क्राप पैदा करेगा जिस में उस को फायदा है। लेकिन में यह कहना चाहता हूं कि देश के हित में यह बात है कि ज्यादा से ज्यादा गन्ना पैदा किया जाय, ज्यादा से ज्यादा चीनी पैदा की जाय जिस में ज्यादा से ज्यादा फारेन एक्सचेंज मिले। तो इसके लिए किसान को अच्छे से अच्छा बीज, अच्छे से अच्छा फर्टिलाइजर कम कीमत पर आप को देना पड़ेगा। फर्टिलाइजर की फैक्ट्री जगह जगह आप ने खोल दी है। लेकिन किसान उसे खरीद नहीं सकता। उसे आधे दामों पर फर्टिलाइजर देना चाहिए। इंडस्ट्री के लिए दुनिया भर की सब्सिडी आप देते हैं। और दूसरी चीजों में सब्सिडी दी जाती है। लेकिन जो असल में जरूरतमंद आदमी है उस को तो आप सब्सिडी देते नहीं हैं। इसलिए मैं आप से यही कहना चाहता हूं कि उस किसान को आप इन्सेन्टिव दें। उसको यह कहें कि देश तुम्हारा है, अगर तुम नहीं कमाओगे, देश की पैदावार नहीं बढ़ाओगे तो देश में इन्कलाब आ जायगा। चीन की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। कहां इतना खतरा है चीन से और पाकिस्तान से? मैं कहता हूं कि इस देश को भुखमरी से सब से ज्यादा खतरा है। लाखों और करोड़ों की तादाद में इन्सान मरेगा अगर किसान बेदिल हो गया पैदा करने से। और वह पैदा जब करेगा जब किसान को छाती से लगाया जाय। लेकिन किसान को छाती से नहीं लगाया जाता। किसान को कौड़ियों की कीमत पर अपनी जिन्स बेचनी पड़ती है। और फिर लोहा उस को दुगुने तिगुने दामों पर मिलता है। लोहे की उसे अपनी हर चीज

के लिए जरूरत है। उस का फावड़ा, खुरपा, दरेंती, कसैला, यह जितनी भी चीजें हैं सब के लिए उस को लोहा चाहिए। इसी तरह सीमेंट उसको नहीं मिलता। आउट आफ बाउंडस हैं उस के लिए सीमेंट खरीदना। किसान क्या कोई हमेशा झोंपड़ी में रहने के लिए पैदा हुआ है। लेकिन वह सीमेंट नहीं ले सकता। सब ब्लैकमार्केटियर्स के पास चला जाता है। ब्लैक मार्केट में चाहे जितनी सीमेंट खरीद लो, उस की कमी नहीं है। लेकिन वह किसान के वश का नहीं है और कोई सीमेंट का कोटा वैसे किसान को मिलता नहीं। यह बात कोई बर्दाश्त करने की है? और फिर चीनी आउट आफ बाउंडस है किसान के लिए। किसान की जच्चा औरत को जब बच्चा पैदा होता है तो उस को चीनी नहीं मिलती। त्यौहार पर उसे चीनी नहीं मिलती। तो क्यों पैदा करे किसान? जब उस को कोई चीज मिलती नहीं है तो किसान की दिलचस्पी क्या है पैदा करनें में? कोई भी चीज होती है शहर के लिए होती है। देहात के लिए नहीं होती। मैं आप की तवज्जह इस तरफ इसलिए दिला रहा हूं कि अब बाबेला नहीं रहा वह किसान। बड़ा सयाना हो गया है और यह जो बैठे-बैठे हिसाब लगाते हैं इनसें कहीं ज्यादा सयाना है। दूकानदार कोई अपनी चीज बेचता है। मुनाफा मिलेगा तो बेचेगा, नहीं, तो नहीं बेचेगा। एक कानून बना था पहले उस की जमीन पर जबर्दस्ती कब्जा करने के लिए। गांव के गांव उठा दिए, दिल्ली के नजदीक के, शहरों के नजदीक के। अगर कोई सड़क बनानी है, कोई नहर निकालनी है, कोई अड्डा बनाना हुआ तो डंगर समझते थे किसान को। अगर एक बीघा जमीन चाहिए थी तो एकड़ की एकड़ जमीन ले लेते थे। फिर बीच में कंपनियां आ जाती हैं, सरमायेदार आ जाते हैं। जो जमीन कौड़ियों के दाम खरीदी जाती है रातों रात वही जमीन कई कई सौ रुपये गज हिसाब से बिकनें लगती है। तो वह किसान बावला नहीं है। वह समझता है हर एक बात को। अब वह बर्दाश्त नहीं करेगा।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर नई जमीन किसान तोड़े, अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा अनाज पैदा हो इस देश में तो उस को उस के लिए ग्रान्ट दी जाय। बार बार मैं अपनी स्पीचेज में यहां कह चुका हूं इस बात को लेकिन जूं तक नहीं रेंगती है इन के कानों पर। मैं मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि अमेरिका और इंग्लिस्तान में ऐग्रीकल्चर ऐक्ट बना हुआ है कि जमीन नवतोड़ की जाय तो किसान को ग्रान्ट दी जाय। ब्लैक मार्केटियर्स को, बड़े बड़े कारखानें वालों को आप ग्रान्ट देते हैं, एक फैक्ट्री कोई लगाये छोटी सी तो उसको ग्रान्ट देते हैं, छोटा-सा मामली धन्धा कोई शुरू करे तो उस को ग्रान्ट देते हैं और वह ग्रान्ट भी कहां इस्तेमाल करते हैं? सब खा जाते हैं ब्लैक मार्केटिंग में। कहां वह उस को उस काम में इस्तेमाल करते हैं जिस के लिए दी जाती हैं? इधर एक यह सपूत है देश का जो काम शुरू करना चाहता है। नई जमीन तोड़ना चाहता है, पथरीली रेतीली जमीन को काश्त के लायक बनाना चाहता है। उस के लिए आप को उसे इन्सेन्टिव देना चाहिए। चाहिए तो यह कि ज्यादा से ज्यादा पानी का बन्दोबस्त किया जाय। लेकिन यह बात नहीं है तो कम से कम उसको एनकरेज करने के लिए नवतोड़ जमीन के लिए आप किसान को ग्रान्ट तो दीजिए।

एक चीज मैं खास तौर से कहना चाहूंगा एक मुकर्रर करो आप कोई कमीशन। दुनिया भर की प्लानिंग आप करते हैं। एक डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन आप ने बैठा दिया। पता नहीं कहां की जमीन की या आसमान की बातें करता है। ऐसे ही आदमी आप को मिलते हैं? किसान का दुश्मन आदमी, किसान के खिलाफ आदमी और सब से बड़ा प्लानिंग कमीशन का नम्बर (2) आदमी बना कर बैठा दिया। कैसा आदमी है जो कहता है कि किसान पर टैक्स लगाओ,

[श्री रणधीर सिंह]

जो कहता है कि किसान का खून चूसो ? मैं बिना इम्तियाज के पूरे जोर से कहना चाहता हूं कि प्लानिंग कमीशन में या कोई भी जगह हो जो आदमी किसान के खिलाफ बात करता है उस को हटाइए। .... (व्यवधान) .... डिप्टी स्पीकर साहब, आप मेरी बात सुनिए। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं ....

MR. DEPUTY-SPEAKER : May I point out that whatever the Deputy Chairman of the Planning Commission might have said, it was within the plan frame that he has suggested certain things, and unless the State Governments agree, it is no use criticising his proposal ?

श्री रणधीर सिंह : मैं कहता हूं कि सरकार को ऐसे ही आदमी मिलते हैं ? जो आदमी कमाने वाला है उस को ही दबाते हैं ......

SHRI SHEO NARAIN (Basti) : The Deputy-Chairman of the Planning Commission is not an exception like the Governor or the President of India.

श्री रणधीर सिंह : खैर, छोड़िए इस बात को। यह बात मैं ने ऐसे ही कही थी। यह किसान का देश है। किसान को आगे बढ़ाना है। उसको एन्करेज करना है तो हर काम के लिए कोई आवाज उठती है तो उस पर टैक्स लगा दो, वह तो पहले ही मरा पड़ा है। जहां सारे देश में बात होती है कि किसान का लगान तोड़ा जाय, किसान की मालगुजारी माफ कर दी जाय वहां यह साहब कहते हैं कि माफ नहीं की जाय, दुगुनी कर दी जाए। एक रोटी मांगता है कि एक रोटी दे दीजिए, दूसरा कहता है कि थोड़ी मलाई भी दे दीजिए। वह कहते हैं कि नहीं रोटी भी छीन लेनी चाहिए। मलाई देने का सवाल कहां आता है ? तो यह प्लानिंग कमीशन के ऊपर ऐसे ही आदमी बिठाए गए हैं जिनकी हमदर्दी नहीं है किसान के साथ। इसकी वजह से किसान का दिल और मुरझा जाता है। मैं कहता हूं एक प्लान बनाया जाय। पांच साल का हो, सात साल का हो या दस साल का हो। एक प्लान आप बनाओ। रुपया मैं बताता हूं कहां से आयेगा। एक हजार करोड़ रुपया एल० आई० सी० का पड़ा है वह पकड़ो आप हिन्दुस्तान की लाइफ इन्शोरेंस का, देश का रुपया एक हजार करोड़ पड़ा है और फिर यह दुनियाभर के बैंक क्यों ? क्यों नहीं कब्जा करते आप ? दस साल में पांच साल में हो, सात साल में हो, आप एक मनसूबाबन्दी बनाओ, एक प्लान बनाओ कि हिन्दुस्तान की जितनी काबिले जरायत जमीन है, काश्त की जमीन है, एक एक चप्पा जमीन के ऊपर पानी हो। आप यह चीज बना लीजिए। पांच साल में, सात साल में बना लीजिए। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं आप को सुझाव देना चाहता हूं कि रुपया देश का चाहे जहां भी हो, जिसके पास भी हो, चाहे बिरला, टाटा के पास है या बैंकों के पास है या एल० आई० सी० के पास है या जागीरदारों के पास है, वह रुपया आप वसूल कर लो। एक नहीं के ऊपर जैसे आप किसान की जमीन पर कब्जा कर लेते हो वैसे ही वहां भी क्यों नहीं करते ?

डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे थोड़ा-सा टाइम आप दें ....

MR. DEPUTY-SPEAKER : Not more than 15 or 16 minutes. I have to accommodate representatives from every State. It is not possible.

श्री रणधीर सिंह : मैं इसी वास्ते तो बोल रहा था कि आप मुझे टाइम देंगे .... (व्यवधान) ... अच्छा अब से केवल 10 मिनट मुझे दे दें। किसान के नाम पर मैं अपील करता हूं आपको।

Mr. DEPUTY-SPEAKER : Try to conclude now. Already you have exhausted 16 minutes.

श्री रणधीर सिंह : यह तो मैं जानता हूं, आप जरूर मुझे टाइम देंगे। अब 2-20 हुआ ठीक 2-30 तक मैं खुद बैठ जाऊंगा।

डिप्टी स्पीकर साहब, जो बात मैंने की वह इसलिए की कि हमें शर्म आती है मांगते मांगते। कभी अमेरिका के पास जाते हैं, कभी कैनाडा के पास जाते हैं, कभी आस्ट्रेलिया के पास जाते हैं। मैं कहता हूं किसान को पानी दो। किसान सारी दुनिया को खिला देगा।

अगली बात मैं मिनिस्टर साहब से यह कहना चाहता हूं फिर दोहराता हूं, बार बार मैं तो कहते-कहते थक गया जैसे इंडस्ट्रीज फाइनेंस कारपोरेशन है वैसे ही आप किसान के लिए एक ऐग्रीकल्चर फाइनेंस कारपोरेशन क्यों नहीं बनाते? अरबों रुपया इकट्ठा करो और किसान को कहो लो दस हजार, लो पन्द्रह हजार, 20 हजार। वह किसान कहीं भाग नहीं जायगा। उससे वह ट्रैक्टर खरीदेगा। उससे वह ट्यूबवेल लगायेगा। उससे वह पम्पिंग सेट लगाएगा। उससे वह अच्छे बीज लायेगा। उससे वह अपनी जमीन को इम्प्रूव करेगा। और उससे सारा देश और सारी जनता फायदा उठायेगी। परमात्मा के नाम पर जैसे इंडस्ट्रिअलिस्ट के लिए है वैसे ही उसके लिए भी आप एक फाइनेंस कारपोरेशन बना दीजिए। उसको कोआपरेटिव सोसाइटीज के पास मत भेजो। पंडित जी ने बड़ी ठीक बात कही थी कि बड़ा खुददार होता है किसान। किसान रुपया उससे लेगा जो किसान की खुददारी पर हमला नहीं करेगा। ये लोग जो कुड़की करने वाले हैं, तकावी के नाम से जो किसान की जमीन को कुड़क करते हैं, किसान उनसे रुपया नहीं लेना चाहता, कोआपरेटिव सोसाइटी से, जो उसको कान पकड़ाते हैं, मुर्गा बनाते हैं, उनसे किसान रुपया नहीं लेना चाहता, किसान आप से रुपया लेना चाहता है और आप उसको सस्ते इन्टरेस्ट पर रुपया दो, दो-चार साल के लिये नहीं, 20 साल के लिये दो, उसकी जमीन गिरवी रखो, उसके बैल, भैंस गिरवी रखो और आप उसको रुपया दो, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर सही तरीके से उसको आप क्रेडिट देंगे तो आप देखेंगे कि वह पहले से कहीं ज्यादा पैदा करेगा। आज क्यों पैदा नहीं करता है? इसलिये कि उसके पास कुछ नहीं है। आज अगर सबसे ज्यादा नुकसान का, टोटे का कोई काम है तो जमींदारी का काम है, लेकिन अगर किसान के पास पैसा होगा, उसके पास अच्छे बीज होंगे, उसके पास अच्छे इम्प्लीमेन्ट्स होंगे, पानी का बंदोबस्त होगा तो आप देखेंगे कि पर-एकड़ प्रोडक्शन कहीं ज्यादा बढ़ेगी।

दूसरी बात मैं बिजली की बाबत कहना चाहता हूं। मुझे पता है कि आज बिजली के कनेक्शन के लिये उसको दो-तीन हजार रुपये रिश्वत में देने पड़ते हैं—यह मैं स्टेट की बात करता हूं। जहां आप उसको प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये दूसरे साधन देना चाहते हैं, वहां आप उसके लिये बिजली का बन्दोबस्त कीजिये।

इसके बाद क्राप इन्शोरेन्स की तरफ़ मैं आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं—मैं पहले भी कई दफा इसका जिक्र कर चुका हूं। जब आदमी का इन्शोरेन्स होता है, कार का इन्शोरेन्स होता है, साइकल का इन्शोरेन्स होता है, फाउन्टेन-पेन का इन्शोरेन्स होता है, करोड़ों रुपये की जायदाद का इन्शोरेन्स होता है, तो फिर क्राप का इन्शोरेन्स क्यों नहीं होता। इसलिये मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप क्राप इन्शोरेन्स को लागू कीजिये।

तीसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि किसान को सिर्फ जमीन पर ही बोझा मत बनाइये। हिन्दुस्तान में डंगरों की आबादी 15-16 करोड़ के करीब है और मेरे हरियाणा स्टेट में—यह बात मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि यह स्टेट डेनमार्क बनने की स्थिति में है—बेहतरीन नस्ल की गाय-भैंसें हैं, इसलिये मैं

[श्री रणधीर सिंह]

आपसे कहना चाहता हूं कि कुछ रुपया आप उधर भी लगायें। उनको प्रोडक्टिव फूड दो, ज्वार-बाजरा से ही सेहत नहीं बनती, अगर देश में अच्छे डंगर होंगे तो देश की हैल्थ बनेगी—इस तरफ आपको ध्यान देना चाहिये।

आखरी बात मैं ज़ोन्ज़ के बारे में कहना चाहता हूं। क्या कर रहे हो? जो मुनाफ़े की बात है, हमारी फसल—गेहूं हो या जो कुछ भी हो, उसको अगर हम कहीं बेचना चाहें, तो आपने हमारी फसल बेचने के लिये पाबन्दी लगाई हुई है—यह पाबन्दी हमारे हुकूक के खिलाफ़ है और किसानों की खुददारी पर ठेस है। मैं चाहूंगा कि ज़ोन्ज़ वाली बात को खत्म करें।

मंडी के बन्दोबस्त की बात और कह दूं। आज वहां पर किसान की लुटाई होती है, ये दरमियान के लोग उसको लूट रहे हैं। 20 रु० के भाव में ये लोग उससे ले लेते हैं और 100 रु० मन पर बेचते हैं, 70 रु० मन वे बीच में खुद खा जाते हैं। जो लोग न खेती करते हैं, न पानी का काम करते हैं और न किसी किस्म की लेबर करते हैं—इनको बीच में से हटाओ और मैं चाहता हूं कि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन इस काम को करे।

मैं जनाब बड़ा मशकूर हूं कि आपने मुझे इस मौके पर बोलने के लिये टाइम दिया।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, खाद्यान्न संकट का मामला जिस तरह से उलझता जा रहा है और जिस तरह से इसकी गहराई बढ़ती जा रही है, इस से देश एक ही नतीजे पर पहुंच रहा है कि खाद्यान्न संकट का अन्त तभी होगा, जब इसकी जननी सरकार, कांग्रेसी सरकार का अन्त होगा, उसके बगैर अन्न संकट खत्म होनेवाला नहीं है। महोदय, इस बात को मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि मंत्री बदलें, प्रधान मंत्री बदलें, आज हमारे मुल्क की नीति करोड़पतियों और बड़े बड़े भूस्वामियों के इशारे पर चल रही है। हम सिंचाई, बिजली, खाद, वगैरह की बातें करते हैं, मगर अभी भी हमारे खेतीहरों का दो-तिहाई हिस्सा ऐसा है, जो बेज़मीन हैं, जो साल भर मेहनत करते हैं, बैसाख की धूप में, सावन-भादों की कीचड़ में, पूस-माघ के जाड़े में मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसके पास एक कट्ठा जमीन नहीं है, उसके पास रहने के लिये भी अपना घर नहीं है, घर के लिये जमीन अपनी नहीं है। ये लोग उसके हित की बातें करते हैं, समाजवाद की बातें करते हैं, सहकारिता की बातें करते हैं, लेकिन सहकारिता वही करेंगे जिनके पास हजारों बीघे जमीन है, घर के दो-चार भाई मिल कर सहकारी समिति कायम कर लेते हैं, जिस प्रकार के समाजवाद की बात बिरला और टाटाओं के नेतृत्व में होनी चाहिये—वही ये लोग कर रहे हैं। लेकिन जो दो-तिहाई मेहनत करने वाले हैं, जिनको दूसरे का कोई सहारा नहीं है, वह अभी भी बेज़मीन है, रहने को उसके पास घर नहीं है। अगर उसके पास अपनी ज़मीन नहीं होगी तो वह खाद कहां देगा, सिंचाई कहां करेगा, बिजली कहां लेगा—उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई मामूली मसला नहीं है, यह मसला बहुत संगीन हो गया है। आज हम देख रहे हैं कि मोरारजी भाई चिल्लाते हैं कि रिसेशन और इनफ्लेशन दोनों ही साथ हो गये हैं, एक तरफ़ देश में माल फाज़िल हो गया, इसलिये कारखाने बन्द हो गये हैं, माल की कमी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ़ महंगाई बढ़ रही है। जब किसी के मरने का वक्त आता है तो सर्दी और गरमी दोनों एक साथ चली आती हैं, इसलिये कांग्रेसी सरकार और इनकी पूंजीवादी व्यवस्था के लिए सर्दी और गर्मी दोनों एक साथ आ रही हैं। इसलिये आ रही है कि खरीदनेवालों का जो बहुमत होना चाहिये, उनके पास खरीदने की शक्ति नहीं रही है, खरीदने में समर्थ नहीं हैं, कारखानों का माल खरीद नहीं सकते हैं। करोड़पति लोग जो थोक बाजार और बैंकों के मालिक बन बैठे हैं, कम दामों पर बेचना नहीं चाहते, इसलिये

आज उनका सामान बिक नहीं रहा है—इस तरह से दोहरा संकट हमारी अर्थ व्यवस्था को—तबाह कर रहा है ।—उसके बाहर यह सरकार जाना नहीं चाहती है ।

जगजीवन राम जी जब खाद्यान्न मंत्री हुए, तो कुछ लोगों को यह भ्रम हुआ कि जिस तबके से आये हैं शायद एक-आध पैसा उसका ख्याल रखेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यह हाल है कि कोई भी आजाय, जैसे कुत्ते की दुम चाहे जितना प्रयास कर लो, सीधी नहीं हो सकती, वैसी ही इनकी स्थिति है, नतीजा यह है कि अभी भी जो खेतिहर हैं, उनको बसाने के लिये इस साल पैसा और कम कर दिया गया है । कम से कम इतना तो होना ही चाहिये कि उस के रहने के वास्ते घर हो ।

आज यह शिकायत आने लगी है कि गांव में जो मेहनत करने वाले हैं, खेत मजदूर हैं, वे वहां से भाग रहे हैं, आज वहां हमको आदमी नहीं मिलता है, क्योंकि उनके वहां पर रहने की व्यवस्था नहीं है । इसलिये प्रश्न यह है कि क्या प्रगतिशील भूमिसुधार करने की अभी भी आप में हिम्मत है ? महोदय, यह सवाल सिद्धान्त का नहीं है, हमारे देश की इस समय जो व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था है, उसको भी जिन्दा रखने के लिये यह भूमि सुधार जरूरी है। आज जैसा जापान ने किया है, जैसा हमारे दाहनी तरफ के सदस्य बात करते हैं—फारमूसा ने किया है, कम से कम उनकी ही नकल करो, उनसे कुछ सीखो । आज वहां 5-6 एकड़ से ज्यादा जमीन का मालिक कोई नहीं है, यदि आप ऐसी व्यवस्था करेंगे, तब ही बिजली, पानी, सहकारिता वगैरह का लाभ उनको मिल सकेगा ।

अभी भी उपाध्यक्ष महोदय, हम लोक सभा के सदस्य, बड़े बड़े सरकारी अफसर, दूसरे लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, न अपने बच्चों को मेहनत के लिये तैयार करते हैं, लेकिन जमीन खरीद कर वहां रखते हैं, हमारी संसद में ही बहुत सदस्य ऐसे हैं, जिनके पास बहुत जमीन है । वही लोग भूमि सुधारों के रास्ते में रुकावट डालने वाले यहां भी आते हैं और यह सरकार उनकी अगवानी करती है । ऐसी स्थिति में पैदावार बढ़ाना कैसे मुम्किन हो सकता ।

बीस साल से आचार्य विनोबा भावे चिलाते आ रहे हैं । गांधी जी ने भी कहा था कि जोतने वाले की जमीन होनी चाहिये । जय प्रकाश नारायण जी भी अपनी कमजोरी सी आवाज में कह रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी सर्वसम्मत कृषि नीति पर देश आश्रित हो । लेकिन जब तक इस में बुनियादी तौर पर और झटका दे कर हम कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं हिन्दुस्तान का आर्थिक ढांचा हिन्दुस्तान का कृषि का ढांचा जोकि चूर चूर हो रहा है, वह चूर होने से बच नहीं सकता है । आगे बढाने का कोई उपाय नहीं हो सकता है । जो मेहनत करने वाला है, जो खेती में काम करता है उसको आप जमीन का मालिक बनायें । जो खेती करता, जो बटाई पर काम करता है, उससे जमीन के छीने जाने का खतरा हमेशा बना रहता है । वह अपना सब कुछ खेती में लगा नहीं सकता है जब उसको डर बना रहता है कि उसकी जमीन उससे छीन ली जाएगी । वह हिम्मत नहीं कर सकता है इसके लिए । इस वास्ते मैं समझता हूँ कि बेदखली के खिलाफ गारंटी देना एक आवश्यक शर्त है खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए ।

सिंचाई का भी सवाल आता है । मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि राज्य मन्त्री ने यह बताया था कि पिछले दस साल में तेरह सौ करोड़ रुपया सिंचाई की मद पर खर्च हुआ है । लेकिन आप इसके मुकाबले में यह देखें कि विदेशी मुद्रा के रूप में विदेशों से बाजरा और गेहूँ मंगाने में हमें साढ़े पंद्रह सौ करोड़ रुपया खर्च करना पड़ा है । यह कितनी शर्मनाक चीज है । अपनी मिट्टी से गल्ला पैदा होगा और उसके

[श्री भोगेन्द्र झा]

लिए तो आपने दस साल में तेरह सौ करोड़ रुपया खर्च किया लेकिन विदेशी गेहूं, बाजरा आदि मंगाने पर आपने साढ़े पंद्रह सौ करोड़ रुपये खर्च किया । बाहर से जब हम अनाज मंगाते हैं तो देश की बदनामी होती है और तरह तरह की शर्तें भी लादी जाती हैं। यह हमारे स्वाभिमान पर चोट है। इधर वाले भी और उधर वाले भी इस में शर्म महसूस करते हैं कि बाहर से गल्ला मंगाया जाए। जो कार्य उनका रहा है वह कुमारी के गर्भ हो जाने जैसा रहा है जिससे उनको शर्म आती है। जो उपेक्षा उन्होंने खेती के बारे में दिखाई उसी का यह परिणाम है कि हम को यह दिन देखने को मिल रहे हैं। विरोध वाले तो यह कहते हैं कि पानी में डूब कर मर जायें। पिछले दस सालों में सिंचाई की मद पर अधिक खर्च न करके विदेशों से ही अन्न मंगाने पर जोर दिया गया है। लगातार हम अन्न बाहर से मंगाते आ रहे हैं । अब सरकार की मर्जी की बात नहीं रह गई है। पैदावार के लिए सिंचाई जारी है। उसके पहले भूमि सुधार जरूरी हैं। जो खेत में मेहनत करता है वह जमीन का मालिक बने। जो मेहनत नहीं करता है, जो जमीनदार है, जो स्वयं खेती नहीं करता है वह दूसरे कारोबार में पैसा लगाये और उसकी सरकार मदद करे, उसको सरकार सहूलियतें दे, छोटे, मझोले दर्जे के कारखाने लगाने में उसको सहूलियतें दें, बैंक से उसको पैसा दे। बैंक सरकार अपने हाथ में ले। जो खेती की देखभाल करता है, जो मेहनत करता है वह तभी ज्यादा बैंकों आदि से सहायता प्राप्त कर सकता है जबकि बैंक सरकार के हाथ में हो। लेकिन सब से पहली शर्त यह है कि वह जमीन का मालिक बने।

जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है इसकी गारन्टी दी जानी चाहिए कि पानी किसान को नियमित रूप से मिलता रहेगा। सिंचाई की सुविधाएं आपको सब से पहले देने का प्रबन्ध करना चाहिये। खेतों के नीचे वह दस पंद्रह हाथ की गहराई पर पानी मिल जाता है। ज्यादा तर जगहों पर वह मिल जाता है। अगल बगल में नदियां भी जा रही होती हैं। कहीं-कहीं इससे नीचे जाकर पानी मिलता है लेकिन आम तौर पर दस पंद्रह हाथ पर पानी मिल जाता है। यह जो पानी है इसका उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। इस में कोई विदेशी मुद्रा खर्च होने का सवाल नहीं है। और कामों के लिए हमारे वित्त मन्त्री कागज के नोट छाप लेंगे लेकिन इस काम के लिए वह ऐसा नहीं करेंगे। तब उन्हें मुद्रा प्रसार का भय न रहेगा। लेकिन सिंचाई के वास्ते जब पैसे की मांग की जाती है तो उसके पास पैसे की कमी हो जाती है। सिंचाई के लिए पैसा नहीं दिया जाता है। इसके स्पष्ट उदाहरण भी मिल चुके हैं। उत्तर बिहार की पश्चिमी कोसी नहर का मामला है। उससे तेरहा लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होगी। दस साल पहले उसका उद्घाटन हो गया है एक बार। फिर चार साल पहले हमारे भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने उसका उद्घाटन किया। उसके बाद फिर उसका तीसरी बार उद्घाटन हुआ। तीन बार उद्घाटन हो गया लेकिन अभी तक इसकी खुदाई का काम शुरु नहीं हुआ। बहुत हंगामा करने के बाद यह सरकार ने तय किया कि नेपाल और भारत के इंजीनियर लोग मिल कर उसका सर्वे करें। उसका सर्वे उन्होंने किया। जून में सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया नेपाल के अन्दर। हम लोग नेपाल गए थे। हमने नेपाल सरकार से इसके बारे में जानने की कोशिश की। हमने पूछा कि क्या आपने स्वीकृति भेज दी है। उन्होंने कहा कि हमारे यहां कागजात आए ही नहीं हैं। यहां सवाल पूछा तो जवाब मिला कि सर्वेक्षण का प्रतिवेदन पड़ा हुआ है। अभी तक यहां से नहीं गया है। आप देखिए कि इस में एक देश के साथ हमारा सम्बन्ध जो है, उसका भी सवाल पैदा होता है। साथ ही नेपाल और

भारत में इसके पानी से सिंचाई होगी। तीन बार उद्घाटन भी हो चुका है। लेकिन अभी तक उसकी शुरुआत ही नहीं हुई है। अभी तक रिपोर्ट ही आप के पास रखी हुई है। इस तरह की उपेक्षा वृत्ति से काम नहीं चलेगा। मैं कहूंगा कि जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको जेल में होना चाहिए। सिंचाई मन्त्री को जेल में होना चाहिये। जो हमारा पड़ोसी देश है, जो हमारा सहोदर है उससे हमारा रिश्ता बिगड़ जाए, इसकी आप को फिक्र ही नहीं है। सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता है, इसकी आपको फिक्र ही नहीं है। ये सोये हुए हैं। दस साल उद्घाटन हुए हो गए हैं। अभी तक कुछ किया ही नहीं गया है।

आप यह देखिये कि कीमतें खाद्यान्नों की कौन निर्धारित करता है? हम इस को देख चुके हैं कि जो नीतियां हैं वह मन्त्रि-मण्डल तैयार करता है, योजना मन्त्री तैयार नहीं करते हैं जो थोक बाजार के मालिक हैं, बैंकों के मालिक हैं वे हुक्म देते हैं और तब वे निर्धारित होती हैं। इसका सबूत हम चीनी के मामले में देख चुके हैं। चीनी मिल मालिक कह रहे थे कि हम निश्चित रूप से छूट ले लेंगे और खुले बाजार में चीनी बेचेंगे। हम लोग कहते थे कि यह असम्भव बात है। लेकिन अब हमने देखा लिया है कि चालीस प्रतिशत चीनी खुले बाजार में और जिस भाव पर वे बेचना चाहें, बेचने की उनको छूट मिल गई है। पांच छः रुपया और कहीं कहीं तो साढ़े छः रुपया किलो तक चीनी बाजार में बिक रही है। यह किस के लाभ के लिए किया गया है। उत्पादकों के लाभ के लिए किया गया है या ग्राहकों के लाभ के लिए किया गया है। क्या यह इसलिए किया गया है कि कांग्रेस ने चुनाव में इसको करने का वादा किया था? किसी वजह से नहीं हुआ है केवल मिल मालिकों के हुक्म पर यह बात हुई है।

आप देखें कि कितना ऊख का उत्पादन होता है। तीसरी योजना के अन्त तक का जो लक्ष्य था वह किसानों ने दूसरी योजना में पूरा कर दिया। तब केन्द्र में पाटिल साहब थे। उनका हुक्म गया कि ऊख की खेती कम करो, दस प्रतिशत उसको कम करो। किसान को दस प्रतिशत ऊख को जलाना पड़ गया, उसको आग लगानी पड़ गई। भारत रक्षा कानून का इस्तेमाल किया गया। कहा गया कि गुड़ नहीं बना सकते हैं। ऊख को आपको मिलों को देना होगा। अब आप देखें कि विश्व के बाजार में आज चीनी का मतलब है सोना, चीनी का मतलब है विदेशी मुद्रा। देश में चीनी की कमी है लेकिन आप चीनी को विदेशों में भेज रहे हैं लेकिन यह कमी पैदा क्यों हुई? इसी वास्ते हुई कि कृषि मन्त्री ने राज्य सरकारों को मजबूर किया कि वे ऊख की खेती को कम करें। तुलशी दास जी उस दिन हिचकते हिचकते कहने की कोशिश की थी लेकिन खुल कर नहीं कहा कि केन्द्रीय आदेश पर यह हुआ था। आज ऊख का संकट है। आज भी किसानों की ठगी चल रही है। अगर एक पैसा ऊख के दाम में बढ़ता है तो चीनी के दाम चार पैसे बढ़ा दिये जाते हैं। कहा यह जाता है कि किसान जो ऊख पैदा करता है चूंकि उस ऊख का दाम बढ़ गया है इस वास्ते चीनी का दाम भी बढ़ाना पड़ा है। इसके लिए किसान जिम्मेदार है, हम नहीं हैं। सब इस बात को जानते हैं कि जितने रुपये मन चीनी उतने आने मन ऊख। यह इसका नापतौल है। उपभोक्ताओं और उत्पादकों में आज कोई टकराव नहीं है। दाम अगर बढ़ते हैं तो सरकार की वजह से और मिल मालिकों की ओछी दृष्टि की वजह से बढ़ते हैं। मिल मलिक जो मुर्गी सोने का अंडा देती है उसी को खा जाना चाहते हैं। वे दूर दृष्टि नहीं रखते हैं। वे यह नहीं सोचते हैं कि किसान अगर अधिक पैदा करेगा तो मिलों को अधिक मुनाफा होगा, वे इसी बात को देखते हैं कि आज और आभी हमें कितना मुनाफा होगा

[श्री भोगेन्द्र झा]

भले ही कल को मिलें बन्द हो जायें। मिलों के बन्द होने का संकट पैदा हो भी गया है। अधिकतर चीनी मिलें बन्द हो रही हैं। कुछ आधी ताकत से काम कर रहीं हैं।

यही खाद्यान्नों की बात है। हर साल जब फसल मार्किट में आती है तो वह सस्ती होती है। दो चार महीने के बाद उसकी कीमतें डेढ़, दो और ढाई गुना बढ़ जाती हैं। यह किसान नहीं करता है। उस में ऐसा करने की ताकत नहीं है। जो बड़े किसान हैं जो हजार एकड़ वाले किसान हैं, जो मुनाफाखोरी भी करते हैं और सूदखोरी भी करते वह ऐसा करते हैं लेकिन उनकी तादाद हजार में से एक ही होगी, सौ में से भी एक नहीं। जो छोटे किसान हैं चूंकि उनको लगान अदा करना होता है, कपड़ा खरीदना होता है या दूसरी जरूरतें पूरी करनी होती है इसलिए वे गल्ला ला कर व्यापारियों को बेच देते हैं। जब गल्ला थोक व्यापारियों के हाथ में चला जाता है तो वे बैंकों के पैसे के बल पर दुगुने, ढाई गुने दामों पर उसको बेचते हैं। यह जो खाद्य निगम है यह मुझे लगता है कि उन्हीं थोक व्यापारियों के हाथ का एक खिलौना बन चुका है। यह दाम बढ़ाने में मददगार बनता है। यह निगम उनके हितों के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से मालूम पड़ता है कि असमर्थ है। इसके जो प्रमुख लोग हैं वे उन्हीं के इशारे पर काम करते मालूम पड़ते हैं। दुहरी टक्कर किसान की होती है। उसका जो माल होता है, अनाज होता है, कपास आदि होते हैं वे सस्ते दामों पर बिक जाते हैं लेकिन जब सामान उसको खरीदना पड़ता है, कपड़ा है या उसके खाने की दूसरी चीजें हैं वे उसको बहुत ऊंचे दामों पर मिलती हैं। उत्पादन के रूप में भी और उपभोक्ता के रूप में भी, दोनों ही रूपों में उसकी लूट जारी है। उसकी लूट बन्द हो, यह बहुत जरूरी है।

इस वास्ते मैं बुनियादी सवाल उठाना चाहता हूं। क्या सरकार हिम्मत करके थोक व्यापार को अपने हाथ में लेगी? अगर सरकार ने इसके पक्ष में निर्णय किया तो उस हालत में देश में जो अलग अलग बन्धन लागू किये गये हैं, कोठियां बनी हैं उनको हम तोड़ सकते हैं। आप सारा खाद्यान्नों का थोक व्यापार अपने हाथ में लें और तब राज्यों में उसका बटवारा हो ताकि देश एक इकाई के रूप में बना रह सके। इसके बगैर यह जो लूट है वह बढ़ती ही जाएगी। यही कारण है कि राज्यों में अन्न के मामले को ले कर विरोध पैदा होता है। इसी संदर्भ में राजनीति के लिए अन्न के इस्तेमाल का सवाल भी उठता है। सरकार कहती है कि वह अन्न का राजनीतिक लाभ के रूप में इस्तेमाल नहीं करती है। लेकिन इस बार इसका सबूत मिल गया है और मालूम पड़ता है कि सरकार पकड़ी गई है। केरल, बंगाल, बिहार आदि सभी राज्यों से अन्न को ले कर आपके पास शिकायतें आती रही हैं। अभी बंगाल में चावल का संकट था। उनके पास चावल नहीं था। अब एक कठपुतली को वहां पर कायम कर दिया गया है। उस व्यक्ति से मुझे कोई शिकायत नहीं है। उस बेचारे के माथे पर हमेशा ऐसा भार पड़ता है। 1940 में जब इन्हीं नेताओं ने यह तय किया था कि बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी को भंग कर दिया जाये और सुभाष बोस को निकाल दिया जाये, तो इन्हीं श्री पी० सी० घोष पर बंगाल कांग्रेस की एडहाक कमेटी का भार डाला गया था। आज उन्हीं के नेतृत्व में बंगाल में एक एडहाक सरकार कायम कर दी गई है।

इस नये मन्त्रि-मण्डल को सत्ता देने के बाद बंगाल में प्रति-सप्ताह सौ ग्राम चावल बढ़ा दिया गया है। प्रश्न यह है कि यह चावल कहां से आ गया। कार्तिक महीना चावल के लिए साल का आखिरी महीना होता है। वह घाटे का महीना होता है। ऐसे समय में यह फ़ालतू सौ ग्राम जावल कहां से आ गया?

यह स्पष्ट है कि पश्चिमी बंगाल के माथे पर जो कठपुतली सरकार बिठा दी गई है, वहां की जनता को उसे स्वीकार करने के लिए यह घूस दी गई है कि उन के लिए सौ ग्राम प्रति-सप्ताह चावल की वृद्धि कर दी गई है। इस सरकार के पास केरल के लिए चावल नहीं है, जहां ज्यादा संकट है। यह सरकार पश्चिमी बंगाल के लोगों को राजनीतिक घूस देने की कोशिश कर रही है।

चूंकि बिहार में इन लोगों की मर्जी की सरकार नहीं है, इसलिए ये बिहार के लोगों को बाजरा खाने के लिए कहते हैं । श्री जगजीवन राम ने कहा है कि लोग जो चीज खाने के आदी हैं, हम उस का ख़याल करते हैं। वह जानते हैं कि बिहार के लोग बाजरा खाने के आदी नहीं हैं । लेकिन फिर भी बिहार को जो खाद्यान्न दिया गया है, उस का तीन-चौथाई बाजरे के रूप में है।

एक माननीय सदस्य न हमें पूछा कि आप अपने राज्यों में क्या करते हैं। मैं उन को बताना चाहता हूं कि उड़ीसा और बिहार की सरकारों ने लगान माफ़ कर दिया है। लेकिन वित्त मन्त्री, श्री मोरारजी देसाई, इस बारे में दिल्ली में ही बोल कर संतुष्ट नहीं हुए। वह दौड़ कर पटना गए और वहां पर कहा कि अगर बिहार की सरकार किसान का लगान माफ़ करेगी, तो केन्द्रीय सरकार इस घाटे को पूरा नहीं करेगी। लेकिन आज बिहार में कोई हिजड़ों की सरकार नहीं है। वे लोग अड़ गए और उन्होंने कहा कि हम श्री मोरारजी देसाई के हुक्म से किसान का गला नहीं काटेंगे। लेकिन तथ्य यह है कि ये लोग तो हुक्म देने से बाज़ नहीं आए।

श्री जगजीवनराम ने इसी सदन में बताया था कि दाल का व्यापारी लाखों मन दाल हावड़ा जंक्शन पर रखे हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि बंगाल सरकार से मश्वरा कर रहे हैं और हम ने उन को राय दी है कि वे उस दाल को जब्त कर के उस को बांटने का इन्तज़ाम करें। हालांकि बंगाल में दाल का संकट है, लेकिन चूंकि वहां पर इन लोगों की मर्जी की सरकार नहीं थी, इसलिए हावड़ा जंक्शन पर जो दाल के डिब्बे भरे हुए थे, उनको तुड़वाकर उस दालके वितरण की कोई व्यवस्था नहीं की गई। मेरे पास तीन छोटे व्यापारियों की चिट्ठियां आई हैं कि हावड़ा जंक्शन पर दाल से भरे डिब्बे पड़े हुए हैं, इस लिए उन के सामान के लिए जगह नहीं मिल रही है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने उस व्यापारी को, अग्रवाल को, जेल में रखा हुआ था। यहां से हुक्म गया कि बंगाल माने या न माने, विधान सभा माने या न माने, पी० सी० घोष को मुख्य मन्त्री बनाया जाये। गवर्नर के हुक्म से अग्रवाल को रिहा कर दिया गया और उस कठपुतली सरकार के शपथग्रहण के समय अग्रवाल वहां पर मौजूद था।

जइस स्थिति में क्या सरकार समझती है कि देश और सदन इस बात पर विश्वास करेंगे कि यह सरकार अपनी खाद्य-नीति का निर्धारण सारे राष्ट्र के हित में करता है, न कि किसी वर्ग-विशेष के हित में? कुछ माननीय सदस्यों ने व्यक्तिगत सम्मति का ज़िक्र किया है। जो व्यक्तिगत सम्मति यहां के मेहनतकशों और किसानों के पास है, सरकार उस का सर्वनाश कर रही है, ताकि कुछ थोड़े से लोग करोड़ से अरब और अरब से खरब बना पायें। यह सरकार थोड़े से पूंजीपतियों के हितों की रक्षा के लिए सारे देश को कुरबान करना चाहती है। आज छोटे मझोले किसान और अधिकांश खुशहाल किसान भी तबाह किये जा रहे हैं। इस सरकार को शहरों के मजदूरों की कोई फ़िक्र नहीं है। आज प्रश्न यह है कि क्या इस सरकार में कोई मौलिक परिवर्तन करने का हिम्मत है या नहीं।

आज हमारा देश चौराहे पर आ गया है। उस की स्थिति संकटपूर्ण है और वह आगे

[श्री भोगेन्द्र झा]

नहीं जा सकता है। कारखानों के माल की खपत के लिए किसानों के पास पैसा चाहिए। आज आवश्यकता यह है कि देश का अन्दरूनी बाजार फैले, लोगों की क्रय-शक्ति में वृद्धि हो, विदेशों से अन्न मंगाना बन्द हो और देश में भुखमरी बन्द हो। आज हमारे देश में एक विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई है, जिस का निराकरण करने के लिए सरकार को अपनी नीति में मौलिक परिवर्तन करना होगा। वह मौलिक परिवर्तन करने के लिए उस को बैंक मालिकों के खिलाफ जाकर बैंकों को राष्ट्रीकरण करना होगा, खाद्यान्नों के थोक-व्यापार का राष्ट्रीयकरण करना होगा, करोड़पतियों के खिलाफ जाना होगा और उन लोगों के भी खिलाफ जाना होगा, जो ट्रेजरी बैंचिज पर बैठ कर उन के इशारे पर सरकारी नीतियों को चलाते हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Sheo Narain.

On this side, I will request the hon. Members not to exceed the limit of ten minutes; then only, I can try to accommodate more members.

श्री शिवनारायण : (बस्ती) उपाध्यक्ष महोदय, ग़रीबों को मिले रोटी, तो मेरी जान सस्ती है, यह नारा इस देश में **राजगुरु, सुखदेव और भगतसिंह ने दिया था**.... **(व्यवधान)** मैं जानता हूं कि ये जनसंघ के आदमी हैं। मैं जानता हूं कि वे किस भाषा में बोल रहे हैं।

मैं किसान का बेटा हूं और खुद किसान हूं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह सबसे पहले अपनी तरफ़ से, किसी बनिये या ब्लैक-मार्केटियर के द्वारा नहीं, मध्यम ग़रीब किसान को कर्ज़ा देने की व्यवस्था करे। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि वह इस काम को अपने जिम्मे ले कि किसानों को स्टेट बैंक से क़र्ज़ा दिया जाये, ताकि हम अपनी खेती में सुधार कर सकें।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाये। मैं इस गवर्नमेंट से पुरज़ोर अपील करता हूं कि इस नपुंसकता की नीति को खत्म किया जाये। उधर से श्री राममूर्ति खड़े हो कर हमारे चीफ़ मिनिस्टर को शिखंडी कहते हैं। उन को बता देना चाहिए कि यह सरकार शिखंडियों की सरकार नहीं है, बल्कि अर्जुन और भीम की औलाद है, गांधी के त्याग और तपस्या की उत्तराधिकारी है।

नौ दस महिनों में ही बंगाल और दूसरे प्रदेशों में इन विरोधी दलों की कलई खुल गयी है। चरणसिंह की भी खुलने वाली है। उत्तर प्रदेश में जब श्रीमती कृपालानी चीफ-मिनिस्टर थीं, तो हमको अपने खेत के लिए ट्यूबवेल लगाने की फ्रीडम थीं, लेकिन आज हमको दस हजार रुपया देना पड़ता है। मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में उन के 94 मेम्बर हैं। वहां पर उन का डामिनेंस है। आज हम पर यह प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है कि दस हजार रुपया दो तो ट्यूबवल लग सकता है हमारे खेतों में। वहां पर आज यह हालत है।

जब यह गवर्नमेंट किसी मामले में हमारी मदद नहीं कर सकती है, तो वह गन्ने के मामले में क्यों इन्टरफ़ियर करती है, जब कि एग्री-कल्चर का सबजेक्ट स्टेट का है, सेंटर का नहीं।

जहां तक बैंकों के राष्ट्रीयकरण का सम्बन्ध है, मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी कहा था कि पंडित जी, यह काम आप अपनी ज़िन्दगी में कर जाओ, आप से बड़ा आदमी देश में नहीं है! अगर आप ने यह काम नहीं किया, तो फिर इस में बहुत कठिनाई होगी। आज इन पूंजीपतियों की जेब में हमारा देश है। आज हमारे लीडरों को गालियां दी जाती हैं कि वे ब्लैक-मार्केटियर्ज के पैसे से यहां आए हैं। मैं मद्रास से लौट कर आया हूं। मुझे विश्वस्त सूत्र से पता चला है कि वहां पर एक एक्स एम० एल० ए० ने इलेक्शन

में चालीस, पचास हजार रुपया तक खर्च किया है।

मैं जानता हूं कि सामने के कुछ एक कम्युनिस्ट ही बैंकों के राष्ट्रीयकरण से सहमत होंगे। बाकी लोग तो सब बैंकों के दोस्त हैं। यह कांग्रेस वाला बोल रहा है, कम्युनिस्ट नहीं बोल रहा है। ग़रीब किसान का बेटा बोल रहा है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाये। (**व्यवधान**) मैं जानता हूं कि जनसंघ का पैसा इन को बुलवा रहा है।

मैं सरकार से यह भी कहना चाहता हूं कि किसानों की फसलों का बीमा किया जाये। जब बड़े बड़े अफ़सरों की तनख्वाहें सुरक्षित रहती हैं, जब सब दूसरी चीजों का बीमा होता है, तो फिर किसानों की फ़सलों का बीमा कर के उन की सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं की जानी चाहिए।

जेनेरल इन्शोरेंस का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। सरकार को सस्ते अनाज की नीति को त्यागना चाहिए और किसानों को अच्छी कीमत देने की व्यवस्था करनी चाहिए। हमको अनाज का आयात बन्द कर देना चाहिए और बैगिंग बाउल लेकर संसार भर में भीख नहीं मांगते फिरना चाहिए। "मेरी नाक कटी तो कटी, पर अपनी नाक बचा लेना," शूर्पनखा ने रावण को यह कहा था। स्वयं बिड़ला के एक आदमी ने मुझसे कहा था कि इस देश में अनाज की कमी नहीं है। पंजाब में अनाज पड़ा पड़ा सड़ गया, लेकिन किस ने उस को रोका ?

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस ने।

श्री शिवनारायण : नहीं, टाटा, बिड़ला और कैपिटलिस्टों की औलाद जो बड़े-बड़े अफ़सरान हैं, यह उन के हाथ में है। वे गाड़ियां नहीं चलने देते हैं। हमारे एक्स-होम मिनिस्टर, श्री गुलजारीलाल नन्दा, ने कहा था कि मैं इस मुल्क से करप्शन को वाइप आउट कर दूंगा। तब इन सभी ने मिल कर उन की टांगें खींचीं।

आप सबने मिल कर खींचा और बड़ी गालियां दीं .....

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन) : इन्दिरा गांधी ने खींचा .....

श्री शिवनारायण : चुप रहो।

श्रीमती लक्ष्मी कांतम्मा (खम्मम) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। .... (**व्यवधान**)

श्री शिवनारायण : श्रीमन्, यह क्या है ...

MR. DEPUTY-SPEAKER : Yesterday, you raised a point of order. I had to listen to you. So I have to listen to her.

श्रीमती लक्ष्मी कांतम्मा: उपाध्यक्ष महोदय, क्या एक मेम्बर दूसरे मेम्बर को चुप रहो कह सकता है ?

श्री शिवनारायण : उपाध्यक्ष महोदय, क्या इन्तजामकार हैं यह लोग ? मान्यवर, मेरी नाक कटती है और हिन्दुस्तान के बड़े से बड़े पूंजीपति की भी नाक कटती है फारेन में। हम किसान के घर के हैं। जब हम गोसैयां के यहां जाते हैं, शुकुल के यहां कि हुजूर दो मन गेहूं दे दो, तो कहते हैं कल आना, परसों आना। यह अटल बिहारी वाजपेयी और इन के आका यह कहते हैं कि कल आना, परसों आना। तब दे दिया दो मन और सूद समेत, सवाई समेत, वह हम ने लौटा दिया। लेकिन उस के बदले भादों महीने में आएंगे, कहेंगे, चल सारे, खेत निरवा, चल सारे, खेत जोत। यह कहते हैं उस सद के एवज में। तो यों ही हमारी नाक कटती है अमेरिका से गेहूं मांगने में। लेकिन यह और उलटे हम को गालियां देते हैं। हम भीख मांग कर के ला रहे हैं और यह बंगाल वाले चिल्लाते हैं कि हम को चावल दो। जब तुम इतने नालायक हो हुकूमत नहीं चला सकते, अपने स्टेट का इंतजाम नहीं कर सकते .... (**व्यवधान**) .....जी, वह गवर्नमेंट नालायक है जो अपने लोगों को नहीं खिला सकती है। वह निकम्मे लोग बैठे हैं उत्तर प्रदेश में। आज वह निकम्मे वहां बैठे हैं .....(**व्यवधान**)..... जिन को निकालना है वह निकल रहे हैं।

[श्री शिवनारायण] :

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा प्वाइंट कह रहा हूं। नये बोझ न लादिए ····· **(व्यवधान)** ·····इनको जरा आप कंट्रोल करें श्रीमन् मैं कह यह रहा हूं हुजूर, किसान पर नये बोझ न लादते जाइए जैसे इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, वाटर रेट, महंगी बिजली वगैरह और खाद की सब्सिडी वापस न ली जाए जो आप दे रहे थे। हुजूर, यह नये नये टैक्स लाते हैं····· **(व्यवधान)** ·····मैं किसी को गाली देने नहीं आया हूं ····· **(व्यवधान)**

Sir, what are they doing. You must control them.

MK. DEPUTY-SPEAKER : You must address the Chair. Please conclude.

श्री शिवनारायण : तो मैं हुजूर से बात कर रहा हूं। यह टैक्सेशन कोई न हो, मैं कहना चाहता हूं नो गवर्नमेंट विदाउट टैक्सेशन·····

एक माननीय सदस्य : हिन्दी में बोलो।

श्री शिवनारायण : अरे हिन्दी वालो, मालूम है तुम्हारा हिन्दी-प्रेम।

उपाध्यक्ष महोदय, यह टैक्सेशन जरूरी है, नो गवर्नमेंट विदाउट टैक्सेशन। कोई भी सरकार बिना कर के चल नहीं सकती। मैं ने जगजीवन बाबू को आज आश्वासन दिया पार्टी मीटिंग में कि आप जितना भी कानून बनाओगे, हम टैक्स देंगे, हम आप को लगान देंगे। लेकिन जब एक मन गन्ने की चीनी पौने चार सेर होती है जिस की कीमत २४ रुपये होती है तो उस २४ रुपये में से १२ रुपये हम को दो तुम हम से चार रुपये ले लो। एक मन पर हम चार रुपये देंगे। लेकिन हुजूर वह बेनिफिट हम को भी तो जाय, किसान के घर भी तो वह बेनिफिट जाय। बस, हुजूर दो मिनट। खत्म कर रहा हूं।

एक अभी चंद प्यारे लाल का कोटेशन देना चाहता हूं। उनकी एक रिक्वेस्ट के ऊपर, उनका एक आदमी आया फूड मिनिस्टर के पास और कहा, हुजूर माफी चाहता हूं इसी पर 95 लाख उन का माफ हो गया। एक आदमी की रिक्वेस्ट पर 95 लाख माफ। 95 लाख मीन्स सवा छः एकड़ का लगान उत्तर प्रदेश में कुल एक करोड़ नहीं होता है। मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं, तुम से ज्यादा सख्त सवाल पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि इन गरीब किसानों को क्यों नहीं माफ करते हैं ? बजाय मालगुजारी और लगान माफ करने के आप तो यहां उलटा टैक्स हमारे ऊपर धरते हैं। मैं इस सरकार को आश्वासन देता हूं कि अगर यह सरकार न्याय करेगी तो यह सरकार बनी हुई है किसानों के बल पर और किसान भी अब जागा है। जय जवान जय किसान का नारा हमारे प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। उनकी आत्मा को शांति मिले। उन्होंने हम किसानों को जगाया। किसान आज जागा हुआ है। किसान कमाता है। अन्न की कमी नहीं है। मैं फूड मिनिस्टर को विश्वास दिलाता हूं और भगवान इन्द्र ने बड़ी कृपा की। पानी बरसाया है। इन्दिरा गांधी का इकबाल काम कर रहा है, जगजीवन राम का इकबाल काम कर रहा है। बाबू जगजीवन राम ने अश्योरेंस दिया है कि हम गुड़ पेलने देंगे किसान को, बाबूजी, आप की आयु दस वर्ष और बढ़ेगी। किसान आप को धन्यवाद देगा कि उस का गुड़ बिकेगा ·····**(व्यवधान)**·····

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन चंद शब्दों के साथ इस गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि किसानों को इग्नोर न करो। ८० प्रतिशत आदमी इस देश का किसान है। जोड़ी बैल पर हम जीत कर आये हैं। यह जोड़ी बैल वाली गवर्नमेंट यहां बैठी है। कैपिटलिस्टों की गवर्नमेंट नहीं है। इन चन्द शब्दों के साथ मैं फिर फूड मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि फूड पालिसी में कोई वह घबड़ायें नहीं। किसान आप के पीछे खड़ा है और वह आप को अनाज देगा और चीनी भी देगा। लेकिन इन ब्लैकमार्केटियर्स और चोरों को आप बन्द करो। इन ब्लैक-

मार्केटियर्स को आप जेल भेजो, यही हमारी मांग है ।

श्री शारदानंद (सीतापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य स्थिति पर विचार करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अभी हमारे शिव-नारायण भाई और उस से पहले रणधीर सिंह आदि ने यहां पर बहुत बड़े बड़े भाषण दिए । उन से उन्होंने अपने को तो धोखा दिया ही साथ-साथ किसानों को भी धोखा दिया है । वह मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां पर जब किसानों का गला घोंटने वाला कोई बिल आता है तो यही लोग उस बिल को पास करने में अपना हाथ उठाते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश की खाद्य स्थिति 20 सालों के बाद भी सुधरी नहीं है । आज कहा यह जा रहा है कि सन् 71 तक हम इस खाद्य स्थिति पर विजय प्राप्त कर लेंगे और हमारा देश आत्मनिर्भर हो जायगा । मुझे पता नहीं है कि स्थिति कब सुधरने वाली है और कैसे इस प्रकार की बात हम लोगों के सामने कही गई है । मैं तो कहता हूं कि आज 20 सालों में इस हुकूमत ने जो भी नये नये प्रयोगों के नारे दिए हैं उन के कारण आज किसान असमंजस में पड़ गया है । वह शंका की दृष्टि से सब कुछ देखता है और उसी के कारण आज यह उत्पादन नहीं बढ़ रहा है । सब से पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि किसान आशंकित कब से हुआ है जब से इन्होंने सहकारी खेती का नारा दिया कि को-आपरेटिव फार्मिंग होगी । इस देश का किसान नहीं चाहता है कि हमारा खेत हम से छीन लिया जाय । किसान नहीं चाहता है कि इस प्रकार का कोई नारा और हमारे सामने लाया जाय । इसलिए किसान सशंकित हो गया है कि सहकारी खेती के इस नारे से । इस के बाद, आज देश को पानी की अधिक आवश्यकता है, उस के बाद बीज आता है, खाद आती है, और अन्य बातें आती हैं लेकिन सब से पहली मांग पानी की है । आज खेती को पानी की आवश्यकता है । सरकार में बैठने वाले लोग भी इस बात को महसूस कर रहे हैं और इधर के बैठने वाले भी महसूस कर रहे हैं । किसान भी आज महसूस कर रहा है । मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह जो थोड़ी बहुत वर्षा हो गई है जिस के कारण आज हम को कुछ राहत मिली है इस पर हम को निर्भर नहीं रहना चाहिए क्योंकि आज बीस सालों के बाद भी हमारे खेतों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाया है । जब तक पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा तब तक हमारे देश की खाद्य स्थिति सुधर नहीं सकती । मैं कहना चाहूंगा कि आज नहरों के द्वारा काश्त-कार को थोड़ा पानी मिलता है, ट्यूबवैल कुछ लगाए गए हैं, उन से कुछ पानी मिलता है लेकिन उस पानी की कीमत किसान को इतनी अधिक देनी पड़ रही है कि जिस के कारण किसान जितना पानी लेना चाहिए उतना नहीं ले पाता ।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि आज सिंचाई की जो छोटी-छोटी योजनायें हैं, सरकार को उन्हें प्राथमिकता देनी होगी । आज जिस प्रकार से नहरों की गारन्टी है, उसी प्रकार से कुओं, तालाबों और पोखरों के द्वारा पानी देने की सरकार गारन्टी दे कि इन के द्वारा हम काश्तकारों की खेती को पानी मुहिया करेंगे । इस प्रकार की एक योजना देश में बननी चाहिए कि हर किसान को, जहां पर उसकी खेती है, वहां पर अगर वह खुद कुंआ बना सकता है, रेहट लगा सकता है, ट्यूबवैल लगा सकता है, तो लगाये, यदि वह नहीं कर सकता है तो सरकार इस का इन्तजाम करेगी ।

15 hrs.

आज खाद के विषय में बहुत बातें की जा रही हैं —उर्वरक के कारखाने लगेंगे, यहां कारखाना लग रहा है, वहां कारखाना लग रहा है और इस प्रकार उर्वरक के सम्बन्ध में सरकार के सामने जो योजना है, जिस के द्वारा वे समझते हैं कि हम देश की खाद समस्या को हल कर सकेंगे, मैं कहना चाहता हूं कि

[श्री शारदानंद]

हमारे यहां की जलवायु उन खादों के लिये वैसी उपयोगी नहीं है, जैसी कि बाहर के देशों में है, ठण्डे देशों में है। हमारे देश में जब तक पानी अधिक नहीं होगा, तब तक इन खादों का ज्यादा प्रयोग हमारे और इस देश के लिये अहितकारक होगा, इस से हमारी खेती को नुक्सान पहुंचेगा। आज किसानों को हमारे देश के अन्दर जो उपलब्ध खाद है, हरी कम्पोस्ट खाद है, उसकी तरफ प्रोत्साहित करना चाहिये, जिस के द्वारा बहुत कुछ आज हम कर सकते हैं। लेकिन इस को आज हम नज़रअन्दाज़ कर रहे हैं, इस की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है और फर्टिलाइजर-फर्टिलाइजर का नारा दे कर हम किसानों को उस के पीछे दौड़ाना चाहते हैं और इस प्रकार जो उस के पास उपलब्ध खाद है, गोबर की खाद है, उस की कमी हमारे देश में होती चली जा रही है।

आज किसानों को अच्छा बीज नहीं मिल रहा है। आपके कृषि भण्डारों से जिनको कृषि विभाग द्वारा चलाया जाता है, वहां तो कुछ अच्छा बीज मिलता है, लेकिन अन्य जो साधन हैं किसानों को बीज देने के, वे ठीक नहीं हैं। वहां से उनको अच्छा बीज नहीं मिल रहा है। इस की व्यवस्था हम को करनी चाहिये ताकि हम को अच्छा बीज मिल सके। अच्छा बीज जब आप हम को देंगे, उससे अच्छी पैदावार होगी।

आज जिस प्रकार से—जैसा मैंने पहले कहा— आपने सहकारी खेती का नारा दिया और जिस के कारण किसानों के दिमाग में तरह-तरह की बातें पैदा हुईं, उसी तरह से जब किसान पैदा करता है तो उस के खेतों और खलिहानों से लैवी वसूल करते हैं — यह गलत बात है। आज हम को इस प्रकार से करना चाहिये कि फूड कार-पोरेशन की स्थापना गांव-गांव में की जाय, हर एक गांव सभा में इस की स्थापना हो और वह फूड कारपोरेशन किसानों के अन्न की खरीद करे ताकि किसानों को उचित मूल्य मिल सके। मेरी यह मांग है कि आप इस प्रकार की व्यवस्था करें।

आपने जो जोनल सिस्टम बना रखा है, यह जोनल सिस्टम समाप्त होना चाहिये। आज देश के एक कोने में बैठा हुआ आदमी तो खा रहा है, लेकिन दूसरे कोने में बैठा हुआ आदमी भूखा मर रहा है। एक तरफ अन्न सड़ रहा है, दूसरी तरफ लोग भूखों मर रहे हैं। यह स्थिति ज्यादा दिनों तक नहीं चलाई जा सकती। हमारे खाद्य मंत्री ने अभी कुछ दिन हुए इसी सदन में कहा था कि हम इस सिस्टम को खत्म करने वाले नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अब वह दिन आ गया है— आज नहीं, तो कल आपको यह करना ही होगा। क्योंकि आज सारे देश की यह मांग है, केवल इधर बैठने वाले लोगों की ही मांग नहीं है, बल्कि उधर बैठने वाले अधिकांश लोगों की मांग है कि ये जोनल सिस्टम समाप्त किये जाएं।

आज हमारे देश में गन्ने की जो हालत है, चीनी की जो हालत है, चीनी के उत्पादन की जो समस्या है, वह विकट रूप धारण कर रही है। इसका कारण यह है कि सरकार ने इन सालों में कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। आज हालत यह हो गई है कि हमारे देश में चीनी का पर्याप्त उत्पादन नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि सन् 1965 में हमारे देश में 32 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था और खपत 28 लाख टन हुई, कुछ चीनी हमारे पास बढ़ी, और उस बढ़ी हुई चीनी को बेच कर हम ने 17-18 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा कमाई। उस के बाद दूसरे ही साल यह हालत हुई कि हमारा उत्पादन 32 लाख टन से घट कर 21 लाख टन हो गया। उसी समय सरकार को सोचना चाहिए था कि इस का क्या कारण है और इस के लिये कोई योजना बनानी चाहिये थी। आज तक आप ने हम को, काश्तकारों को, चंगुल में

फंसाये रखा, पैदा हम करते हैं, भाव आप तय करते हैं और आज यह स्थिति है कि हम पैदा करते हैं और हम को मिल मालिकों की दया पर छोड़ दिया गया है, वे हम को जो चाहें भाव दें। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस समय आपने यह योजना बनाई थी, उस समय आपने क्या तय किया था, ये मिल मालिक किसानों को कितना पैसा देंगे और क्या भाव मिल मालिक शुगर का रखेंगे ? इस का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि आपने कोई योजना नहीं बनाई है। ऋशर पर आपने जो पाबन्दी लगा दी है कि 22 दिसम्बर के बाद चलेंगे—मैं जानना चाहता हूं कि आपने यह पाबन्दी क्यों लगाई है। अगर आप काश्तकार के हमदर्द थे, तो आप ऐसी पाबन्दी नहीं लगाते, लेकिन आप काश्तकार के हमदर्द नहीं हैं, इसीलिए पाबन्दी लगाई है, क्योंकि यदि शुरू से ही आपने ऋशर को चलने दिया होता तो आज ऋशर और मिल मालिकों के कम्पीटीशन में किसान को ज्यादा पैसा मिल सकता था, लेकिन आपने उस कम्पीटीशन को नहीं होने दिया। आप किस के हमदर्द बनते हैं। आप इस प्रकार की योजनायें बनाते हैं, जिसमें किसानों का गला घोटा जाता है।

उत्तर प्रदेश चीनी के विषय में सब से बड़ा उत्पादक प्रदेश था—लेकिन आज वहां क्या हालत है। आज वहां पर गन्ना मिलें बन्द हो रही हैं। कारण क्या है ? कारण यह है कि आप ने कभी भी किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया। जिस समय गन्ने का उत्पादन कम होना शुरू हुआ था, आपको उसी समय विचार करना चाहिये था कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज किसानों के गन्ने की कीमत आप पौने तीन रु० तय करते हैं, क्यों तय करते हैं? आपको याद होना चाहिये जब रफी अहमद किदवई साहब ने इस विभाग को अपने हाथ में लिया था, उन्होंने कहा था कि जितने रुपये मन शुगर होगी, उतने आने मन गन्ने की कीमत होगी। आपने उस बात का ख्याल क्यों नहीं किया, आप को उसी समय सोचना चाहिये था। आज आप सोचने बैठे हैं कि किसान को कुछ मिल जाये—इसी लिये हम ने 40 परसेंट की छूट कर दी है। 40 परसेन्ट की छूट तो आप ने दी है, पर शक्कर का भाव आज क्या है—क्या इसकी भी आपने चिन्ता की है। आज उपभोक्ता और किसान को आप लड़ाना चाहते हैं — यह बात ठीक नहीं है। जिस समय गन्ने का उत्पादन कम होना शुरू हुआ था, उसी समय आप को चाहिये था कि गन्ने की कीमत बढ़ाते। आज जो मांग है कि गन्ने की कीमत 5 रु० मन की जाय, किसान आज आशंकित है कि इस समय तो ऋशर और मिल मालिकों में कम्पीटीशन है, इस लिये हम को यह भाव मिल रहा है, अगर इसके बाद हमने गन्ना पैदा किया तो क्या गारन्टी है कि यही पैसा मिलेगा। आज उस को इस बात की कोई गारन्टी नहीं है, इस लिये सरकार को उसे गारन्टी देनी चाहिये कि किसानों का भाव उतना ही रहेगा। आप भावों को निर्धारित कीजिये और वे सारे देश में एक से होने चाहियें। अभी तक यह होता था कि दक्षिण के जो किसान हैं, उनको ढाई हजार रु० प्रति एकड़ आता था, जब कि यहां के किसानों को 400–500 रु० प्रति एकड़ आता था—आज इस प्रकार की दो तरह की नीति को आपको समाप्त करना चाहिये और आपको किसानों को आश्वासन देना होगा कि गन्ने का यह जो भाव है, वह हमेशा आगे रहेगा।

हमारे उत्तर प्रदेश में और जो पुस्तिका आपने हम को दी है उस को देखने के पश्चात् हम ने यह देखा कि छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये आपने 510 करोड़ रुपये के लगभग दिया है, लेकिन जो माध्यम योजनायें हैं, उस के लिये आपने एक भी पैसा नहीं दिया है। मैं आप को बताना चाहता हूं कि आपकी एक योजना थी, जिस पर काम भी शुरू हो चुका था और जिस के द्वारा लाखों एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश की सींची जाती, आज

[श्री शारदानंद]

उस योजना को आपने ठप्प कर दिया है। वहां पर काम शुरू हो गया था, वहां पर क्वार्टर्स बन गये थे कुछ थोड़ा बहुत काम भी हुआ — वह क्या योजना थी ? वह पंचेश्वर की योजना थी। अगर यह पंचेश्वर की योजना पूरी हो जाती तो आज शारदा सागर, जिसमें 10 हजार फिट पानी रोकने की व्यवस्था है, उस की कैपैसिटी 10 हजार फिट से बढ़ कर 30 हजार फिट हो जाती। इस योजना के पूरा होने से हमारे प्रदेश को पानी मिलता और लाखों एकड़ जमीन में सिंचाई होती। अभी हमारे भाई शिवनारायण जी कह रहे थे कि बिजली नहीं मिलती, बिजली मिलती है तो उस के लिये हम को इतना रुपया देना पड़ता है। मैं उन से कहना चाहता हूं कि वे जरा अपनी सरकार से पूछें कि चौथी पंच वर्षीय योजना के भी दो साल समाप्त हो रहे हैं, उसके बाद भी उनकी योजना की रूप रेखा नहीं बन पाई है—इसका क्या कारण है। इस प्रकार यदि आप सब सरकारों को फेल करना चाहेंगे, एक तरफ आप इस तरह की बातें करते हैं और दूसरी तरफ इन योजनाओं की तरफ ध्यान नहीं देते हैं जिनके द्वारा हमारे देश को, हमारे प्रदेश का भला होने वाला है।

एक चीज और कह कर समाप्त करूंगा और वह यह है कि मैं आपको चेतावनी देता हूं कि आज हमारे जो किसान हैं, उन के अन्दर वह ताकत काम करने की नहीं है—क्यों ताकत नहीं है ? इस लिये नहीं है कि उस को पौष्टिक पदार्थ नहीं मिलते हैं, जो कुछ उस को मिलता है, उसी में सन्तोष करता है। वह पौष्टिक पदार्थ खाये इसका आपको प्रबन्ध करना होगा, इस की तरफ आपको ध्यान देना होगा। चरागाह जो नष्ट हो गई हैं उन की तरफ आपको ध्यान देना होगा। आपने जो योजनाएं बना रखी हैं उनकी वजह से देश चौपट हो गया है। आज उस के अन्दर यह भावना पैदा हो रही है कि उसकी उन्नति में किसी को कोई रुचि नहीं है। लिपस्टिक आदि जो भौतिक चीजें बढ़ रही हैं वह इनकी ओर नहीं जा सकता है। उसको पेट पालने की ही चिन्ता रहती है। उसका थोड़ा बहुत जो खर्च है वह पेट पालने पर ही होता है। इस कारण से आज उसके अन्दर यह भाव पैदा हो रहा है कि वह इतनी मेहनत करता है और उस मेहनत से उसको इतनी आमदनी हो जाती है कि वह पेट पाल सके और वह आगे ज्यादा पैदा करके क्या करेगा।

खेती पर मजदूर जो लगे हुए हैं उनकी क्या हालत है। आप देखिये वे शहरों की तरफ आ रहे हैं। शहरों की आबादी बढ़ती चली जा रही है। दिल्ली, कानपुर किसी भी शहर को आप देखलें, उसकी आबादी बढ़ती चली जा रही है। इसलिए आबादी बढ़ रही है कि देहातों में जो खेतीहर मजदूर हैं जिन की तरफ आपने कोई तवज्जह नहीं दी है, ध्यान नहीं दिया है उनके सामने कोई रास्ता नहीं रह गया है सिवाय इसके कि वे शहरों की ओर भागें और वहीं रिक्शा चला कर अपना पेट पालें। आपने उनको रिक्शा चलाने के लिए मजबूर कर दिया है। आप ने उनको मजबूर कर दिया है कि वे गांवों से भाग कर शहरों की तरफ जायें और वहां जा कर रिक्शा चलावें। खेती में वह समय आता है कि जब खेतीहर मजदूरों की अधिक आवश्यकता पड़ती है। यह जो आवश्यकता उनकी है वह आज गांवों में पूरी नहीं हो रही है। इस वास्ते खेतीहर मजदूरों की तरफ भी आपको ध्यान देना होगा।

गोवद्ध बन्द न करके देश में आपने इस प्रकार की स्थिति पैदा कर दी है कि हमारे पास अच्छे बैल नहीं रह गए हैं। ट्रैक्टरों की भी व्यवस्था नहीं हो पाई है। अभी मैंने पिछली मर्तबा प्रश्न पूछा था। उस प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया था कि एक योजना वह बना रहे हैं जिसके अधीन उत्तर प्रदेश में छोटे कटर बनाये जाएंगे। पता नहीं

वह योजना कब पूरी होगी। खेतीहर मजदूरों के अन्दर काम करने की ताकत नहीं है, उनकी शक्ति कम हो रही है क्योंकि उनको अच्छा खाना, अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है। इसलिए वे आज काम नहीं कर पा रहे हैं। उतना काम नहीं कर पा रहे हैं जितना उनको करना चाहिये। मैं प्रार्थना करता हूं कि छोटे ट्रैक्टर बनाने का कारखाना जल्दी से जल्दी स्थापित किया जाए ताकि सस्ते ट्रैक्टर आसानी से सुलभ हो सकें। छोटे-छोटे ट्रैक्टर अपने ही देश में बनने चाहिएं। पानी की अच्छी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये। सरकार को गारन्टी करनी चाहिये कि पानी काशतकारों को समय पर और उचित मात्रा में मिलता रहेगा। कुओं और पोखरों की गांवों में उपयोगिता बहुत अधिक है। मैं चाहता हूं कि उनके द्वारा किसानों को पानी देने की व्यवस्था भी सरकार अपने हाथ में ले।

श्री ओंकार लाल बोहरा (चित्तौड़गढ़): उपाध्यक्ष महोदय···

उपाध्यक्ष महोदय: दस मिनट।

श्री ओंकार लाल बोहरा: आपके प्रति पूरा सम्मान रखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि पिछले तीन दिन से जो बहस चल रही है इसके चलते मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि मेरी पार्टी में आपने मुझे नहीं बुलाया और और लोगों को बुलाया जबकि मेरा नाम बहुत पहले था। अब भी आप मुझे यह निर्देश दे रहे हैं कि मैं केवल दस मिनट में खत्म कर दूं। मैं कहना चाहता हूं कि मैं न तो श्री शिव नारायण हूं और न ही चौधरी रणधीर सिंह और शायद यही मेरा दोष है। मैं कहना चाहता हूं कि आपको न्यायसंगत होना चाहिये।

मैं खाद्य मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस विषय पर बहस आमंत्रित की। अपने देश की परम्परा के अनुसार राजा इंद्र को हमें धन्यवाद देना चाहिये क्योंकि उसकी कृपा से ही इस बार प्रकृति अनुकूल रही है और वर्षा अच्छी हो गई है। मैं समझता हूं कि इस दृष्टि से माननीय जगजीवन राम जी और शिन्दे साहब बड़े भाग्यशाली हैं। बारिश अच्छी होने से वे भी कटु आलोचना से बच गए।

लेकिन सही बात यह है कि अगर हम प्रकृति के भरोसे ही अपनी खाद्य समस्या को हल करने का प्रयत्न करते रहे तो मैं समझता हूं कि यह हमारी बहुत बड़ी भूल होगी और यह झूठी खुशी होगी। देखना यह है कि आजादी के बाद खाद्य के क्षेत्र में खाद्यान्नों की उपज के अन्दर, पैदावार बढ़ाने में हमने ईमानदारी से कितने प्रयत्न किये हैं। हमारे देश के बारे में यह चर्चा थी कि भारत कृषि प्रधान देश है। यहां के लाखों करोड़ों किसान पैदावार बढ़ाने में योग दे रहे हैं। लेकिन कृषि प्रधान देश होते हुए भी आज हमें विदेशों में दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं और भिखारी की तरह झोली पसारे हुए हम को उनसे अनाज की भीख मांगनी पड़ रही है। हमें ऐसा करते समय अपनी इज्जत बेइज्जती की परवाह भी नहीं होती है। साथ ही भारत को विदेशों में गलत ढंग से चित्रित भी किया जाता है और कहा जाता है कि भारत नंगा है, भारत भूखा है। चूंकि हम भिखारी की तरह मांगते फिरते हैं इस से हमारी प्रतिष्ठा नीचे और नीचे चली जा रही है। इससे भी बड़ा दुर्भाग्य हमारा यह है कि जो ढंग हमने अपनाया है उस में न तो हम कृषि प्रधान देश रहे हैं और न ही औद्योगिक दृष्टि से जैसा उन्नत हमारा देश होना चाहिये था, वह ही हम बन पाए हैं। ऐसी अवस्था में देखना यह है कि क्या कारण है कि हम अपने देश की इस सब से बड़ी समस्या को हल नहीं कर पाते हैं। बातें बहुत होती हैं। जितनी चर्चा हम लोग यहां करते हैं, जितनी घोषणायें मंत्रियों की ओर से या अधिकारियों की ओर से होती हैं दुर्भाग्य की बात है कि उन में से दस प्रतिशत पर भी अमल नहीं किया जाता है। अगर दस प्रतिशत पर भी अमल किया जाता तो देश का नक्शा दूसरा ही होता। इसी का यह परिणाम है कि हमें अपना पेट

[श्री ओंकार लाल बोहरा]

पालने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है जोकि सब से ज्यादा अपमानजनक और लज्जाजनक स्थिति है। इसको हमें स्वीकार करना चाहिये। पिछले बीस वर्ष से हम सचमुच में केवल पार्लिमेंट के फ्लोर पर या मंत्रियों के घोषणापत्रों में ही खाद्यान्नों का उत्पादन देखते रहे हैं। मैं समझता हूं कि यदि हमें खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाना है तो हमें मिशनरी स्पिरिट से काम करना होगा, उच्च स्तर पर योजना बना कर उसको सर्वोच्च प्राथमिकता दे कर काम करना होगा। उत्पादन बातें करने से, समाजवाद का नारा देने से, लम्बे लम्बे भाषण देने से नहीं बढ़ेगा। ऐसा करके जवार और बाजरे और गेहूं की पैदावार को नहीं बढ़ाया जा सकता है और कश क्राप्स की पैदावार को नहीं बढ़ाया जा सकता है।

हमारा देश जबर्दस्त आर्थिक संकट में से हो कर गुजर रहा है। किसानों के बारे में जैसा कि किसानों के प्रमुख प्रतिनिधियों ने कहा है, मैं भी जोर दे कर कहना चाहता हूं कि उनको अधिक से अधिक राहत मिलनी चाहिये। किसान जो काम करता है उसको देखते हुए उसको प्रतिष्ठा मिलनी चाहिये, समाज में उसके काम का उचित मूल्यांकन होना चाहिए। आज जिस तरह का हमारी समाज व्यवस्था का ढांचा है उस में जिसके पास अधिक पैसा होता है उसी को सम्मान मिलता है। इस वास्ते किसान लोग सामाजिक दृष्टि से उस सम्मान को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जो उनको मिलना चाहिए। वे गरीब हैं। यही कारण है कि नई पीढ़ी के लोग भारत में खेती का काम नहीं करना चाहते हैं। वे खेती के काम को हीन समझते हैं, छोटा समझते हैं। इसलिए हीन समझते हैं कि किसान को वह सम्मान प्राप्त नहीं है, वह प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है जो उसको मिलनी चाहिये। किसान के लड़के पढ़ लिख कर निकलेंगे तो वे खेती का काम नहीं करेंगे। हमने सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में किसान को वह दर्जा नहीं दिया है जिसे प्राप्त करने का किसान अधिकारी है, जिस में किसान समुदाय यह अनुभव करे कि जो वह कर रहा है, देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है, देश की बड़ी सेवा कर रहा है। बाबू लोगों की कितनी कद्र होती है उतनी किसान की नहीं होती है। यह एक बहुत बड़ा साइकोलोजिकल प्रश्न है। इस पर हमें गम्भीरता से विचार करना होगा। जब तक हम बुनियादी समस्या को हल नहीं करेंगे, जब तक हम यह अनुभव नहीं करेंगे कि जो किसान है, जो मजदूर है, जो खेती करता है, जो वह पैदा करता है, वह पैदा करने वाला बड़ा है तब तक मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी आदमी उत्पादन के क्षेत्र में उत्साह नहीं दिखाएगा।

हम आधुनिक युग में रह रहे हैं, ज्ञान विज्ञान के युग में रह रहे हैं। लेकिन आज भी खेती के वही पुराने तरीके काम में लाये जा रहे हैं, वही पुराने ढंग अपनाए जा रहे हैं। ये साधन बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। अगर हम चाहते हैं कि देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए देश में ही अन्न की पैदावार बढ़े, तो यह तभी हो सकता है जब नई पीढ़ी इस काम में लगे और आधुनिक टैक्नोलौजी का आधुनिक ज्ञान विज्ञान का लाभ उठाये और मिशनरी भावना से उत्पादन बढ़ाने के काम को अपने हाथ में ले। अगर पुराने तरीकों से काम चलाया जाता है, पुराने हथियार काम में लाये जाते हैं तो हम जो बड़ी बड़ी अपेक्षायें किसान से करते हैं, वे अपेक्षायें हमारी पूरी नहीं हो सकती हैं। उनके पूरा होने की हम आशा नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले मेरा निवेदन यह है कि जो नई पीढ़ी आ रही है उस पीढ़ी के नौजवानों को हमें प्रोत्साहन देना चाहिये और उनको समझाना चाहिये कि वे किसानी के काम को महत्व दें, उसको छोटा काम न समझें। यह तभी सम्भव होगा जब हमारे दिल और दिमाग साफ हों, खेती का काम करने वाले जो किसान हैं उनको हम प्रतिष्ठा प्रदान करें, यह समझें कि वह देश का नम्बर एक सेवक है, प्रथम श्रेणी का सेवक है।

सही बात यह है कि किसान को आज न सुधरे हुए बीज हम दे पाते हैं, न अच्छा फर्टिलाइजर दे पाते हैं और न ही उनको खेती के लिए सिंचाई की सुविधायें दे पाते हैं। मैं राजस्थान की चर्चा करता हूं। सैंकड़ों किसानों ने अपने पम्पिंग सैट लिये लेकिन उनको बिजली नहीं मिली। जब बिजली देने का सवाल आया तो उनको कहा गया कि दो हजार रुपया और दो सरकार को ऋण के रूप में तब तुम्हें बिजली मिलेगी। पम्पिंग सैट खरीदने के लिए किसानों ने कर्जा लिया, तकावी लोन लिया तो उनसे कैसे यह आशा की जा सकती है कि दो हजार रुपये आपको वह ऋण पत्र खरीदने में दे सकेगा। इस वास्ते देखना यह है कि कितनी ईमानदारी से हम खाद्यान्न की समस्या को हल करने में सचेष्ट हैं।

खाद्यान्न की समस्या हमारी आर्थिक नीति से भी सम्बन्धित है। जब तक सिंचाई की बड़ी बड़ी योजनायें और माइनर इरिगेशन स्कीम्ज अधूरी रहेंगी, जब तक हमारी परती जमीन को पानी नहीं मिलेगा, तब तक वह सोना नहीं उगलेगी। सरकार परती जमीन को पानी दे और उस को उन लोगों में बांटे, जो स्वयं खेती करते हैं। आज हजारों बीघा जमीन ऐसे लोगों के पास है, जो स्वयं खेती नहीं करते हैं। मेरे मित्र, श्री रंगा, माफ़ करेंगे, देश में, और खासकर राजस्थान में, हजारों बीघे जमीन अनेक राजा महाराजाओं के पास है, जो स्वयं खेती नहीं करते हैं, न करना चाहते हैं और यदि बेचते हैं, तो बड़े महंगे दामों पर बेचते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार की ओर से राज्य सरकारों को यह निर्देश और परामर्श दिया जाये कि भूमि सीलिंग कानून को तुरन्त अमल में लाया जाए। जो लोग स्वयं खेती नहीं करते हैं, उन के हाथों से भूमि ले कर उन लोगों को दी जाये, जो खुद काश्त करते हैं। इस बारे में नई पीढ़ी के उन लोगों को प्रोत्साहन दिया जाये, जो खेती करना चाहते हैं। यह वाजिब नहीं है, यह न्यायसंगत नहीं है कि जमींदारों, राजा-महाराजाओं और सामन्तों के पास हजारों बीघे जमीन पड़ी रहे और केवल चरागाह, उन के एशो-आराम और उन के बड़प्पन को सिद्ध करने के लिए पड़ी रहे। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि राज्य सरकारें जल्दी से जल्दी भूमि सीलिंग के कानून को लागू करें।

जब तक भूमि का समुचित वितरण नहीं होगा, जब तक भूमिहीन खेतिहरों को जमीन नहीं मिलेगी, तब तक उन को उत्पादन बढ़ाने का उत्साह नहीं होगा।

राजस्थान में केवल एक गंगा नहर बनने से लाखों बीघे जमीन आबाद हो गई। श्री गंगा सिंह जी ने जिस ज़मीन में वह नहर बनवाई थी, उस की तुलना में गंगानगर का इलाका चमन हो गया है। वहां पर राजस्थान नहर बनाना भी तय हुआ है। अगर उस नहर को पूरा बनने का मौका मिल जाये, उस पर जो करोड़ों रुपये लगने हैं, वे उपलब्ध हो जायें और वह नहर पूरी हो जाए, तो वह न केवल राजस्थान, बल्कि सम्पूर्ण भारत, की खाद्य समस्या को हल करने में बहुत महत्वपूर्ण पार्ट अदा कर सकती है। जब इन बड़ी-बड़ी योजनाओं और छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए पैसा मांगा जाता है, तो उस की उपेक्षा की जाती है, लेकिन जब पी० एल० 480 के अन्तर्गत विदेशों से अन्न मंगानें की लज्जाजनक और अपमानजनक स्थिति आ जाती है, तब हम अपने स्वाभिमान और देश के गौरव का खयाल नहीं करते हैं। इस लिए मैं निवेदन करूंगा कि केन्द्रीय सरकार राजस्थान नहर की योजना को कार्यान्वित करे। अकेले उस नहर से राजस्थान से करोड़ों टन अनाज मिलेगा, जिस से देश की खाद्य समस्या को हल करने में मदद मिलेगी। जब तक ऐसी बड़ी-बड़ी योजनाएं पूरी न हों, तब तक छोटी-छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए, छोटे-छोटे एनीकट्स के

[श्री ओंकार लाल बोहरा]

लिए, धनराशि स्वीकृत की जानी चाहिए, क्यों कि इन छोटी-छोटी सिंचाई योजनाओं से लाखों एकड़ जमीन की सिंचाई की जा सकती है।

मेरी मांग है कि हमने जो रेस्ट्रिक्शन लगाए है कि एक जिले से दूसरे जिले और एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त को खाद्यान्न न जाये, उन को समाप्त करना चाहिए। इस प्रकार का प्रतिबन्ध खाद्यान्न के नियन्त्रण और सुविधाजनक वितरण में बहुत बाधा है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कैश क्राप्स और दूसरी क्राप्स में संतुलन कायम करना चाहिए। जूट, रबर और चाय तो बहुत बड़े उद्योग हैं और हमारे लिए विदेशी मुद्रा के अर्जन के लिए साधन हैं। लेकिन इन के अतिरिक्त तिलहन, कपास और गन्ना की पैदावार और गेहूं, ज्वार और बाजरा आदि दूसरे खाद्यान्नों की पैदावार में संतुलन कायम किया जाना चाहिए।

सबसे पहले हमें यह घोषणा करनी चाहिए कि हम आगामी वर्ष से विदेशों से अन्न नहीं मंगायेंगे। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, तब तक हम अन्न के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर रहेंगे। अगर सरकार अगले वर्ष के लिए कोई बड़ा पग उठाना चाहती है, या इस बहस के दौरान कोई महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहती है, तो वह यही होना चाहिए कि हम शपथ लें कि अब हम अन्न का एक दाना भी विदेशों से नहीं मंगायेंगे और पूरी ताकत के साथ देश को इस सम्बन्ध में स्वावलम्बी बनायेंगे। तभी मैं समझूंगा कि हम ने ईमानदारी से कोई प्रयत्न किया है कि हम स्वावलम्बी हों और अन्न के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर न हों।

मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि केन्द्र से भूमि सीलिंग कानून के बारे में राज्य सरकारों को निदेश जाने चाहिएं और राजा-महाराजाओं और श्रीमन्तों के पास जो हजारों बीघे जमीन पड़ी है, उस का वितरण होना चाहिए। स्वयं काश्त करने वालों के पास जमीन जानी चाहिए और भूमिहीनों और खेतिहरों को जमीन मिलनी चाहिए।

अन्त में मैं फिर कहना चाहता हूं कि हम इस बारे में केवल बातें ही न करें, बल्कि जब तक हम मिशनरी भावना से काम नहीं करेंगे जब तक हमारे मनों में किसान के प्रति प्रतिष्ठा और सम्मान की भावना पैदा नहीं होगी, उत्पादन करने वालों के प्रति सम्मान की भावना पैदा नहीं होगी, तब तक देश का उत्पादन कभी नहीं बढ़ेगा।

SHRI K. M. ABRAHAM (Kottayam) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, a little while earlier you advised the Congress Members to limit their speeches to ten minutes, because you are going to give a chance to every State. Unfortunately, there is no Congress member here from our State. So, I would request you to give those 10 minutes which you give to Congress members, to some non-Congress member from our State.

The food situation in the country is in an acute crisis. But that is part of the bigger economic crisis, which is ever deepening day by day. If this crisis continues for a long time, it will result in a political crisis when the Congress regime will be doomed. It is only to get out of this crisis that Congress is trying to share the burden of the toiling masses by giving them food, either by foreign aid or by PL 480 imports.

I am sorry to say that the Congress Government is not following either a national food policy or monopoly procurement or equitable distribution. They always talk of self-sufficiency. In 1947 they were saying that within ten years self-sufficiency in food will be achieved. In 1947, on the eve of independence, Shri Jawaharlal Nehru declared that India will become self-sufficient in food in ten years. During the First Plan also it was claimed that self-sufficiency in food will be achieved in ten years. Now also they are talking the same language, that India will become self-sufficient in ten years.

15·28 Hrs.

[SHRI C. K. BHATTACHARYYA *in the chair*]

This reminds me of an incident. In the year 1950 I happened to cross a river in my part of the country in a small boat. The boatman was a pretty old man and I asked him his age. He told me that he is sixty. After about ten years I happened to pass through the same route and I crossed the river in the same boat. I met the same old boatman and I asked him his age. He gave me the same reply, that he is sixty. I was surprised. I asked him "How is it that you are only sixty ? Ten years back also you were saying that you are sixty." He quietly replied "decent men do not change their words". The members of the Congress Party are perhaps decent people and that is why they are not changing their words and they are saying the same thing, namely, within ten years India will become self-sufficient. But the people are not so gullible to be taken in by such statements.

In order to make the donkeys walk it is the usual practice to attach a pole or stick to the yoke and hang some straw or grass on the pole so that it will be hanging before the donkey. The donkey will walk fast thinking it can get that grass by walking fast. But, as the donkey moves forward, so also the yoke and the poll attached to it with the result that the donkey never gets the grass at all. So also they say, "You come with us; you will be given food", but we will not reach that if we travel with them for another hundred years.

SHRIMATI LAKSHMIKANTHAMMA: Was there no increase in food production at all ?

SHRI K. M. ABRAHAM : You can say that when your chance comes.

In 1940 our Travancore State was ruled by one Sir C. P. Ramaswami Ayyar. We called him a brutal oppressor, Satan and all that, but during the war period he gave us 16 ounces of rice. After 20 years of independence our Kerala people are getting only three ounces of rice. It is shameful to say so.

When we say that it is political discrimination or that they are bringing food in politics, they are quarrelling with us. Let me go through some data. What is the actual position of Kerala ? Kerala is a deficit State. The *per capita* production of foodgrains in Kerala is 5.1 ounces whereas in Andhra it is 14.9 ounces, in Madras 13.5 ounces, in West Bengal 12 ounces, in Madhya Pradesh 13.8 ounces and in Orissa 16.6 ounces. As per the Nutrition Committee's recommendation an adult must have 14 ounces of foodgrains a day. In order to give six ounces of rice to an adult in Kerala 77,000 tonnes of rice must be given per month but actually I will give you seven month's allotment. From March to October 1965, we got 6,63,791 tonnes. during the same period in 1966 we got 5,14,694 tonnes but during March to October this year we got only 3,56,694 tonnes, In 1965 every month we got at an average rate of 82,900 tonnes; in 1966 it was 64,300 tonnes but in 1967 it was only 44,500 tonnes. Only half the allotment given in 1965 and 1966 is given in 1967. Not only that, in 1965 and 1966 they said that there was a poor crop; and in 1967 they say that there is a bumper crop; yet, we are getting only at the rate of 44,500 tonnes.

During the last three months, that is, during August, September and October we got 40,555 tonnes in August, 37,158 tonnes in September and 22,763 tonnes only in October.

When the South Zone was removed the Central Government promised Kerala that they would give sufficient rice to Kerala so that they need not have a buffer stock. I will read one sentence only from Government's letter. It reads :—

> "As we have agreed to meet the full rice requirements of informal rationing in Kerala at the present quantum of ration there is no need for the Kerala Government to build up a buffer stock of their own. We are stocking our depots in Kerala adequately to maintain issue at the present quantum of ration."

They promised 75,000 tonnes every month but we are getting only 29,000, 30,000 or 40,000 tonnes of rice. When we say that

[Shri K. M. Abraham]

it is politically motivated they quarrel with us and say that we are creating a wrong impression against the Centre.

AN HON. MEMBER : No political motivation here.

SHRI K. M. ABRAHAM : During the debate in this House, the hon. ex-Law Minister, Mr. A. K. Sen, said that the West Bengal Government had failed to give rice to the people. From where will they give rice for a full ration ? The Central Government must have done that. But after the Ministry has gone, by hon. friend said, the ration has incresed and foodgrains were rushed to West Bengal. How is this possible ? I ask you : is it not a politically motivated thing ?

Again, our hon. Law Minister, Mr. Pasampalli Govinda Menon, when he visited Kerala last time, said that both the Kerala Government and the Central Government had failed to give rice to the people. How is it ? At least he accepted that the Central Government failed. His argument was this: the Kerala Government failed to give rice to the people and the Central Government failed to give rice to Kerala Government. This is his argument.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE) : We have been giving wheat. Wheat is being given to the extent of shortfalls.

SHRI K. M. ABRAHAM : When Mr. Govinda Menon speaks such things, he has some motive behind it. At that time there was the student's strike, the engineering student's strike, in Kerala. To insinuate the people against the Government, he thought that that was the time to say that the Kerala Government had failed to give rice to the people; that is his political motive....*(Interruptions)*. The Central Government knows, the Congress knows, that only through food, only by not giving rice to Kerala, they can insinuate the people against the Kerala Ministry. They tried it even before. In 1959, they adopted another method, *i.e.*, by a political struggle, the so-called liberation struggle. At that time our Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi, the ex-Congress President, came there personally, intervened in the agitation and toppled the Government. This time, they are coming in another way. Excuse me, Sir, when I say this : the characteristic feature of the criminals is that they will do the same kind of crime every time; that is to say, the pickpockets will do pick-pocketing and the burglars will do only their job, burgling; so also, the Congress cannot but topple the Government. That is what they did in Haryana and West Bengal and they are now trying to topple the Government of Kerala....

MR. CHAIRMAN : The hon. Member may conclude.

SHRI K. M. ABRAHAM : I am going to take the time of the other speaker of my Party also.

Mr. CHAIRMAN : The hon. Member has already taken the time allotted to his Party.

SHRI K. M. ABRAHAM : No, I have taken only half the time.

MR. CHAIRMAN : I have this on record. He will have to conclude in a minute or two.

SHRI K. M. ABRAHAM : I will just conclude. I would like to say one or two things about the procurement policy. Upto this time the Centre was alleging that Kerala was not procuring their targeted quantity. I will read out to you one report. During the last crop, the target was 49,162.8 tonnes whereas we procured 54,244.8 tonnes. At the same time last year, *i.e.*, 1966, the target was 43,714 tonnes but only 36,764 tonnes was procured. I am going to charge the Government : is it possible for the Government to have such a procurement policy in the State ? No, it is not possible. Kerala Government asked the Centre to give them either 75,000 tonnes of rice or allow them to purchase it from other States. But when we ask for purchasing from other States, they will

immediately comes and say 'It is a Centre's affair. You need not interfere in such things'. Perhaps, our Food Minister may contradict it. I am going to read a part of the sentence banning the State Governments from purchasing foodgrains from other States. 'You advised us against approaching surplus State Governments directly for supply of foodgrains over and above the quantities allotted by the Centre.' This is a dog in the manger policy. They are not giving us rice, nor do they allow us to purchase from other States. We are even willing to pay a higher price than that fixed by the Central Government. The neighbouring States are ready. If we give a higher price, they are ready to give us the rice, but the Centre is not allowing us. Either you must allot us 75,000 tonnes of rice every month or allow us to buy it from outside the State and also allow us, even if it is necessary, to pay a higher price and buy from other States.

Before I conclude, I would say one thing. The Central Government must have a national food policy. It must have a monopoly procurement policy and equitable distribution policy.

About self-sufficiency I have to say a word. There are 11 million acres of cultivable land in the country which should be distributed amongst the tillers of the soil. Even if half of this 11 million acres of land is brought under the plough, we need not depend upon foreign countries. I conclude.

SHRI R. S. ARUMUGAM (Tenkasi) : Mr. Chairman, Sir, while we are discussing the food situation, we should not forget the achievements so far made in the food front after Independence. By constructing a number of dams we have brought hundreds of thousands of acres of land under irrigation. By installing fertiliser plants we have increased our fertiliser production. By supplying fertilisers, improved seeds and pesticides and giving assured water supply and improved agricultural implements and other facilities to the ryots we have increased the agricultural production to a large extent. But if we had not reached the targets, that is because of some reason or the other. Nobody can deny it.

Sir, if we take up Madras State, under the then Congress Government tremendous progress has been made in agriculture. All possible dams have been constructed and 90% of river water has been harnessed and utilised.

SHRIMATI LAKSHMIKANTHAMMA: And every village has been electrified.

SHRI R. S. ARUMUGAM : Out of five lakhs pump sets in India, more than 2½ lakhs pump sets have been set up in Madras State alone. Everywhere, they have been electrified. Quick-maturing and high-yielding paddy strain known as KDT-27 was raised in the Tanjore district. By implementating all these schemes, our State has been made a surplus State whereas formerly it was one of the deficit States in India. All these were the achievements of the then Governments in power.

Government must give incentive to the agriculturists for agricultural production. The agriculturists must get remunerative prices for their produce. In the Madras State, there is a vast difference between the procurement price and the market price. The procurement price per bag of 56 Madras measures of paddy is Rs. 25 whereas the market price for the same quantity is more than Rs. 50 in some cases and in some other cases it is more than Rs. 60. Further, the procurement which is being done is also coercive and harassing and with police excess. I am not aganist procurement, but it should not be coercive. The ryots have to seek remedy through the courts and sometimes they have to go up to even the High Court. Would it be possible for all the agriculturists to seek remedy through the courts ? I ask the hon. Minister whether it will give incentive to the agriculturists to produce more. I submit that it will never give them that incentive.

In Tirunelveli and Ramanathapuram and other districts, the agricultural labourers have to go to places other than their own for harvesting. They are getting only paddy as their wages, but when they are returning home, on the way they are prosecuted and their paddy is seized. Such unfortunate things are going on in the Madras State

[Shri R.S. Arumugam]
in the name of procurement and other restrictions.

In the villages, every villager got his rations formerly through family cards at the rate of Rs. 1.25 per Madras measure. But now it has been discontinued, and most of the people in the rural areas are suffering in order to get rice. In some places, the selling price for one Madras measure of rice is Rs. 2, in some others it is Rs. 3 and in some other places it is even more.

SHRI G. VISWANATHAN (Wandiwash) : Where is that ?

SHRI R. S. ARUMUGAM : In Kanyakumari district of Madras State.

SHRI G. VISWANATHAN : That may be the price in Connaught Place, not in Madras State.

SHRI R. S. ARUMUGAM : That is the position in Madras State. In my district, Trunelveli the selling price is at about Rs. 2¼.

SHRI G. VISWANATHAN : Let him not give wrong figures. When he gives those figures I think the hon. Member is not talking of Madras State but of the position in Delhi, perhaps.

SHRI SAMBASIVAM (Nogapattinam) : That is the position in Ramanathapuram district of Madras State.

SHRI G. VISWANATHAN : The hon. Member is misleading the House.

MR. CHAIRMAN : The hon. Member must be allowed to have his say.

SHRI R. S. ARUMUGAM : That price in Kanyakumari district of Madras State. *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN : Order, order. The hon. Member might proceed with his speech.

SHRI S. XAVIER (Tirunelveli) On a point of privilege. He is misleading the House and he is making a wrong statement of facts.

MR. CHAIRMAN : In any case, let him finish his speech.

SHRIMATI LAKSHMIKANTHAMMA: He has said all that the Congress Government had done and what the present Government there have not done.

MR. CHAIRMAN : Has he finished his speech ?

SHRI D. C. SHARMA (Gurdaspur) : He has just now begun ?

SHRI R. S. ARUMUGAM : Not only with respect to rice, but in the case of other commodities of daily consumption, the prices are going up higher and higher.

SHRI G. VISWANATHAN : It is due to the wrong economic policy of the Central Government.

SHRI R. S. ARUMUGAM : I am speaking of the state of affairs in the Madras State.

SHRI G. VISWANATHAN : Let him say that in the Madras Assembly. What is the need for saying it in Parliament ?

SHRI R. S. ARUMUGAM : I am being interrupted frequently.

MR. CHAIRMAN : He will please not enter into a discussion with him. Let him address the Chair.

SHRI S. XAVIER : Is Madras a surplus State ?

MR. CHAIRMAN : Order, order. Let him proceed.

SHRI R. S. ARUMUGAM : Until the Madras Government is able to give 3 Madras measures for one rupee.....

AN HON. MEMBER : An election promise.

SHRI G. VISWANATHAN : He should have said that in his election meeting. What is the purpose of saying it here ?

SHRI R. S. ARUMUGAM : I would tell the Madras Government not to discontinue the family card system in the rural areas. *(Interruptions)*.

SHRI R. S. ARUMUGAM : They are interfering with me.

MR. CHAIRMAN : Let him address me.

SHRI R. S. ARUMUGAM : In Tuticorin, we cannot get rice at less than Rs. 6.....(*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN : Let him finish this speech.

SHRI S. XAVIER : I know the state of affairs in Madras State. It is incorrect to say that rice is sold at Rs. 6/-.

SHRI R. S. ARUMUGAM : In most of the States, land reforms have been implemented. Still there are hundreds of thousands of peasants and agricultural labourers without land for cultivation. There are forest cultivable lands, *purambok* and *patta* lands lying waste. We can acquir the falow *patta* lands which will not cost much. These lands may be distributed to the landless poor and Harijans. Government must give subsidy and loans to these agriculturists for expenses of reclamation and cultivation. By these schemes, the poor people will get lands for cultivation, it will at the same time give them occupation and also provide the country with much-needed food.

SHRI J. K. CHOUDHURY (Tripura west) : Mr. Chairman, in my part of the country, there has been a parody....

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) : Which part ?

SHRI J. K. CHOUDHURY : Tripura and parts of Bengal ....

MR. CHAIRMAN : That should be found out from the list not by putting a question here.

SHRI S. M. BANERJEE : Tripura—I am answering him.

MR. CHAIRMAN : Shri Banerjee is here to answer all irrelevant questions.

SHRI J. K. CHOUDHURY : Parody of a sacred song——

रघुपति राघव राजा राम
पूरा महीना आधा काम
चोराई का द्वार तेरा नाम
सबको मुनाफा दे भगवान ।

Now that has been a song of despair and banter that everybody is after profit and those who cannot make undue profit have no right to live.

About rice, it went to Rs. 80 a maund. Now, with the coming in, of course not fully but partly, of the new harvest it has come down to Rs. 60. Imagine the position of a day labourer or of those workers who live from hand to mouth, even those clerks and teachers and others of the lower echelons of service. How can they live ?

The key to the whole thing is agriculture. Once our food stocks are enough, everything will come down. I do not want to repeat what has been said in this House by so many members, for instance land reforms. That is a must, but then, we have had enough of make-believe in this respect as well. We have passed laws, but in the implementation there have been subterfuges. Hundreds and hundreds of acres of land are under one man in *benami*. It is going on like this. But even though every one who is interested in farming gets his share of land, India of 500 million people cannot live merely by agriculture. They must be diverted to other sources of employment, now particularly, because in the villages they find it difficult to live. The towns are swelling in population, and all sorts of social problems are being created.

I will just touch on certain things. We have heard enough of droughts, but why should droughts effect our country in such a way after we have spent over Rs. 1,200 crores on irrigation, on big dams and other things ?

We have got from abroad food worth Rs.1,800 crores and more in all these years. Why could we not divert it to the improvement of agriculture, at least a part of it, and bring it more irrigation, small and medium irrigation schemes.

Then, about the figures of food production I wonder how they could gather those figures. No farmer is going to tell how much grain he has in his granary for two reasons. Firstly, he is superstitious, he thinks that if he gives out his real figure and it is a bumper crop, the next year he will have ill-luck. Secoodly, he is afraid of

[Shri J. K. Choudhury]

Government acquisition of his rice or paddy. Then how was Government aware that we got 89 million tonnes of food in 1964, 75 million in 1965 and 72 million in 1966 and it will be 95 this year ? About this 95 million tonnes, again doubts have been raised and those doubts are sought to be resolved. On the whole, it comes to this that we do not know the actual figures. All that we do know is that there is food in the country, but it is not being distributed well.

For distribution, the solution must be radical. All middle men must be wiped out from the food business. The question then again comes up : which will be the means of distribution ? The Food Corporation of India, or something like that. But then, these people whom you will send, perhaps as Government servants or in any other capacity, will go to the farmers and cheat them—most of them I do not say all, there are honourable exceptions; taking 1,100 grammes they will make it one kilo, and paying the farmer Rs. 40, they will get a receipt from him for Rs. 45 or Rs. 50. How are you going to change all these things?

I have a proposal to make. It will sound absurd, because anything that is rather radical or new sounds absurd to us at first. For instance, I once suggested to the Speaker in a letter that in all these blank wooden panels of this House there ought to be parts of the map of India in relief with arrangement for illumination from behind, so that whenever we are going to have a talk about any place of the country of which generally the Members have not perhaps clear ideas, it can be pointed out and illuminated from behind and you can see the hills, rivers, the taluks and the districts and whatever land has been taken away by China and whatever by Pakistan, and so on. And we in our constituencies are affected by this kind of grabbing very much. I have not heard anything about it because it was perhaps something new. I do not see what a wonderful new suggestion I had made ! It is vrey easy to do.

16 HRS.

Anyway, in the same manner,—I am not going into all those details—they have been discussed threadbare in all these days and hours. But, in order to implement whatever has ben suggested in this House, from this side and that side, you have to take certain measures. I believe in one thing: that every officer from the rank of a Deputy Collector to that of an IAS should have training in the villages for three years; he must take his training in villages, one year in one State, so that he will learn the language of the State in the process; he will mix with the farmers and know what India is; and he will get the edges of his class—consiousness rounded to some extent. On top of it, he will see to it that they get all their things whether you give them fertilisers or seeds or whether you do something in the villages and see that these are done properly and in time. And he will have to work with what are now known as the BDOs. Every BDO must be ....

SHRI D. C. SHARMA : Send the Ministers to the villages.

SHRI J. K. CHOUDHURY : Yes; for myself, I am very much in favour of that. You may send the Ministers to the villages. (*Interruption*). Now, my proposition is that every BDO must be an agricultural graduate and all these trainees along with the BDO must supervise whatever has been suggested by way of land settlement, irrigation, fertilisers, composts, better seeds, insecticides and all the rest of it. Otherwise, whatever you may do, the farmer will not get them in time. Unless the whole country applies its mind to this problem, nothing is going to be solved. We shall remain beggars for ever.

We are now depending, as the fundamental principle of our economics, on three things: beg, borrow and steal. We beg food from all countries, particularly from America; we borrow money from all countries, from the so-called Consortiums, for our industries and for other purposes, leaving the stealing within the country to be done by whoever can do it with impunity. In spite of all our audit and PAC reports, you know what is being done and by whom and why. I am not going into the details. Can we be a free nation, and when shall we become a free nation unless we are free in respect of our food, unless we are free in respect of our industries at least to a large extent ? And the more science will develop

the fewer will be the number of people required in the industries so that the question of unemployment will increase. Therefore, in order to find for the peasant, for the farmer, alternative occupation in his leisure hours, during the months in which he has not to work in his field, you must find for him small cottage industries. We know there are corporations for that, but again my point is, what about the implementation ? In spite of all the subsidies paid, nothing much is achieved. Take Khaddar for example. I am glad that at least it has been made compulsory for Government servants of the lower cadre, say, the Class IV employees, for whom Khaddar uniforms have been given. We find the screens in our M.P.s' houses made of Khaddar. But this kind of oxygen will not be sufficient for the industry. This kind of subsidies in industry is not right. The industries must live by their own merit.

Mahatma Gandhi used to say, and he emphasised that mass production in India means production by the masses. 100 crores of people making one thing each will in the aggregate mean 100 crores of things. So, the farmer must have this alternative occupation for a better living in addition to better agriculture, supervised by all the trainees from the Deputy Magistrates upto the highest ranks in the services, everyone putting in three years training, one year in each State. After these three years, they will know the real problems of the country. They will become familiar with the lives of our farmers, with our agriculture and with the languages of at least three States in which they have spent one year each. After that they can come here and for one more year they can take their lessons in becoming "imitation sahibs" at the administrative training schools and colleges.

The policies and programmes that have been discussed threadbare should be implemented through these agencies, not through the VLW's—the Village Level Workers. They cannot do anything substantial in the matter. Thus the farmer will be cheated for ever and we shall remain beggars for ever.

SHRIMATI NIRLEP KAUR (Sangrur) : Mr. Chairman, Sir, we all agree that the food problem in India is the most important and pressing problem of to day and if not solved, it poses a potential danger not only to our industry and economy but also to our foreign policy. The person who eventually is going to solve it is the farmer, who is the least consulted or heard. I am going to speak about Punjab, because Punjab is the most advanced State in Agriculture. I am sure if I state the conditions, the shortcomings and requirements of Punjab, it would help in solving the food problem and also, it would help in adopting in other States the same practices which are adopted in that State.

Regarding the farmer, he has been lacking in and crying for practically everything he requires for agriculture, *viz.*, water, electricity, seeds, fertilisers, finance, tractors, insurance, implementation of land reform policies, etc. For the past 20 years, we have been hearing from all sides of the House about these things, but nothing has been done so far to satisfy these requirements of the farmer. If I tried to speak about all these things, it will take hours and therefore I will confine my remarks to irrigation. In Punjab, when we were given the Bhakra dam, we thought it is going to solve the problem and bring hopes to the people of Punjab. But what has happened actually is that Bhakra, which was supposed to irrigate 20 lakh acres of land, is actually irrigating only 15 lakh acres. At the same time, a very big problem has arisen *viz.*, waterlogging. The area that is going to be submerged by waterlogging is more or less equivalent to the area that the Bhakra is irrigating. Actually there are four districts in Punjab which shall come under waterlogging. I would submit that the Ministers in charge of Food and Agriculture must take courage and make radical changes in their policies. When they resort to new policies they must consult the farmers directly eliminating politics, the Planning Commission and all those elements which come in between the Ministry of Agriculture and the agriculturists.

The four districts which I was mentioning are Ludhiana, Amritsar, Sangrur and Patiala which have come directly under waterlogging and we are losing land so fast there that soon there will be *kalar* all over and

[Shrimati Nirlep Kaur]

we will be losing this land to agriculture. So the radical change we need is that we should invest a lot of money—from where the money is going to come I will mention later—and the whole area should be brought under tubewell system. Actually I am trying to make out a scheme whereby we should put all that area under tubewell system and the water used for irrigation through canals should be released and sent to Ferozepur, Bhatinda, Rajasthan or Haryana. In this way we will be solving two problems at one and the same time : one will be correcting the waterlogging of the area with the tubewell system and the other will be releasing water for other areas as in Pakistan. That is what they are doing there. They are pumping out water and throwing it back into canals and again drawing water from the land. That is one of the ways of solving the problem.

In areas like Haryana, Rajasthan, Ferozepur and Bhatinda, and in many other places also, the farmers are not able to have two crops; because of lack of water we only have one crop in these areas. The new hybrid seeds require six to seven waterings whereas the previous seeds used to require only two to three waterings. We are actually losing food production in the *kalar* area because there is too much of water and in other areas because there is lack of water.

If we are to put tubewells in these four places round about Rs. 60 crores will be required. I am not very sure as to how the PL 480 funds are being handled, but if the Government cannot give all this money to these four districts they can surely loan this money to the agriculturists of Punjab to be repaid back in three years time. In this way all these four districts can be covered. These districts are really in a sad state of affairs. Year after year the people here see land going under water-logging, and the conditions of the agriculturists, which were a happy lot at one time, are becoming bad. It is pathetic to see them in the conditions they are now. In front of their eyes they are losing everything that they owned.

I would also suggest this irrigation system in new areas like Rajasthan and may be in certain parts of Ludhiana where new canals are going now. They should resort to pipe-line irrigation. There are many advantages in this. Pipe line should go over there with the main canals especially in places like Rajasthan. All this work should be finished on an emergency basis. The excavation cost, which is tremendous, for making these huge canals and drains will be saved. The compensation paid for purchase of land will also be saved. We will also not deprive agriculture on all these lands. The problem of waterlogging also will not arise when we start irrigating through pipes.

Evaporation and seepage is sometimes to the extent of 27 per cent. We can save all this. Also, we can have quicker construction and control on the pressure of water that is released. On enquiries I understand that we have pipes in our country in abundance. We produce a lot of pipes. In fact, we are exporting these big pipes to foreign countries. Even technical know-how is not required from outside India because I am told that our people have gone and constructed a pipe-line system in West Germany to their satisfaction. So, surely we can do this in our own country.

When we introduce this system we should stop irrigation from canals by the distributaries immediately. I would say that the Government of India should lay down a condition that whenever grants are given they should be used only for irrigation by the pipe system. In that way, we can to some extent minimise corruption which takes place while purchasing land and giving contracts for digging canals etc. So, I would request the hon. Agriculture Minister to lay greater emphasis on irrigation by the pipe system.

Many hon. Members have spoken here on different aspects of agriculture. But, somehow, everytime we get up and make speeches, we do not feel—at least I do not feel—that they realy have any effect on our Minister, because they have a set policy and set course in their minds and they go only by that. At least after 20 years they should have realised that some drastic changes are necessary in their polices. Unless they change their polices, there is not going to be any improvement in the situation in the foreseeable future. Here I am not eferring only to irrigation; I have in mind

other things also. For instance, when water is supplied to the farmers through the pipe system, it should be at the same rate at which water is now supplied through the canals. Otherwise, the farmers will be very reluctant to receive water through the pipes. Similarly, the rate for electricity also should not be high to the farmers.

Now there is a great difference in the treatment meted out to the farmers and the city dwellers. Whenever there is an adversity of nature the compensation that is given to the farmers is so poor that it looks as if a mockery is made of the farmers. For instance, in a certain place in Punjab there was a hailstorm and the entire crop was damaged. All the compensation that was given by the government was Rs. 100 per family. What will he do with that Rs. 100 ? Will he buy food for his cattle, or seed for the next crop or food for his family ? This making a mockery of the farmer should be stopped forthwith. During the days of adversity help should be given to the farmers in the real sense. If they cannot give the farmers help during perods of adversity then, in fairness, they should not, like sharks, ask for their pound of flesh whenever there is a good crop. I have heard so many officials saying that the farmer is well off because he has a bumper crop, forgetting conveniently that in the previous two years there was drought, he had reaped nothing and that he has to make up the loss of those two years. When they take to planning they must consider all these aspects.

श्री तुलशीदास जाधव (वारामती) : सभापति महोदय, यह फूड के बारे में जो डिबेट है यह डिबेट तो हर सेशन में होती है और इस के बारे में बहुत से संजेशंस दिए जाते हैं। लेकिन यह कुछ समझ में नहीं आता कि अपनी प्लानिंग में गलती है या कुछ जिन के हाथ में यह डिपार्टमेंट रहता है उन के अन्दर इनीशिएटिव कम होता है या जो उत्पादन करने वाले लोग हैं उन से जो एक अर्ज पैदा हुई है उस को भरपूर सहायता नहीं दी जाती, क्या बात है ? यह जो दो-चार कारण हैं, इन में सरकार को खोज करनी चाहिए कि कौन सा कारण है जिन से अनाज की कमी बनी हुई है। इतनी यहां जमीन पड़ी हुई है। इन्सान भी ज्यादा है। पापुलेशन की दृष्टि से क्यों उतना अनाज पैदा नहीं होता इस के ऊपर जरा खोज और सोच विचार करना चाहिए। मेरी दृष्टि में जो अभी अनाज अपने पास है उस का भी ठीक रीति से, जैसा चाहिए वैसा बटवारा नहीं होता। हम देखते हैं कि हर प्रान्त में, हर शहर में कमोडिटीज की प्राइसेज अलग अलग होती हैं। अभी जब मैं दो-तीन महीने के लिये बाहर परदेश में गया था, तो मैंने देखा कि जो चीज हम देहात में खरीदते थे, जो कीमत वहां पर थी, वही कीमत उन चीजों की बड़े शहरों में थी। लेकिन हमारे यहां इस से भिन्न परिस्थिति है—जहां चावल ज्यादा पैदा होता है, वहां उसकी कीमत कम होती है, लेकिन 10-5 मील पर उस की कीमत दुगुनी होती है। इस से देश में यूनिटी की भावना, जिसे एक्य की भावना कहते हैं, वह पैदा नहीं हो सकती है। आज हर जगह फूड कारपोरेशन खरीद नहीं करता है, हर प्रान्त में उस का एकाधिकार नहीं है, हर जगह खरीदने का अलग अलग तरीका है। जैसा महाराष्ट्र में मोनोपोली परचेज प्रोक्योरमेंट सिस्टम है। हर राज्य में वहां के शासन में जो पार्टी है, उस का फर्ज है कि कम से कम अपने प्रान्त में अनाज के बारे में वह सेल्फ़-सपोर्टिंग हों और जहां पर ज्यादा अनाज हो, वहां मोनोपोली परचेज प्रोक्योरमेंट से ले लें और जहां कमी है वहां सेन्ट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दे दें। जब एक पार्टी का राज्य कन्याकुमारी से हिमालय तक और कलकत्ता से बम्बई तक था, उस वक्त भी यही हालत थी और आज भी यही हालत है। हो सकता है कि कोई स्टेट कोआपरेट करती हो या न करती हो, लेकिन मिनिस्टर साहब ने जैसा कहा—कि किसी गवर्नमेंट ने नान-कोआपरेशन नहीं किया, ऐसी हालत में यह ख्याल पैदा होता है कि फिर इसकी क्या वजह है ? हो सकता है कि किसी प्रान्त का चीफ़ मिनिस्टर न मानें, लेकिन चीफ मिनिस्टर जो कि स्टेट का प्रमुख होता है, वही अगर कुबूल न करे, तो जो आदमी गांव में रहते

[श्री तुलशीदास जाधव]

हैं, वे कैसे कुबूल करेंगे। तो मेरा सेन्ट्रल गवर्नमेंट और हर प्रान्त के चीफ़ मिनिस्टर से अनुरोध है कि यदि देश को एक मानना है, तो इस रीति से उस में कम और ज्यादा की डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिये।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि जो फसल के पैदा करने वाला काश्तकार है, उस को अनाज कम मिलता है, जो काश्तकारी नहीं करता है, प्रोडक्शन नहीं करता है, ऐसे एलीमेंट को सफीशियेन्ट मिलता है। ऐसा किसी भी देश के समाज में नहीं देखा है कि जो पैदा करने वाला है, उस को कुछ न मिले और दूसरे लोग खा जाएं। आज हमारे किसानों के अन्दर पैदावार के प्रति इतना इन्सेन्टिव पैदा हुआ है कि वह कहने लगा है कि मुझ को इरिगेशन की सुविधा दो, बीज की सुविधा दो, फर्टिलाइजर की सुविधा दो, कई जगह पर हम लोग उन के पीछे लग कर कहते हैं कि ज्यादा पैदावार करो लेकिन जब उसे सामान पूरा नहीं पड़ता है, तो वह निराश हो जाता है। आज काश्तकार अनपढ़ होने के बाद भी, जो उन के लड़के हैं, यदि वे थोड़ा भी पढ़े हुए होते हैं, तो उन को शहर में भेजता है और उन को पट्टेवाली नौकरी कराता है, पीयुन की नौकरी कराता है और यदि सौ रुपया कमाता है तो उस में से 50-60 रु० खेती का ऋण देता है, सरकारी रेवेन्यू देता है। यह हाल क्यों होता है? इस के बारे में जहां तक मैंने देखा है उस को पूरी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। आप बड़ी-बड़ी योजनाओं को पूरा करना चाहते हैं। वह ठीक है, लेकिन जब पैसा होगा तभी तो करेंगे। इस वक्त लोगों में उत्साह है, जमीन तैयार है, नये-नये बीज तैयार हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि वक्त पर बीज मिलना चाहिये, छोटी छोटी इरिगेशन की सहूलियत दी जानी चाहिए। पंडित जी ने कहा था कि स्माल इरिगेशन, स्माल कोआपरेटिव इण्डस्ट्रीज से डीसेन्ट्रलाइजेशन करने के बाद कम्यूनिज्म विदआउट वायालेन्स की तरफ़ जा सकते हैं। अगर उस रास्ते की तरफ हम को जाना हो, तो हम ऐसी चीजों की तरफ़ ज्यादा ध्यान दें।

हमारे महाराष्ट्र में कुएं होते हैं, तीन-चार हजार रुपया खर्च करने के बाद उन को बनाया जाता है, इन्जिन न मिलने पर भी किसान अपने दो बैलों की मदद से खेती करने को तैयार है, लेकिन उन को उस के लिये पूरा पैसा नहीं मिलता। हमारे शोलापुर जिले में कई कूएं ऐसे पड़े हैं जिन के लिये दो हजार रुपया उन को मिला, चार हजार नहीं मिला और वे आधे खुदे हुए वैसे ही पड़े, हैं—उनका कोई उपयोग नहीं हो सकता है, रात के अन्धेरे में लोग उन में गिर जाते हैं, न उन का फसल के काम में उपयोग हो सकता है। ऐसी स्थिति में उस दिये हुए पैसे का कोई उपयोग नहीं है। उन को पूरा करना चाहिये, ताकि उन का उपयोग हो सके। मेरी विनती है कि आप इस पर सीरियसली विचार करें। आज काश्तकार लाख-दस लाख रुपया नहीं चाहता, जो छोटी छोटी चीजें हैं, वे अगर उस को दे दी जायें, तो वह अनाज पैदा करने के लिये तैयार है। मैं महाराष्ट्र की बात कहता हूं, काश्तकार अपने सब बाल बच्चों को लेकर खेत पर रहता है, 24 घन्टे काम करने को तैयार है। आज जैसे शुगरकेन के बारे में महाराष्ट्र में बहुत तरक्की हुई है। जो शुगरकेन एक एकड़ में सरासरी 50-60 टन होता है था वह बढ़ कर 100 टन तक पैदा होता है। इतनी शक्ति आज वहां का किसान अपने खेत में डालने के लिए तैयार है। इसलिए मेरी विनती है कि जो भी खामियां हैं, उन को वहां दुरस्त करें।

जो सरकारी कर्मचारी इन कामों में एप्वाइन्ट करें, वे ऐसे होनें चाहियें, जो इन कामों को जानते हों। आज क्या होता है कि वे खुद तो कुछ जानते नहीं हैं, काश्तकार से पूछते हैं कि इस को क्या कहते हैं और उस को क्या कहते हैं और उसको पूछ कर फिर काश्तकार को कहते हैं कि तुम ऐसा करो,

वैसा करो। ऐसी हालत में काश्तकार कहता है कि हमारे अफसर हम से ही पूछ कर हम को बताते हैं—ऐसा उस के मन में विचार उठता है।

महाराष्ट्र में दालों के बारे में काफ़ी महंगाई है। वहां पर जो दालें पैदा होती हैं, वे दूसरे प्रान्तों में जाती हैं, और वहां लोगों को नहीं मिलती हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस रीति से कन्ट्रोल कीजिये कि हर प्रान्त में एक समानता आ जाये।

महाराष्ट्र के बड़े बड़े शहरों में राशनिंग है। बम्बई, पूना, नागपुर, शोलापुर में है—वहां पर राशन देने का काम सैन्ट्रल गवर्नमेंट का है। मैं 15 दिन पहले वहां के मिनिस्टर साहब से मिला था तो उन्होंने कहा कि राशन वक्त पर नहीं मिलता है और सफिशियेन्ट नहीं मिलता है। यह व्यवस्था शहरों में होने से महाराष्ट्र गवर्नमेंट को शहरों पर अनाज देने का जोर देना पड़ता है और देहात को कम मिलता है। क्योंकि शहरों में पढ़े लिखे लोग होते हैं, अगर कमी पड़ती है तो मोर्चे निकलने शुरू हो जाते हैं, गड़बड़ होने लगती है। लेकिन जहां गड़बड़ नहीं होती है, उनके लिये कोई हल नहीं ढूंढा जाता है। चीनी भी काश्तकारों और मजदूरों को 100 ग्राम, 150 ग्राम मिलती है, जबकि शहरों के दूसरे लोगों को 500 ग्राम, 700 ग्राम मिलती है, यह विषमता निकलनी चाहिये। कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे समाजवाद कहने वाली कांग्रेस हो, या कम्यूनिस्ट जो कहते हैं कि कम्यूनिज्म आना चाहिये, या पी० एस० पी० या एस० एस० पी० वाले जो कहते हैं, यह नहीं होना चाहिये।

महाराष्ट्र में चीफ मिनस्टर ने एलान किया कि दो-ढाई वर्ष में सैल्फ सफिशिएन्ट होंगे, लेकिन उस के लिये इरिगेशन की व्यवस्था होनी चाहिये, पानी देने की तजवीज होनी चाहिये। आज ऐसे कृष्णा-गोदावरी का पानी हमें नहीं मिलता है, उस के लिये यहां प्लान्ज पड़े हुए हैं। वहां मिनिस्टर कहते हैं कि प्लान्ज भेजे हुए हैं, यहां मन्जूर नहीं होते हैं, पैसा नहीं है, पानी नहीं मिलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए।

आज इलैक्ट्रिक गांव गांव में लेने की तमन्ना पैदा हुई है। गांव के लोग यदि बिजली मिल जाये तो पानी के कुओं पर बिजली की मोटर बैठाने को तैयार हैं, अपने खर्चे से लेने को तैयार हैं, लेकिन वह भी नहीं मिलती। कई जगह घर के लिये देते हैं लेकिन कुओं के लिये नहीं मिलती है। काश्तकारों को यह बिजली मिलनी चाहिये और सस्ती मिलनी चाहिये।

श्री देवराव पाटिल (यवतमाल) : प्लानिंग कमीशन तो उन पर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाना चाहता है।

श्री तुलशी दास जाधव : अभी मैंने आठ दिन हुए पढ़ा था कि प्लानिंग कमीशन ने कहा है कि खेती की इन्कम पर टैक्स लगाया जाये। मेरी समझ में नहीं आता है कि ये लोग क्या करेंगे, अगर किसी काश्तकार को जरा भी कोई फायदा होता है, तो ये उस को ले लेना चाहते हैं। आज उन के पास कपड़ा नहीं है, खाने को नहीं है, ऐसे लोगों पर टक्स बैठाइयेगा। तो इस का क्या नतीजा होगा। आज उन में इन्सेन्टिव पैदा हुआ है, तो यह बड़े दुख की बात है कि सरकार उन पर टैक्स लगा देना चाहती है। मैंने गाडगिल साहब की स्पीच को पढ़ा है·····

श्री देवराव पाटिल : लेकिन अपने मिनिस्टर साहब ने विरोध किया है जगजीवन राम जी ने विरोध किया है।

श्री तुलशी दास जाधव : जगजीवन राम बाबू तो काश्तकार से भी निचले समाज के श्रमजीवी हैं, उनको तो विरोध करना ही चाहिए।

[श्री तुलशीदास जाधव]

दुनिया के दूसरे देशों के साथ भारत का मुकाबला किया जाए तो आपको पता चलेगा कि हिन्दुस्तान में एक एकड़ भूमि पर बोझा ज्यादा है। इस बोझे को कम करना होगा। यह ठीक है कि अमरीका टैक्नौलौजी के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ा हुआ है। लेकिन फिर भी वहां पर छः परसेंट लोग ही खेती पर निर्भर करते हैं। हमने एक अमेरिकन अंबेसी में सिनेमा देखा था जिससे पता चला कि अमरीकी लोगों ने उन्नत औजार काम में लाये हैं और मशीनों की सहायता से बहुत ज्यादा काम होता है, आदमी के हाथ से बहुत कम काम होता है। लेकिन हिन्दुस्तान की आबादी ज्यादा है और यहां काम करने वाले हाथ भी ज्यादा हैं। यहां पर ज्यादा लोग काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर भी आप देखें कि सौ एकड़ पर बाकी देशों में कितने आदमी काम करते हैं। पोलैंड में 31 हैं, चैकोस्लोवाकिया में 24 हैं, हंगरी में 24 हैं। रूमानिया में 30 हैं। यूगोस्लाविया में 42 हैं। बलगेरिया में 33 हैं। ग्रीस में 48 हैं और हिन्दुस्तान में 148 हैं। इसको कम करना होगा।

भारत में लोगों को कितना न्यूट्रिशन मिलता है इसको भी आपको देखना चाहिये। यहां पर मृत्यु संख्या अधिक है, इसको भी आपको देखना चाहिए। न्यूट्रिशन न मिलने की वजह से ही यह मृत्यु संख्या अधिक होती है। अगर देखा जाए तो एक आदमी को 183 पाउंड दूध मिलना चाहिये। उसकी एफिशेंसी को बनाए रखने के लिए और मृत्यु संख्या को कम करने के लिए। लेकिन दूसरे देशों के मुकाबले में भारत के लोगों को कितना दूध मिलता है इसको आप देखें। पोलैंड में 266 पाउंड मिलता है, हंगरी में 240 पाउंड मिलता है, चैकोस्लोवाकिया म 299 पाउंड मिलता है, रूमानिया में 140 पाउंड मिलता है, यूगोस्लाविया में 160 पाउंड मिलता है, बल्गारिया में 150 पाउंड मिलता है, ग्रीस में 155 पाउंड और डेनमार्क में 406 पाउंड। आप देखें कि भारत में बिहार में 69 पाउंड मिलता है और उड़ीसा में भी 69 पाउंड मिलता है। मध्य प्रदेश में 18 ही पाउंड मिलता है। बम्बई में 91 पाउंड मिलता है, मद्रास में 37 पाउंड, बंगाल में 44, असम में 50, उत्तर प्रदेश में 144 और पंजाब और हरियाना में कुछ ज्यादा दूध मिलता है, वहां 206 पाऊंड मिलता है। न्यूट्रिशन कम होने से ही आदमी की जिन्दगी कम होती है, उस में ताकत कम होती है और इसी वजह से मृत्यु दर भी बढ़ती है।

सभापति महोदय: वह तो आपको देख कर ही मालूम होता है।

श्री तुलशीदास जाधव: मृत्यु दर जब अधिक है तो इसका मतलब यही है कि देहातों में लोग ज्यादा मरते हैं। वही लोग हैं जो कि पैदा करके शहर वालों को खिलाते हैं। उन में और ज्यादा ताकत होगी तो ज्यादा पैदा करेंगे। मृत्यु दर प्रति हजार में पोलैंड में 141 है, रूमानिया में 175 है, यूगोस्लाविया में 137 है, बलगेरिया में 144 है। जबकि हिन्दुस्तान में 1919 में वह 175 थी, 1930 में 178 थी और 1940 में 160 थी। मृत्यु संख्या भी ज्यादा है। मृत्यु संख्या जो बढ़ती है यह शहरों की नहीं देहातों की बढ़ती है जो काश्तकार है, जो अनाज पैदा करने वाला है, वह मरे भी और कुछ मिले भी न उसको तो कैसे आप आशा कर सकते हैं कि वह अधिक पैदा करके आपको दे।

प्रत्येक व्यक्ति को 2300 कैलोरीज चाहियें जबकि 1800 और 1900 ही मिलती हैं। ये आंकड़े मिनिस्टर साहब के पास खुद होंगे। उनके पास तो बड़े बड़े आफिसर हैं, सैक्रेटरी वगैरह हैं वे दे देते हैं। उनको इन आंकड़ों का पता भी है। लेकिन फिर भी कुछ मैं भी बतलाना चाहता हूं....

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम): कैलोरीज तोल कर खाते जो नहीं है, आंकड़े ही जानते हैं ।

श्री तुलशीदास जाधव : जगजीवन राम जी बिहार से आते हैं और शिदे साहब हमारे प्रान्त से आते हैं । दोनों ही काश्तकार हैं । दोनों काश्तकारों की कठिनाइयों को समझते हैं । मैं चाहता हूं कि काश्तकारों को बिजली, पानी, बीज, खाद आदि समय पर देनें का वे प्रबन्ध करें ताकि उत्पादन कर सके ।

मैं एक बात कह कर समाप्त करता हूं । मैं जगजीवन राम जी के प्रान्त बिहार में गया था । आठ दिन मैं वहां रहा हूं । गंडक और कोसी को मैंने देखा है । कोसी से पानी मिलना शुरू हो गया है । इसका परिणाम यह हुआ है कि जहां कुछ भी पैदा नहीं होता था वहां अब गेहूं और चावल पैदा होने लग गया है । हरे-हरे पौधे वहां देखनें को मिले हैं । यह हो सकता है कि लोग कहें कि जगजीवन राम जी ने अपनें प्रान्त में पैसा खर्च किया है । लेकिन उनको इसकी परवाह नहीं करनी चाहिये । अगर उनके प्रान्त का इससे भला हुआ है तो होने दें । लेकिन मैं कहूंगा कि गंडक और कोसी के लिए थोड़े पैसे की जरूरत है । अगर उन्होंने इस पैसे का प्रबन्ध कर दिया तो मैं कह सकता हूं कि बिहार ही नहीं आधे हिन्दुस्तान को अनाज देने की क्षमता वहां पैदा की जा सकती है । मैं उन से कहना चाहता हूं कि चाहे हमारे प्रान्त में से पैसा काट लें लेकिन कोसी और गंडक के लिये पैसे की जरूरत को पूरा कर दें ।

श्री मुन्निका सिंह (औरंगाबाद) : बहुत दुख की बात है कि बीस वर्ष आजाद हुए हो जाने के बाद भी अभी तक हम अन्न के मामले में आत्म निर्भर नहीं हो पाए हैं । हमेशा ही सरकार की तरफ से इस तरह का एलान किया जाता है कि अमुक साल तक हम अन्न के मामले में आत्म निर्भर हो जायेंगे । किन्तु दुख है कि सरकार की कोई सुनियोजित योजना खेती के सम्बन्ध में न होने के कारण हम बहुत पीछे रह रहे हैं और राष्ट्र की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचा कर हम विदेशों में जाकर गल्ले की भीख मांगते फिरते हैं और हमें कहना पड़ता है कि अभी भी खाद्यान्नों के मामले में जो देश की स्थिति है वह बहुत ही भयावह है, यहां पर भुख मरी है ।

यों तो इस वर्ष कुछ वर्षा की कृपा रही है । सरकार की ओर से ढोल पीटा जा रहा है कि इस वर्ष बम्पर क्राप है और ९५ मिलियन टन हम पैदा कर लेंगे । लेकिन आज से साल भर पहले या दो साल पहले इस देश की क्या हालत थी ? आपको उसको ध्यान में रखना चाहिए । बीस वर्ष के बाद भी मारी खेती सिर्फ आसमान वर्षा पर निर्भर रहे और वह गैम्बल आफ़ रेन रहे और इस विज्ञान के युग में भी हम आसमान की ओर टकटकी लगा कर बैठे रहें कि कब वर्षा हो और कब हमारी खेती अच्छी हो यह बहुत ही निराशाजनक स्थिति है । हम बड़े खुश हैं कि इस वर्ष बम्पर क्राप होगी । इस को ले कर भले ही कितनी ही खुशी मनाई जाए लेकिन किसी भी सरकार के लिए यह शर्म और दुख की बात होनी चाहिए कि हम अनाज के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं और हमें दूसरों के सामने झोली पसार कर अनाज की भीख मांगनी पड़ती है ।

आप यह भी देखें कि हमारी आबादी किस अनुपात में बढ़ रही है । 1975 तक हम को करीब 138 मिलियन टन अन्न चाहिये । सवाल यह है कि हम आज की आवश्यकताओं को और हमारी जो आवश्यकताएं आगे बढ़नें वाली हैं, उनको कैसे पूरा करें । उत्पादन बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम सिंचाई के साधन उपलब्ध करनें होंगे । जहां कहीं पहले से ही सिंचाई का समुचित प्रबन्ध है, जहां पर नहरें हैं और बारहों महीनें पानी की व्यवस्था है वहां हमें पर्याप्त मात्रा में खाद और उन्नत बीज पहुंचानें की व्यवस्था करनी होगी । जिन इलाकों में अभी तक सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं है, प्रबन्ध नहीं है वहां आपको

[श्री मुद्रिका सिंह]

नदियों को बांध कर नदी के पानी को खेतों तक पहुंचाना होगा या जहां नदी से भी पानी नहीं पहुंच सकता है वहां धरती के गर्भ को चीर कर उसके नीचे जो विशाल पानी का भंडार है उसे ऊपर लाना होगा और उसे सिंचाई के लिए देना होगा। डीजल पंप या बिजली पंप के जरिये आप इस काम को कर सकते हैं। लेकिन दुख है कि सरकार के पास आज भी ऐसी कोई सुनियोजित योजना नहीं है। जहां सिंचाई का समुचित प्रबन्ध है वहां खाद, बीज और किसान की क्रय शक्ति की व्यवस्था वह करें और जहां सिंचाई का समुचित प्रबन्ध नहीं है वहां विज्ञान की मदद से, इस वैज्ञानिक युग में, धरती के गर्भ से ट्यूब वैल के जरिये पानी निकाल कर सिंचाई का प्रबन्ध वह करे और नदियों का जो पानी बेकार जाता है उसे बांध कर सिंचाई के काम में उसका अधिक से अधिक उपयोग वह करे।

इसके साथ-साथ किसान को इन्सैंटिव आपको देना होगा। लेकिन इन्सैंटिव देने की बात तो दूर किसान से हम कृषि-कर वसूल करने की बात सोच रहे हैं। आज अगर बम्पर क्राप हुई है, अगर आप कहते हैं कि 95 मिलियन टन पैदा होने का अनुमान है तो मैं खाद्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या यह अन्न आपको आज की आबादी के लिए पर्याप्त है और क्या आपको अमरीका या आस्ट्रेलिया के पास अनाज की भीख मांगने के लिए झोली फैला कर नहीं जाना पड़ेगा। जिस किसान से आप कृषि-कर लेने की बात सोच रहे हैं वह दो वर्षों से सूखे का शिकार रहा है। ये वे किसान हैं जिन्होंने अपने गहने बंधक रखे हुए हैं। ये वे किसान हैं जिनके मवेशी अकाल की स्थिति के कारण मर गए हैं, अन्न चारे के अभाव के कारण मर गए हैं। अगर आज थोड़ा अधिक पैदा हुआ है तो वह अपनी इस अतिरिक्त आमदनी से अपने गहने जोकि बंधक रखे हुए हैं छुड़ायेगा, जो बैल उसके मर गए हैं नए बैल खरीद कर खेती की व्यवस्था करेगा। एक-एक अंचल में गवर्नमेंट की ओर से बीस-बीस लाख रुपये का कर्जा दिया हुआ है। गवर्नमेंट लैंड रैंट रिकवरी एक्ट के दायरे में उस की वसूली को तेज करने जा रही है। वह कानून इतना व्यापक है कि सुहाग चिह्न के गहनों को छोड़कर सब गहनों को शरीर से उतारा जा सकता है। किसान उस कर्ज को देगा, या कृषि-कर देगा ?

मैं समझता हूं कि किसानों पर इस तरह के कृषि-कर का बोझ लादने की बात शायद वही कर सकते हैं, जिन्हें इस देश के किसानों की आर्थिक स्थिति का कतई ज्ञान नहीं है। वे किताबों के पोथे पढ़े होंगे, उनको अर्थ-शास्त्र का भी ज्ञान होगा, लेकिन वे आसमान पर छलांग भरते रहते हैं, वे धरती पर नहीं उतरते हैं। बिहार के किसी भी गांव में चले जाइये, जो दो बरस से अकाल की चपेट में रहा है, और वहां के किसान की दयनीय दशा को देखिये। दो बरसों से बारिश न होने के कारण आज किसानों का आर्थिक मेरुदंड टूट गया है। इस वर्ष हथिया की बारिश न होने की वजह से अधिकांश धान मर गया है। जमीन की नमी खत्म हो गई है, जिससे 75 परसेंट जमीन पर रबी की बुवाई नहीं हो पाई है। ऐसा मालूम होता है कि किसानों से कर लेने की बात करने वाले लोग दया के पात्र हैं, नाराजगी के नहीं। उनकी नासमझी पर हमें तरस आता है। उनकी विद्वता के लिए भी यह एक चैलेंज है।

कृषि और कृषिकों के सम्बन्ध में सरकार की जो नीति रही है, उसका एक उदाहरण मैं देता हूं। कृषि मंत्री यहां मौजूद हैं। वह किसानों को ज्यादा पैदा करने की प्रेरणा देना चाहते हैं। लेकिन जब सरकार की ओर से करोड़पतियों को फैक्टरियां चलाने के लिए बिजली दी जाती है, तो उसकी दर पांच या छः पैसे प्रति यूनिट रखी जाती

है और यदि किसान अपने खेत में पम्प लगा कर सिंचाई करना चाहता है, तो उस से इक्कीस, बाइस पैसे प्रति यूनिट चार्ज किये जाते हैं। एक तरफ़ तो नहरों के रेट में वृद्धि और दूसरी तरफ़ इनकम टैक्स का स्वप्न, यह तो अजीब पागलपन की बात मालूम होती है।

मैं सरकार को एक्यूज करता हूं कि उसने किसान को ज्यादा-से-ज्यादा पैदा करने की प्रेरणा देने के बदले उसका पैर खींचा है। कृषि मंत्री के समक्ष मेरा सुझाव है कि इस देश में एक कारपोरेशन बनाया जाये, जो गांवों में किसान से फसल के टाइम पर गल्ला खरीदे एक निश्चित मूल्य पर और वह मूल्य ऐसा हो, जो किसान के उत्पादन-खर्च, भूमि में लगी पूंजी, हल और बैल के मूल्य और मेहनत के खर्च को मद्दे-नज़र रख कर तय किया जाये। इस के बदले में किसान को उस की जरूरत की तमाम चीजें, जैसे खाद, बीज, पम्प, ट्रेक्टर, पेस्टीसाइड और कर्ज आदि, समय पर दी जायें। इस तरह सरकार का कर्ज भी नहीं डूबेगा, हमारा काम भी हो जायेगा और हम बीच के एक्सप्लायटर, कर्ज देने वाले बनिये, से छूट जायेंगे। सरकार की नीति यह होनी चाहिए कि किसान को पर्याप्त इन्सैन्टिव दिये जायें, ताकि उनमें अधिक पैदावार करने की अर्ज पैदा हो।

श्री शिव कुमार शास्त्री (अलीगढ़) : सभापति महोदय, जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, तभी से खाद्य समस्या भी अनिमंत्रित अतिथि के रूप में हमारे यहां धरना दे कर बैठ गई है। अभी तक इस समस्या का समाधान करने के लिए जो भी प्रयत्न किये गये हैं, उनमें सरकार को सफलता प्राप्त नहीं हुई है। कई खाद्य मंत्री हमारे सामने आए, जिनकी ओर से अनेक बार इस आशय की घोषणायें की गईं कि हम फ़लां वर्ष तक अथवा इतने दिनों में अन्न के सम्बन्ध में आत्म-निर्भर हो जायेंगे, किन्तु द्रोपदी के चीर की तरह वह समय बढ़ता ही जा रहा है और उसका कोई अन्त नहीं दिखाई दे रहा है।

मेरी दृष्टि से इस समस्या के समाधान के लिये जो प्रयत्न मूल रूप में होने चाहिए थे, वे नहीं किये गये। जो कुछ किया गया, वह भारत की परिस्थिति के अनुकूल नहीं था। एक तो यह कहा गया—और इस सम्बन्ध में प्रयत्न भी किये गये—कि हमारे देश में जो अन्न उत्पन्न होता है, उससे हमारे पेट का गड्ढा नहीं भरा जा सकता है, इसलिए हमें अपने खाने-पीने की आदतों में परिवर्तन करना चाहिए और उसके लिए खुले रूप से मांस खाने का प्रचार किया गया। कहा गया कि लोग मछली और मुर्गी खाने की आदत डालें। लेकिन इससे भी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। हमें विचार करना चाहिए कि मांस अन्न का स्थान नहीं ले सकता है; वह सब्जी का स्थान तो ले सकता है। यदि इस तर्क में कुछ शक्ति थी, तो सरकार को यह परीक्षण करना चाहिए था कि जो लोग मांसाहारी हैं, या मांस के आदी हैं, उनके अन्न या चावल की कमी कर दी जाती, या कुछ दिनों के लिए उनका अन्न बन्द कर दिया जाता और यह देखा जाता कि वे मछली या दूसरे मांस पर कहां तक रह सकते हैं।

उसी प्रकार से भारत जैसे सघन जनसंख्या वाले देश में ट्रैक्टरों की आवश्यकता नहीं है और उनका प्रयोग भी हमारे अनुकूल नहीं है, लेकिन सरकार की ओर से ट्रैक्टरों के प्रयोग पर जोर दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे एक सम्बन्धी के यहां ट्रैक्टर है। गत वर्ष उन्होंने मुझे लिखा, "हमारे ट्रैक्टर का एक पुर्जा खराब हो गया है, उसको अलीगढ़ में तलाश किया, मथुरा में ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला। हमने कश्मीरी गेट की फ़लां ट्रैक्टर कम्पनी

[श्री शिव कुमार शास्त्री]

से ट्रैक्टर लिया था। हमने उनको पत्र लिखा है। आप कृपा कर के टेलीफ़ोन से उन को कहिये कि वहां का कोई मिस्त्री आकर उस पुर्जे को लगा जाये। आने-जाने का व्यय और पुर्जे की कीमत हम देंगे।" मैंने उस कम्पनी को टेलिफोन किया और इस बारे में पूछा। उन्होंने कहा, "हमारे पास तीन मिस्त्री हैं, लेकिन वे सब बाहर गए हुये हैं। जब कोई आयेगा तो भेज देंगे।" खेती का काम करने वाले और देहात के लोग जानते हैं कि खेती में पगड़ी बांधने का भी अन्तर हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति एक पुर्जे के लिए अलीगढ़ और मथुरा में दो तीन दिन खराब करे, फिर दिल्ली पत्र भेजे और फिर यहां का मिस्त्री वहां जाए और दस पन्द्रह दिन इस तरह से निकल जायें, तो वह व्यक्ति खेती नहीं कर सकेगा।

इसलिए इस समस्या का समाधान करने के लिए सब से पहले गौ की रक्षा होनी चाहिए थी। गौ की रक्षा करने के दो लाभ होते। एक तो दूध के बढ़ने से अन्न की समस्या हल होती। हम सब का अनुभव है कि जिनको दूध, दही, मक्खन, मलाई खाने को मिलती है, वे अन्न कम खाते हैं, दो तीन फुलकों से उनका गुजारा हो जाता है। लेकिन जहां सूखा शंख बजता है, वहां बीस, पच्चीस, तीस रोटियों से भी कुछ नहीं हो पाता है।

गौ की रक्षा और उसकी नस्ल में सुधार से जहां अन्न की समस्या का समाधान होता, वहां खेत में चलने के लिए अच्छे बैल भी मिलते। अगर हल का कोई पुर्जा खराब होता है, तो गांव का मिस्त्री आकर उसको ठीक कर देता है। स्वयं किसान भी इतनी योग्यता रखता है कि वह ठोक-पीट कर उसको ठीक कर लेता है। खेत में जो चारा उत्पन्न होता है, वह बैल के काम आता है। अगर खेत में चलते हुए बैल पेशाब कर देता है, तो वह अन्न की वृद्धि करेगा, अगर वह गोबर करता है तो अन्न की वृद्धि करेगा। लेकिन अगर ट्रैक्टर खेत में चलते हुये "पेशाब" कर दे, तो जहां डीजल गिरेगा, वहां अन्न का दाना भी नहीं पैदा होगा।

भारत जैसे कृषि-प्रधान देश में, जहां पर सघन आबादी है, और एक-एक किसान के हिस्से में तीस-पचास बीघे के टुकड़े आते हैं, वहां पर ट्रेक्टर क्या उपयोगी होगा? उसके लिए बहुत बड़ी जमीन चाहिए। वैसे मैं ट्रेक्टर का विरोधी नहीं हूं। जो बड़े-बड़े जमींदार उसका उपयोग कर सकते हो, वे करें। लेकिन मुख्य रूप से समस्या का समाधान तब होगा, जब गोधन की रक्षा होगी, क्योंकि उससे अन्न के उत्पादन में वृद्धि होगी, दूध और घी खानें को मिलेगा और खेती के लिए उपयोगी बैल मिलेंगे। इसके साथ-साथ जो और बातें हैं उनमें मुख्य रुकावट भ्रष्टाचार की है। यों तो सभी मुहकमों में यह है कि पर मुझे इस व्यंग्य के लिए क्षमा किया जाय, आपके तो विभाग का नाम ही खाने-पीने का विभाग है। इस लिए उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक यह भ्रष्टाचार व्याप्त है। मैं पिछले दिनों अपने निर्वाचन क्षेत्र में घूमने के लिए गया तो मुझे एक जमींदार ने 50 थैले खाद के दिखाये और कहा कि इसमें हर एक थैले में दस दस किलो कम खाद आई है। हमने तोल करके देखे हैं, और आप चाहें तो आप के सामने भी तोल सकते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक स्थान में जहां पर और चीजें रुकावट डालती हैं. . .

एक माननीय सदस्य : कहां से खरीदी गई थीं ?

श्री शिवकुमार शास्त्री : अलीगढ़ से। को-आपरेटिव से खरीदी गई थीं।

उसी तरह से मैं यह कहना चाहता हूं कि वैसे खाद्य मंत्री जी ने स्वयं यह स्वीकार किया था तीन चार दिन हुये कि हमारी तो खेती कागजों पर ज्यादा होती है और इसी लिए होता यह है कि जो आंकड़े दिए जाते हैं वह

वास्तविकता से दूर होते हैं। उदाहरण के लिए मैं बताता हूं। सन् 1951 में भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी और यहां पर अन्न का उत्पादन 5 करोड़ 83 लाख टन हुआ और सन् 1961 में आकर जनसंख्या ४४ करोड़ हो गई और उत्पादन जो सन् 64 में हुआ वह 8 करोड़ 89 लाख 50 हजार टन के बराबर बताया गया। अब इस दृष्टि से अगर आप देखें तो उत्पादन लगभग दुगुना हो गया। तो उससे समस्या का समाधान होना चाहिए था। लेकिन स्थिति यह है कि भुखमरी उसी तरह से बढ़ती जा रही है। केवल अं ों में आप का अन्न का उत्पादन बढ़ जाय उस से तो लोगों को तृप्ति नहीं होगी—

घर से खत आया है कि कल हो गया तीजा उनका ।
पायोनियर कहता है कि बीमार का हाल अच्छा है ।।

बीमार का हाल तो तब अच्छा होगा कि जब बीमार खुद कह दे कि हम ठीक हो रहे हैं। इसलिए मैं अधिक न कहकर यही कहना चाहता हूं मुख्य रूप से भारत की इस समस्या का समाधान करना है तो गउओं की रक्षा करनी चाहिए। उससे दूध, घी जहां पर उत्पन्न होगा वहीं उससे अच्छे बैल भी उत्पन्न होंगे और उससे भारत आत्म-निर्भर हो सकेगा।

श्री राम सिंह अयरवाल (सागर) : सभापति महोदय, भारतवर्ष एक कृषि-प्रधान देश है। हमारे करीबन 50 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। उसमें से करीब 70 प्रतिशत जमीन भारत की 5 प्रतिशत आदमियों के पास है। मेरे कहने का मतलब यहां पर जो किसान हैं भारतवर्ष के अन्दर वह बड़े-बड़े किसान हैं। और उन के नीचे काम करने वाले बहुत सारे मजदूर हैं। जिस जमीन पर खेतिहर मजदूर हल जोतते हैं यदि वह जमीन उनको दे दी जाती है तो मैं सोचता हूं कि वह बड़ी लगन से, बड़े चाव से खेती करेंगे और ज्यादा उत्पादन करेंगे। जैसा कि आजादी के बाद देखा गया मालगुजारी प्रथा को खत्म किया गया। उससे क्या हुआ। दो मालगुजार जमींदार थे उन्होंने अपने भाई भतीजों लड़कों बहुओं के नाम पर अपनी जमीन करवा दी। इससे क्या हुआ कि जो जमीन भूमिहीनों में बट जानी चाहिए थी वह न बट कर के उनके परिवार में ही सारी जमीन चली गई। इस प्रकार से जो एक बटवारा जमीन का किया गया वह नाजायज रूप से हुआ। इसके लिए मैं शासन से अनुरोध करता हूं कि इसकी सही तरीके से छानबीन होनी चाहिए और जो जायज किसान हैं जो हल जोतने वाले किसान हैं उनको वह जमीन मिलनी चाहिए।

हमारे मध्य प्रदेश में जो खेतिहर मजदूर बटाई पर जमीन लेते हैं उनको तीन वर्ष बाद जो जमीन वह लिए हुए होते हैं वह बदल देते हैं और इस प्रकार से उनका उस जमीन पर अधिकार नहीं होने पाता है। मेरा तो यह कहना है कि जो जमीन जोतता है उसी का हक उस पर हो जाना चाहिए। यदि इस प्रकार से होता है तो वास्तव में बहुत कुछ प्राप्ति हो सकती है।

आजादी के बाद देखा गया कि औद्योगिक क्रान्ति भारत में लाने की कोशिश की गई। संसार के दूसरे देशों में ज्यों ही आबादी आई त्यों ही वहां पर ऐग्रिकल्चरल रिवोल्यूशन आया। किन्तु भारत वर्ष ऐसा अभागा देश है कि जहां पर कृषि क्रान्ति न आ करके औद्योगिक क्रान्ति आई। इसके परिणामस्वरूप दिल्ली सरीखे विशाल शहरों में बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हुईं, वहां अमीरी आई। जो पैसा मद्रास, कलकत्ता, बंबई आदि बड़े बड़े शहरों की सड़कों और बिल्डिंगों को बनाने और उनको मेन्टेन करने पर खर्च किया गया यदि वह देहात में खर्च किया जाता तो भारत का ज्यादा कल्याण उससे होता। आज जो दिल्ली के अन्दर चम-

[श्री रामसिंह अग्रवाल]

चमाती हुई बिजली दिखाई पड़ती है वह बिजली अगर गांवों को दी जाती और खेती में उस का उपयोग होता तो मैं समझता हूं कि उसका अधिक लाभ देश को मिलता । जो हमारे देश का पैसा आज बरबाद जा रहा है, जनता का पैसा बरबाद जा रहा है इस प्रकार से, वह बड़ा भारी अत्याचार देश पर किया जा रहा है। इसलिए मेरा यह कहना है कि इस प्रकार की जो खेती की जमीन की समस्या है उसका हल किया जाय ।

16.57 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER In the Chair]

दूसरी ओर हमारे भारतवर्ष में बेकारी की समस्या फैल रही है । उसका परिणाम यहां की आमदनी पर पड़ रहा है । इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हमारे जो एम्प्लायमेंट एक्सचेंज हैं उनको ऐसा आदेश दिया जाय कि जो मैट्रीकुलेट हैं और वह खेती करना चाहते हैं तो उनको उस के लिए जमीन दी जायगी और उनके लिए और सारी सुविधायें दी जायेंगी । इस प्रकार का प्राविजन और किया जाता है तो मैं समझता हूं कि उससे बहुत कुछ बेकारी की समस्या हल हो सकती है ।

जहां तक खाद्य पदार्थों के मूल्य निर्धारण की बात है जैसा कि शारदानन्द जी ने कहा था गन्ना उत्पादन जो किया जाता है उसका किसान को उचित मूल्य नहीं मिलता जबकि मिल मालिकों को ज्यादा मूल्य मिलता है । तो मेरा यह कहना है कि जो मिल मालिक का खर्च है, मान लीजिये 5 रुपये का एक किलो सुगर बिकता है और डेढ़ रुपये उसके बनाने पर खर्च आता है तो साढ़े तीन रुपया जो बचता है सीधा यह किसान के पास जाना चाहिए । अगर मान लीजिए जो बीच के आदमी रहते हैं उनके लिए आठ आने मान लीजिये तो भी कम से कम 3 रुपये सीधे किसान के पास पहुंचने चाहियें । इस प्रकार से मूल्य का निर्धारण होना चाहिये जिससे कि सही तरीके से हमारे किसान को उस की उपज का फायदा मिल सके ।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि भूमिहीन हरिजन आदिवासियों के साथ ऐसा हो रहा है कि जिन हरिजन आदिवासियों को जमीन दी गई है वह कहने मात्र को दी गई है और जिनकी वह जमीनें हैं चाहे वह मालगुजार हों चाहे जमीदार हो उनका गांव में दब दबा रहता है । इस कारण से वह जमीन जोत नहीं पाते हैं, उन के खेत छीन लिए जाते हैं, उन के पशुओं को मारा पीटा जाता है । उनके पशुओं को कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है । इस प्रकार से जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए सुरक्षा होनी चाहिए । मेरा कहना यह है कि जो सहकारी खेती होती है, वह वास्तव में सफल खेती नहीं है । इस की जगह यदि कलैक्टिव फार्मिंग की जाय, तो ज्यादा सुन्दर है ।

17 hrs.

एक माननीय सदस्य : मैं जानना चाहता हूं कि यह बहस कल चलेगी या नहीं ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : The Speaker has announced that tomorrow the Minister has to reply. Beyond that I cannot give any information.

एक माननीय सदस्य : यहां पर तमाशा यह चलता है कि जो भलमनसाहत से काम करता है, उसकी सुनवाई नहीं होती है जो उदण्डता बरतते हैं, उनको मौका दिया जाता है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The hon. Member may get in touch with the Minister of Parliamentary Affairs for further information.

DISCUSSION RE LAW AND ORDER SITUATION IN DELHI

MR. DEPUTY-SPEAKER : The House will now take up discussion under Rule 193. Under the rule I have to conclude the discussion in one hour.